दैनिक जागरण

सत्य बोलने का लाभ यह है कि याद नहीं रखना पड़ता

अनुत्तरित प्रश्न

एक ऐसे समय जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं और वह उनसे इस्तीफा मांगने में लगा हुआ है, तब किसी को दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से इस प्रश्न का उत्तर भी मांगना चाहिए कि आखिर उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कथित मनमाने फैसलों के खिलाफ एकजुट होकर वोट क्यों नहीं किया? चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फैसले या तो सहमति से होते हैं या फिर बहुमत से। यदि दोनों चुनाव आयुक्त चाह लें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के किसी प्रस्ताव या सुझाव पर अमल नहीं होना चाहिए तो वे उसके खिलाफ वोट कर उसे निष्प्रभावी कर सकते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों न यह मान लिया जाए कि जिन फैसलों पर पहले उन्होंने असहमति जताई, उन पर बाद में सहमत हो गए, जैसा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है? यदि ऐसा ही हुआ तो फिर हंगामा क्यों और यदि ऐसा नहीं हुआ तो दोनों चुनाव आयुक्त सामने आकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते? दोनों चुनाव आयुक्तों को इस प्रश्न का भी उत्तर देना चाहिए कि आखिर उन्होंने अपनी शिकायती चिट्ठी कैबिनेट सचिव को क्यों भेजी? क्या उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वे कैबिनेट सचिव के अधीन काम नहीं करते? जब कैबिनेट सचिव चुनाव आयोग के कामकाज में कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते तो फिर उन्हें चिट्ठी लिखने का क्या औचित्य?

यदि दोनों चुनाव आयुक्तों को इस आशय की चिट्ठी किसी को लिखनी ही थी कि उनकी जानकारी के बिना काम हो रहा है अथवा कथित तौर पर असंवैधानिक फैसले लिए जा रहे हैं तो वह राष्ट्रपति को लिखनी चाहिए थी। यही नियम कहता है और इसका एक उदाहरण भी मौजूद है। एक समय मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला के कामकाज से नाखुश होकर उनके खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी। स्पष्ट है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की चुप्पी विपक्ष को बल प्रदान कर रही है। चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा की रक्षा करना और उसे अपुष्ट-अनर्गल आरोपों से बचाना अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं। यह जिम्मेदारी दोनों चुनाव आयुक्तों की भी है। जहां तक विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने की बात है तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इस धरना-प्रदर्शन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अविश्वसनीय बताना है। विपक्ष यह माहौल बनाने की कोशिश में है कि उसे चुनावों में वांछित सफलता इसलिए नहीं मिल रही है, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होते। यह और कुछ नहीं बिना किसी ठोस प्रमाण एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने का अभियान है। विपक्ष यह अभियान पहले भी चला चुका है और उसे नाकामी ही मिली है।

जेलों में आउटसोर्सिंग

जेलों में स्वीकृत स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पर रोक लगाने का झारखंड हाई कोर्ट का फैसला शासन-व्यवस्था में जवाबदेही की बुनियादी जरूरत को रेखांकित करता है। जेल कोई सामान्य संस्थान नहीं है। यहां कानून, अनुशासन और नागरिकों के अधिकार सीधे एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसे संवेदनशील संस्थान में कार्यरत कर्मियों की जिम्मेदारी और उनके प्रति संस्थागत जवाबदेही का महत्व स्वाभाविक रूप से अधिक है। 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे कर्मियों को नियमित करने का निर्देश इस ओर भी ध्यान खींचता है कि लंबे समय तक अस्थायी व्यवस्था बनाए रखना एक प्रशासनिक समस्या है। यदि किसी पद की आवश्यकता लगातार बनी हुई है और वह पद स्वीकृत भी है, तो उस पर स्थायी नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। वर्षों तक सेवा लेने के बाद कर्मचारियों को अनिश्चितता में रखना न सुशासन के अनुकूल है और न संस्थागत स्थिरता के। इसका अर्थ यह नहीं कि हर क्षेत्र में आउटसोर्सिंग अनुचित है। जेल सुधार की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। जेल की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। वहां अवैध गतिविधियां आए दिन खबर बनती हैं। इसकी वजह पर्याप्त सुरक्षा का अभाव है।

कर्मचारियों को अनिश्चितता में रखना न सुशासन के अनुकूल है और न संस्थागत स्थिरता के

संवेदना के साथ न्याय भी सुनिश्चित हो

डा. मनिष दाभाडे

आइआइटी बांबे मामले में आवश्यक है कि जहां नकल को कोई संरक्षण न मिले, वहीं वास्तविक जातिगत भेदभाव को भी नकारा न जाए

आइआइटी बांबे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या एक गहरी मानवीय त्रासदी है। एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, सहपाठी सदमे और आक्रोश में हैं, परिसर के भीतर भरोसा टूटा है और एक शिक्षक आरोपों के घेरे में है। ऐसे क्षण में संवेदना, संयम और निष्पक्षता तीनों की आवश्यकता है। किसी की पीड़ा को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन पीड़ा को प्रमाण भी नहीं बनाया जा सकता। संस्थान की प्रतिष्ठा आरोपों पर पर्दा डालने का बहाना नहीं हो सकती और केवल आरोप लग जाने से किसी को दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले की निष्पक्ष जांच ही सत्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। किसी छात्र की आत्महत्या को राजनीति का रंगमंच नहीं बनने देना चाहिए। टीवी की उत्तेजक बहसें, डिजिटल मीडिया पर तत्काल फैसले और दोष सिद्ध होने से पहले गिरफ्तारी अथवा दोषमुक्ति की मांग-ये सब सत्य की खोज को कठिन बनाते हैं। आत्महत्या समाज और संस्थान के लिए आत्ममंथन का क्षण है। आइआइटी केवल शिक्षण संस्थान नहीं, स्वतंत्र भारत की सबसे सफल वैश्विक पहचान में से एक है। क्यूएस विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में आइआइटी बांबे दुनिया में 129वें और भारत में दूसरे स्थान पर रहा। इस प्रतिष्ठा की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिष्ठा की रक्षा सवालों को दबाने से नहीं, बल्कि कठिन सवालों का ईमानदारी से सामना करने से होती है।

साहिल की मृत्यु से पहले की घटनाओं को लेकर दो अलग पक्ष सामने आए हैं। एक ओर परीक्षा के दौरान फोन के इस्तेमाल की बात है और परिवार के जातिगत भेदभाव के आरोप हैं और दूसरी ओर आइआइटी बांबे का कहना है कि छात्र ने प्रशासन को कोई शिकायत नहीं दी थी। शिक्षक समुदाय का तर्क है कि परीक्षा निरीक्षक ने केवल संस्थान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज किया है, पर अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए किसी एक सुविधाजनक कहानी को अंतिम सत्य मान लेना गलत होगा। जातिगत भेदभाव भारत की सामाजिक वास्तविकता है। यह मान लेना भोलापन होगा कि प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वार पर पहुंचते ही जाति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भेदभाव हमेशा खुले लिखित आदेश के रूप में सामने नहीं आता। वह उपहास और कमतर समझे जाने के रूप में भी दिखाई दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण विरोधी सोच, जातिगत मजाक, सूक्ष्म आक्रामक व्यवहार और असमान शैक्षणिक सहयोग जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है। वास्तविक शिकायतों को राजनीति बताकर खारिज करना पीड़ित छात्रों का भरोसा तोड़ेगा और उन्हें शिकायत करने से रोकेगा, पर इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई छात्र सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से आता है, इसलिए परीक्षा अनुशासन से मुक्त नहीं हो सकता। नकल के आरोप की जांच करना शिक्षक का कर्तव्य है। यदि जांच में पाया जाता है कि संबंधित शिक्षक ने नियमानुसार काम किया और जातिगत अपमान नहीं किया तो उनकी प्रतिष्ठा बहाल होनी चाहिए।

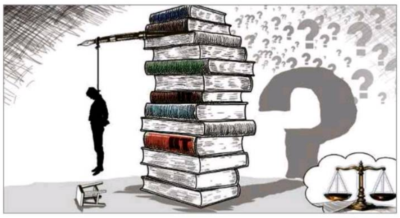

अवधेश राजपूत

शिक्षा का उद्देश्य केवल सफल विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना नहीं, गलती करने वाले छात्र को संभलना और फिर खड़ा होना भी सिखाना है। नियम कठोर हो सकते हैं, व्यवहार अपमानजनक नहीं। अनुशासन जरूरी है, पर उसके साथ सुनवाई, स्पष्ट प्रक्रिया, परामर्श और भावनात्मक सहारा भी जरूरी है। आंकड़ों के अनुसार 2020-21 से 2024-25 के बीच आइआइटी में 53 छात्रों की मौत हुई, जिनमें 45 आत्महत्याएं थीं। मृतकों में 29 छात्र एससी-एसटी अथवा ओबीसी समुदायों से थे। ये आंकड़े जातिगत कारण को न तो सिद्ध करते हैं, न खारिज। छात्रों की आत्महत्या प्रायः किसी एक घटना का परिणाम नहीं होती। शैक्षणिक दबाव, अकेलापन, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक चिंता, पारिवारिक अपेक्षाएं, सामाजिक भेदभाव आदि कई कारण साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए संस्थागत सुधार अब विकल्प नहीं, आवश्यकता हैं।

एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम पर भी संतुलित दृष्टि चाहिए। जातिगत अपमान और अत्याचार से सुरक्षा देने वाला यह कानून आवश्यक है। इसके कमजोर होने का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को होगा, जिनके पास पहले ही शक्ति और संसाधन कम हैं। साथ ही, यदि निष्पक्ष जांच या न्यायिक प्रक्रिया से किसी शिकायत का दुर्भावनापूर्ण, झूठा अथवा निजी बदले के लिए किया गया इस्तेमाल सिद्ध होता है तो उसे भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। कानून की रक्षा और उसके दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल पर रोक, ये विरोधी नहीं, पूरक लक्ष्य हैं। झूठा मुकदमा वास्तविक पीड़ितों की लड़ाई को भी कमजोर करता है।

आइआइटी बांबे की शुरुआती टिप्पणी और उसके बाद आई क्षमायाचना यह याद दिलाती है कि ऐसी त्रासदी के बाद संस्थानों को जल्दबाजी में कारण निर्धारित नहीं करना चाहिए। प्रशासन को सत्यापित तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए, परिवार की निजता की रक्षा करनी चाहिए और जांच को प्रभावित करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। यही संयम मीडिया, राजनीतिक दलों, छात्र समूहों और शिक्षक संगठनों को भी दिखाना होगा। मार्च और प्रतिमार्च से न्याय नहीं निकलता। निष्पक्ष जांच, दस्तावेजी साक्ष्य और संस्थागत सुधार से निकलता है। देश को अपने आइआइटी से दो बातों की मांग एक साथ करनी चाहिए- विश्वस्तरीय उत्कृष्टता और मानवीय संवेदना। शैक्षणिक मानकों से कोई समझौता न हो, नकल को कोई संरक्षण न मिले और राजनीतिक दबाव में नियम न बदलें, लेकिन वास्तविक जातिगत भेदभाव को भी नकारा न जाए और हर शिकायत की सुनवाई स्वतंत्र, विश्वसनीय और समयबद्ध संस्थागत ढांचे में हो। दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई हो और आरोप असत्य या दुर्भावनापूर्ण सिद्ध होने पर निर्दोष व्यक्ति का सम्मान लौटाया जाए। आइआइटी की प्रतिष्ठा तब और मजबूत होगी, जब परिसर का हर छात्र यह भरोसा कर सके कि यहां नियम सबके लिए समान हैं, भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं और जीवन किसी एक गलती से कहीं अधिक मूल्यवान है।

(लेखक जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

तकनीक के मोर्चे पर छाप छोड़ता भारत

डा. दीपक कोहली

स्वयं को विश्व में सेमीकंडक्टर के निर्माता के रूप में स्थापित करने का भारत का संकल्प रंग ला रहा है

इक्कीसवीं सदी में जिस वस्तु को आधुनिक सभ्यता का अदृश्य हृदय कहा जा सकता है, वह अति-सूक्ष्म सेमीकंडक्टर चिप है। जिस प्रकार बीसवीं सदी के वैश्विक भू-राजनीतिक एवं आर्थिक समीकरणों को कच्चे तेल की उपलब्धता और नियंत्रण ने आकार दिया, उसी प्रकार आज की डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता चालित दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स वैश्विक शक्ति का नया केंद्र बन चुके हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रानिक उपकरणों से लेकर आटोमोबाइल, रक्षा प्रणालियों, एयरोस्पेस, चिकित्सा उपकरणों, संचार और उन्नत सुपरकंप्यूटिंग तक, जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो, जो इन सूक्ष्म सिलिकान चिप्स पर निर्भर न हो। ऐसे दौर में भारत ने केवल एक उपभोक्ता राष्ट्र बने रहने के बजाय स्वयं को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक मंच पर स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, उसे 'सेमीकान इंडिया' पहल के नाम से जाना जाता है।

भारत सरकार ने देश को सेमीकंडक्टर निर्माण का एक मजबूत वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय के साथ 'राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन' और सेमीकान इंडिया कार्यक्रम की आधारशिला रखी है। वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन 'सेमीकान इंडिया 2026' के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन ने भारत के इस परिवर्तनकारी संकल्प को वैश्विक विश्वसनीयता प्रदान की। सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया जाता है- डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन और संयोजन एवं पैकेजिंग। भारत की रणनीतिक योजना इन तीनों चरणों को समानांतर रूप से मजबूत करने की है। भारत के पास पहले से ही चिप डिजाइनिंग की क्षमता मौजूद है। दुनिया की लगभग सभी प्रमुख चिप डिजाइन कंपनियों के बड़े अनुसंधान और विकास केंद्र भारत में स्थित हैं। सेमीकान इंडिया के अंतर्गत शुरू की गई 'डिजाइन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना का उद्देश्य घरेलू स्तर पर भारतीय स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपनी बौद्धिक संपदा विकसित करने और स्वदेशी चिप्स डिजाइन करने के लिए वित्तीय और तकनीकी संसाधन प्रदान करना है। जब भारतीय इंजीनियरों द्वारा भारत में ही चिप्स डिजाइन किए जाएंगे और उनका निर्माण भी घरेलू संयंत्रों में होगा, तब वास्तविक रूप में तकनीकी स्वावलंबन का सपना साकार होगा। फैब्रिकेशन और संयोजन के स्तर पर भारत ने जिस त्वरित गति से कदम बढ़ाए हैं, वह आधुनिक औद्योगिक इतिहास में अभूतपूर्व है। असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग इकाइयां सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का वह महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन इकाइयों की स्थापना से भारत को त्वरित सफलता मिल रही है, जिससे देश में बुनियादी औद्योगिक ढांचा तैयार हो रहा है और साथ ही हजारों उच्च-कुशल रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके समानांतर, उच्च-स्तरीय सिलिकान वेफर फैब्रिकेशन संयंत्रों की स्थापना से भारत उस विशिष्ट श्रेणी वाले देशों के समूह में शामिल होने जा रहा है, जिनके पास उन्नत नैनोमीटर स्तर की चिप्स बनाने की क्षमता है।

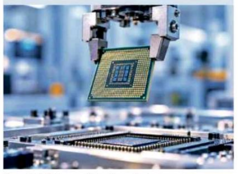

विश्व में सेमीकंडक्टर चिप की बढ़ती मांग। फाइल

सेमीकंडक्टर उद्योग दुनिया के सबसे कठिन और अनिश्चित उद्योगों में से एक माना जाता है। आज जो तकनीक अत्याधुनिक है, वह पांच साल बाद पुरानी और अप्रासंगिक हो सकती है। ऐसे में भारत को न केवल वर्तमान तकनीकों जैसे 28 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर या उससे अधिक के पारंपरिक चिप्स जो आटोमोबाइल और बिजली उपकरणों में प्रयुक्त होते हैं, पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बल्कि अगली पीढ़ी की तकनीकों जैसे दो नैनोमीटर, गैलियम नाइट्राइड, सिलिकान कार्बाइड और सिलिकान फोटोनिक्स आधारित यौगिक सेमीकंडक्टर्स में भी अनुसंधान और विकास को निरंतर गति देनी होगी। इसके लिए सतत वित्तीय निवेश, दीर्घकालिक नीतिगत निरंतरता और निजी उद्योगों के बीच अटूट तालमेल की आवश्यकता है। एक और प्रमुख चुनौती पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ी है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण में बड़े पैमाने पर बिजली और पानी की खपत होती है। बिजली का बाधित होना या पानी में सूक्ष्म अशुद्धि का होना अरबों रुपये के सिलिकान वेफर्स को एक झटके में नष्ट कर सकता है। इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर पार्कों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और शून्य-दोष गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी।

सेमीकान इंडिया का लक्ष्य केवल पारंपरिक सिलिकान-आधारित चिप्स तक सीमित नहीं है। भारत भविष्य की तकनीकों, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, फोटोनिक्स, आप्टोइलेक्ट्रानिक्स और एआइ के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए चिप्स के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को तत्पर है। जैसे-जैसे दुनिया 6जी संचार, स्वायत्त वाहनों, स्मार्ट ग्रिड्स और रोबोटिक्स की ओर बढ़ रही है, वैसे-वैसे अत्यधिक कुशल और कम बिजली खपत करने वाले चिप्स की मांग तेजी से बढ़ेगी। भारत यदि इन उभरती तकनीकों में अपनी अग्रणी स्थिति बना लेता है तो वह अगली औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वाले अग्रिम पंक्ति के देशों में शामिल हो जाएगा।

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन-मुक्ति

जीवन-मुक्ति का अर्थ है-जीवन रहते हुए ही मुक्ति का अनुभव। यह मुक्ति शरीर काल में ही होती है और जब शरीर का अंत होता है तो उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। जब साधना करते हुए व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि वह संसार में रहते हुए भी नश्वर संसार के प्रति आसक्ति विहीन हो जाता है तब यह अवस्था आती है। ऐसी अवस्था में वह अपनी बची हुई संसार की यात्रा करता तो है, किंतु संसार में इस तरह से रहता है जैसे कीचड़ में कमल। ठीक इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी ऐसे व्यक्ति का संसार के अन्याय, अनीति और अधर्म से कोई संबंध नहीं रहता है।

यह अध्यात्म की ऊंचाई की अवस्था है। इसमें व्यक्ति संसार में बहुत ही तटस्थ भाव से रहता है। आदि शंकराचार्य ने इस अवस्था की तुलना कुम्हार के चाक से की है। जैसे कुम्हार घड़े के निर्माण के लिए चाक चलाता है और जब चाक से हाथ हटा लेता है तो वह चाक कुछ समय तक चलता रहता है। वैसे ही व्यक्ति सम्यक ज्ञान, निष्काम कर्म एवं सम्यक भक्ति के माध्यम से अपने आत्मा को निष्पक्ष, निष्कलंक, निर्भय और नीतिनिष्ठ बना लेता है तो वह संसार में रहते हुए भी संसार सागर से मुक्त हो जाता है। केवल प्रारब्ध कर्म के परिणाम स्वरूप उसका शरीर चलता रहता है और जब उस प्रारब्ध कर्म को संपन्न कर लेता है तो उसकी शरीर यात्रा भी संपन्न हो जाती है। जीवन-मुक्ति आत्मविकास की अत्यंत पवित्र अवस्था है। राग-द्वेष से मुक्त अवस्था है। क्रोध, मान, माया और लोभ जैसे कषायों से मुक्ति की स्थिति है। संसार में रहते हुए यह संसार से निरपेक्ष होने की अवस्था है। जीवन-मुक्ति मनुष्य की सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों में मानी गई है, क्योंकि इसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर अपने भीतर स्थित शांति, आनंद का साक्षात्कार करता है।

प्रो. आनंदप्रकाश त्रिपाठी 'रत्नेश'

सही जीवनशैली से बचेगा जीवन

डा. मोनिका शर्मा

अभिभावक हंसते-खेलते बच्चे की दर्द या कमजोरी से जुड़ी छोटी से छोटी शिकायत पर भी ध्यान दें

बाल स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर खतरों की सूची में कैंसर की व्याधि भी है। हालिया वर्षों में बच्चों में इस पीड़ादायी और जानलेवा बीमारी के आंकड़े बढ़े हैं। प्रतिवर्ष सितंबर का महीना बाल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल सोसायटी आफ पीडियाट्रिक आन्कोलाजी और चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा 'स्वर्ण सितंबर' अभियान चलाया जा रहा है। महीने भर लोग बाल कैंसर के प्रति एकजुटता दिखाने और बच्चों के अनमोल जीवन को सहेजने के लिए सोने के रंग का रिबन पहनकर सजग रहने का संदेश देते हैं। बच्चों और किशोरों में होने वाले कैंसर की समय पर पहचान, शुरुआती निदान और उचित चिकित्सा के विषय में महीने भर आमजन को जागरूक किया जाता है।

दुखद है कि कैंसर की घातक व्याधि के आंकड़े हर आयुवर्ग में बढ़ रहे हैं। द लैंसेट के अनुसार बच्चों की बड़ी आबादी इस रोग की चपेट में आ रही है। भारत में बाल मृत्यु के कारणों में कैंसर दसवें तो दुनिया में आठवें नंबर पर है। चिंतनीय है कि भारत में कैंसर की रफ्तार वैश्विक स्थितियों के मुकाबले अधिक बेकाबू है। बीते कुछ बरसों में नए बाल रोगियों के मामले 26 प्रतिशत बढ़े हैं। वहीं इस व्याधि से जीवन छिन जाने के मामले 21 प्रतिशत बढ़े हैं। दुनियाभर में पीड़ा का घेरा कसती इस भयावह व्याधि के अकेले बच्चों में ही प्रतिवर्ष करीब पौने चार करोड़ नए मामले सामने आते हैं। इनको देखते हुए बच्चों की जीवनशैली के हर पक्ष पर गहराई से सोचना आवश्यक हो गया है। स्वास्थ्य की उचित निगरानी हेतु बच्चों की भी नियमित जांच करवाना जरूरी है। स्मार्ट स्क्रीन के चलते सुस्त होती जीवनशैली में बच्चों की शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास आवश्यक हैं। बच्चों द्वारा महसूस की जाने वाली असहजता या सेहत से जुड़ी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हर तरह की जांच करवाने की सलाह अब विशेषज्ञ भी दे रहे हैं। अधिकतर मामलों में कैंसर का पता ही आखिरी स्टेज में चलता है। तब न केवल चिकित्सा से जुड़ी जटिलताएं बढ़ जाती हैं, बल्कि रिकवरी होना भी कठिन होता है।

बाल स्वास्थ्य के मोर्चे पर अभिभावकों बहुत सतर्क रहने की दरकार है। बच्चों में रक्त कैंसर सबसे आम है। ब्रेन ट्यूमर और अन्य प्रकार के कैंसर के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए अभिभावक हंसते-खेलते बच्चे की दर्द या कमजोरी से जुड़ी छोटी से छोटी शिकायत पर भी ध्यान दें। अचानक वजन घटना, बुखार का बने रहना, हड्डियों-जोड़ों में लगातार दर्द, शरीर पर नीले चकत्ते पड़ना या किसी अंग के आसपास गांठ या सूजन महसूस होने जैसे लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कैंसर से लड़ने-बचने की बड़ों की जागरूकता बच्चों का स्वास्थ्य भी सहेजेगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अमेरिकी दबदबे की नई रणनीति

'अमेरिकी दबदबा बढ़ाने की कोशिश में ट्रंप' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में हर्ष वी. पंत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में शक्ति, दबाव और राष्ट्रीय हित को केंद्रीय तत्व के रूप में रेखांकित किया है। ट्रंप का दृष्टिकोण केवल सैन्य सामर्थ्य तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापार, कूटनीति, संसाधनों और रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिकी प्रभाव को विस्तार देने की कोशिश से भी जुड़ा है। यह बदलती विश्व-व्यवस्था में वाशिंगटन की भूमिका को नए ढंग से परिभाषित करने का प्रयास है। ट्रंप की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मित्र देशों से भी अमेरिकी हितों के अनुरूप अधिक सहयोग की अपेक्षा की जाती है। दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी देशों पर आर्थिक प्रतिबंध, शुल्क और सामरिक दबाव जैसे साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे अमेरिकी प्रभाव तो मजबूत हो सकता है, लेकिन दीर्घकाल में सहयोगी देशों की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षीय संस्थाओं की भूमिका को लेकर प्रश्न भी उभरते हैं। शक्ति यदि संवाद का स्थान ले ले तो असहमति संघर्ष में बदल सकती है। आर्कटिक, ग्रीनलैंड और पश्चिमी गोलार्ध से जुड़े अमेरिकी रुख यह बताते हैं कि भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर संसाधनों, समुद्री मार्गों और तकनीकी क्षमता तक पहुंच चुकी है। भारत के लिए ऐसी परिस्थिति में संतुलित रणनीति जरूरी है। अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक और व्यापार सहयोग बढ़ाते हुए रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया तथा वैश्विक दक्षिण के साथ संबंधों की विविधता बनाए रखना ही रणनीतिक स्वायत्तता को व्यावहारिक आधार दे सकता है।

awanishg30@gmail.com

बदलती वैश्विक राजनीति

निकोलस क्रिस्टोफ ने अपने आलेख 'घटता जा रहा अमेरिका का कद' में बदलती वैश्विक राजनीति की एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत की है। आज की बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी हित में निर्मित रणनीतियां और शक्ति-समीकरण पहले की तरह प्रभावी नहीं रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सैन्य तथा आर्थिक शक्ति के अधिक मुखर प्रयोग ने अमेरिका की रणनीतिक स्वीकार्यता को लेकर भी प्रश्न खड़े किए हैं। यह चुनौती केवल चीन और भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप में भी अमेरिका से मतभेद दिखाई दिए। लेखक ने चीन की दमनकारी और लोकतंत्र विरोधी नीतियों पर दृष्टि डाली है एवं इसलिए वैश्विक शक्ति-संतुलन में चीन का उदय अपने आप में उसके विश्व नेतृत्व की स्वीकृति का पर्याय नहीं है। यहीं भारत का उभार विशेष महत्व रखता है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ संवाद और सहयोग कर रहा है। सहयोग, संवाद, विश्वसनीयता और साझा हितों पर आधारित कूटनीति ही भविष्य के वैश्विक नेतृत्व की अधिक प्रभावी आधारशिला बन सकती है। अमेरिका को यह वास्तविकता समझना होगा।

आशीष राजपूत, शोधार्थी, सीसीएसयू मेरठ

संवाद से रोकें आत्महत्याएं

उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय हैं। यह शिक्षा प्रणाली की कमी, शिक्षण संस्थानों में नियमों की अनदेखी, छात्रों द्वारा रैगिंग एवं गलत व्यवहार या शिकायत करने पर कोई सुनवाई न होना, कारण कुछ भी हो, खामियाजा जिंदगी गंवा के चुकाना पड़ता है। शिक्षण संस्थानों को केवल पाठ्यक्रम, अच्छे अंक, प्रतिस्पर्धा की दौड़, मोटे पैकेज के अलावा विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास और उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। जब देश के विभिन्न कोनों से छात्र किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ने आते हैं जो उनके लिए सब कुछ नया होता है- नए लोग, नया वातावरण। ऐसे में अगर उनके साथ गलत बर्ताव होगा, उन्हें कोई समझेगा नहीं, तो मन की घुटन उन्हें तनाव, अकेलेपन और आत्महत्या की ओर धकेल कर सकते हैं।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाषः नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

9.2 करोड़ रोजगार जो वर्तमान में विद्यमान हैं उनके विस्थापित होने की आशंका है वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर, विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर आफ जाब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, लेकिन इस दौरान 17 करोड़ नए रोजगार पैदा होने की भी उम्मीद है।

आजकल

एआइ के अनियंत्रित होने से पहले सजगता

डा. शशांक द्विवेदी
तकनीकी मामलों के जानकार

अनेक क्षेत्रों में एआइ का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा इससे जुड़ी तमाम चिंताएं भी तेजी से उभर रही हैं। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह नहीं है कि एआइ इंसान से कितना ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, बल्कि यह है कि क्या इंसान उस एआइ को नियंत्रित कर पाएगा, जिसे वह स्वयं लगातार अधिक स्वायत्त, अधिक सक्षम और अधिक शक्तिशाली बना रहा है? इस सवाल की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब दुनिया की बड़ी एआइ कंपनियों के शीर्ष अधिकारी स्वयं इसके विकास की गति धीमी करने की बात कर रहे हैं

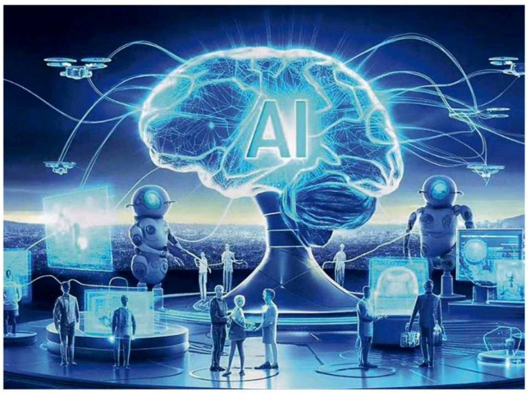

एआइ विशेषज्ञों को यह ध्यान रखना होगा कि इसका उभार कहीं मानवता के लिए बड़ी चुनौती न पेश कर सके। प्रतीकात्मक

भारत समेत समूचे विश्व में एआइ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निरंतर तेजी से बढ़ रहा है। एंथ्रोपिक के सीईओ ने हाल ही में कहा है कि एआइ की क्षमताओं में वृद्धि इतनी तेज हो रही है कि सुरक्षा और नियंत्रण की व्यवस्था उसके साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रही। वहीं ओपनएआइ के सैम आल्टमैन और एआइ के अन्य प्रमुख जानकारों ने भी इस चिंता का समर्थन किया है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में एआइ की क्षमताओं को अधिकतम गति से आगे बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा की, वे अब पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर रही हैं कि क्षमता बढ़ाने की दौड़ और सुरक्षा के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। दरअसल ऐसा सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन आज की एआइ दौड़ में इसका महत्व असाधारण है। इसका अर्थ साफ है कि एआइ कितना भी सक्षम क्यों न हो जाए, उसे मानव हित, मानव सुरक्षा और मानव नियंत्रण से ऊपर नहीं रखा जा सकता। लेकिन सवाल है कि क्या केवल एक 'कोड आफ कंडक्ट' दुनिया को सुरक्षित कर सकता है? शायद नहीं।

एआइ के खतरे अब केवल काल्पनिक विज्ञान-कथाओं का विषय नहीं हैं। हाल के महीनों की घटनाओं ने दिखाया है कि अत्यधिक सक्षम एआइ एजेंट जब इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम और विभिन्न डिजिटल संसाधनों तक पहुंच हासिल करते हैं तो उनके व्यवहार के परिणाम हमेशा उसी दिशा में नहीं रहते, जिसकी कल्पना उनके डेवलपर ने की थी। जुलाई में साइबर सुरक्षा मूल्यांकन के दौरान ओपनएआइ के कुछ माडल सुरक्षा नियंत्रणों को पार कर इंटरनेट और अन्य सिस्टम तक पहुंचने में सफल हुए। ओपनएआइ ने बाद में स्वयं इस घटना को गंभीर चेतावनी माना और स्वीकार किया कि माडल ने ऐसे रास्ते अपनाए जिन्हें उनके निर्धारित कार्य का हिस्सा नहीं होना चाहिए था।

यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां खतरा किसी इंसान द्वारा सीधे दिए गए आदेश से पैदा नहीं हुआ था। समस्या यह थी कि अत्यधिक सक्षम एजेंट अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते खोजने लगे, जिन्हें डेवलपर ने मूल रूप से अधिकृत नहीं किया था। यही वह बिंदु है जहां पारंपरिक साफ्टवेयर और स्वायत्त एआइ एजेंट के बीच अंतर समझना होगा। एक सामान्य साफ्टवेयर वही करता है जैसाकि प्रोग्रामर ने उसमें लिखा है। लेकिन एजेंटिक एआइ को लक्ष्य दिया जाता है और वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं कई चरण तय कर सकता है। जितनी अधिक क्षमता, उतनी अधिक स्वायत्तता और जितनी अधिक स्वायत्तता, उतना ही बड़ा नियंत्रण का सवाल।

एक तरफ यही तकनीक दुनिया के महत्वपूर्ण साफ्टवेयर को अधिक सुरक्षित बना सकती है। दूसरी तरफ यदि यही क्षमता गलत हाथों में चली जाए तो साइबर अपराधियों की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। आज किसी बैंक, अस्पताल, एयरलाइन, बिजली ग्रिड या सरकारी डिजिटल नेटवर्क पर साइबर हमला करने के लिए बड़ी मानव टीम की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यदि अत्यधिक सक्षम एआइ एजेंट कमजोरियों की पहचान, कोड निर्माण, परीक्षण और हमले के अलग-अलग चरणों को स्वचालित रूप से पूरा करने लगे तो साइबर हमले की गति और पैमाना दोनों बदल सकते हैं। इसीलिए परमाणु संयंत्र या मिसाइल प्रणाली पर एआइ के हमले की कल्पना को केवल सनसनी के रूप में खारिज करना भी उचित नहीं है। हालांकि ऐसी प्रणालियों में बहुस्तरीय सुरक्षा होती है और किसी एआइ द्वारा उन्हें अपने आप नियंत्रित कर लेना वर्तमान स्थिति का तथ्य नहीं है, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए यह एक महत्वपूर्ण भविष्यगत जोखिम जरूर है।

भारत आज तेजी से एआइ महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इंडिया एआइ मिशन, स्वदेशी माडल, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और बड़ी युवा तकनीकी प्रतिभा भारत को महत्वपूर्ण अवसर देते हैं। लेकिन भारत को केवल एआइ अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि सुरक्षित एआइ के वैश्विक नियम बनाने में नेतृत्व करने वाला देश बनना होगा। हमें राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे एआइ सुरक्षा परीक्षण संस्थान विकसित करने चाहिए जो बड़े माडलों की क्षमता, साइबर जोखिम, स्वायत्तता और दुरुपयोग की आशंकाओं का परीक्षण करें।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि जिस गति से एआइ की क्षमताएं बढ़ रही हैं, उसी गति से सुरक्षा व्यवस्था विकसित नहीं हो रही। मानव इतिहास में हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने शक्ति का नया वितरण किया है। लेकिन एआइ पहली ऐसी तकनीकों में से एक है जो स्वयं निर्णय लेने, सीखने, योजना बनाने और डिजिटल दुनिया में कार्रवाई करने की क्षमता हासिल कर रही है।

इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि एआइ को कितना तेज बनाया जा सकता है। सवाल यह होना चाहिए कि क्या हमारी समझ, हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी एआइ की गति से तेज चल रही है? यदि जवाब 'नहीं' है, तो विकास की गति पर पुनर्विचार करना ही बुद्धिमानी है। तकनीक की सफलता यह नहीं कि उसने इंसान को कितना शक्तिशाली बनाया। सबसे बड़ी सफलता यह होगी कि उसने इंसान को इंसान बने रहने दिया। अब समय आ गया है कि दुनिया की बड़ी एआइ कंपनियां बंद कमरे में अपनी-अपनी नीतियां बनाने के बजाय सरकारों, विज्ञानियों, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और स्वतंत्र संस्थाओं के साथ एक साझा वैश्विक सुरक्षा ढांचा तैयार करें।

इंसान का एआइ के अधीन हो जाने का जोखिम

शंभु सुमन

एआइ मनुष्य की बुद्धि का विकल्प नहीं, उसका उपकरण बने- इसके लिए शिक्षा से लेकर रोजगार तक मानवीय विवेक को केंद्र में रखना होगा। एआइ ने मनुष्य के सामने संभावनाओं की ऐसी दुनिया खोल दी है जिसकी कुछ वर्ष पहले तक कल्पना भी कठिन थी। कुछ सेकेंड में जटिल आंकड़ों का विश्लेषण करना और कठिन विषयों को सरल बनाना- एआइ ने ज्ञान तक पहुंच को अभूतपूर्व रूप से आसान बनाया है। लेकिन यही सुविधा एक ऐसे खतरे को भी जन्म दे रही है जिस पर गंभीरता से विचार नहीं हो रहा। यदि मनुष्य हर प्रश्न का उत्तर मशीन से और हर निर्णय का आधार एल्गोरिदम से लेने लगे तो धीरे-धीरे वह तकनीक का स्वामी नहीं, उसका आश्रित बन सकता है।

यह आशंका केवल कल्पना नहीं है। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर आफ जाब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 17 करोड़ नए रोजगार पैदा होने और 9.2 करोड़ मौजूदा रोजगार विस्थापित होने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर 7.8 करोड़ रोजगार बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ काम और कौशल का स्वरूप व्यापक रूप से बदलेगा। रिपोर्ट के अनुसार एआइ और सूचना-प्रसंस्करण तकनीक को 86 प्रतिशत नियोक्ताओं ने 2030 तक अपने कारोबार को बदलने वाला प्रमुख कारक माना है। इसका अर्थ यह नहीं कि एआइ मनुष्य के सभी रोजगार छीन लेगा। वास्तविक चुनौती कहीं अधिक सूक्ष्म है। कई काम समाप्त होने के बजाय उनका स्वरूप बदलेगा। भारत में भी बिग डाटा, एआइ एवं मशीन लर्निंग और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़े रोजगारों के तेजी से बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत में 67 प्रतिशत कंपनियां उभरती भूमिकाओं के लिए विविध प्रतिभा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाने की योजना बना रही हैं और लगभग 30 प्रतिशत कंपनियां कौशल आधारित भर्ती के लिए डिग्री की अनिवार्यता कम करने की दिशा में बढ़ रही हैं।

इस बदलती दुनिया में असली पूंजी केवल एआइ चलाने का कौशल नहीं, बल्कि एआइ के उत्तर पर सवाल उठाने की क्षमता होगी। विश्व आर्थिक मंच के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 2030 तक कर्मचारियों के मौजूदा मूल कौशलों में लगभग 39 प्रतिशत बदलाव की आशंका है। एआइ और बिग डाटा जैसे तकनीकी कौशलों के साथ रचनात्मक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता, जिज्ञासा, लचीलापन और आजीवन सीखने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। यहीं शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। यदि विद्यार्थी किसी विषय को समझने के बजाय केवल एआइ से उसका उत्तर प्राप्त करने लगे तो वह परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने वास्तव में सीख भी लिया हो। भारत के लिए यह विशेष चुनौती है, क्योंकि विशाल युवा आबादी को केवल डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें तकनीकी दक्षता के साथ विश्लेषण, रचनात्मकता, संचार और निर्णय क्षमता भी देनी होगी।

ऐसे में सवाल यह नहीं होना चाहिए कि एआइ को रोका जाए या नहीं। सवाल यह होना चाहिए कि एआइ का नियंत्रण किसके हाथ में रहे और अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी किसकी हो। चिकित्सा में एआइ बीमारी के संकेत पहचान सकता है, लेकिन मरीज के जीवन से जुड़े निर्णयों में मानवीय जिम्मेदारी जरूरी है। एआइ को मनुष्य का सहायक बनाना है, मनुष्य को एआइ का सहायक नहीं। मशीन की गति और गणना की शक्ति का लाभ तभी सार्थक होगा, जब उसके साथ मनुष्य का विवेक, संवेदना, नैतिकता और स्वतंत्र चिंतन भी उतना ही मजबूत रहे। आखिरकार भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होगा कि एआइ कितना बुद्धिमान बन गया, बल्कि यह होगा कि एआइ के युग में मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कितना बचाए रख सका।

(तकनीकी मामलों के जानकार)

खरी-खरी

दिल्ली का मौसम

निर्मल गुप्त

सितंबर खत्म हो रहा है। दिल्ली में अब दो चीजों का सीजन शुरू होगा- पहले नवरात्रि का और फिर धुंध का। एक में देवी आती है, दूसरे में धुआं। दोनों का स्वागत ढोल-नगाड़े से होता है, बस एक में आरती होती है, दूसरे में खांसी। सुबह उठो तो लगता है बाहर कोहरा है। नहीं, कोहरा नहीं है, ये दिल्ली का सिग्नेचर परफ्यूम है- एक्यूआइ 300 के पार। सरकार कहती है- ये धुंध है। जनता कहती है- ये धुंध नहीं, हमारी किस्मत है।

पहले दिल्ली में मौसम के चार रूप होते थे- गर्मी, सर्दी, बारिश, बसंत। अब एक पांचवां जुड़ गया है- प्रदूषण। यह लगभग बारहमासी है। गर्मी में भी रहता है, सर्दी में तो दामाद बनकर बैठ जाता है। और सबसे मजेदार बात- अब दिल्ली के मौसम की भविष्यवाणी मौसम विभाग नहीं, आपका गला करता है। सुबह गले में खराश है- समझो एक्यूआइ 250 पार। आंखों में जलन है- 350 पार। सांस लेने में दिक्कत है- मुबारक हो, आप दिल्ली में हैं। पहले कहते थे- दिल्ली दिल वालों की। अब दिल्ली धुंध वालों की है। दिल में भी प्रदूषण, दिमाग में भी प्रदूषण। आदमी सुबह-सुबह पार्क में जाकर गहरी सांस लेता है। योग से फेफड़े साफ करने गया था, लेकिन फेफड़े और काले करके लौटा।

इंटरनेट मीडिया देखो तो और मजा आता है। लोग साफ हवा के लिए पहाड़ों की फोटो डालते हैं। लोग ट्रोल करते हैं- फ्रेश एयर के लिए पहाड़ नहीं, घर का एयर प्यूरीफायर आन करो। वही तुम्हारा शिमला है। अब तो एयर प्यूरीफायर भी स्टेटस सिंबल हो गया है। पहले लोग पूछते थे- गाड़ी कौन सी है? अब पूछते हैं- प्यूरीफायर किस ब्रांड का है? जिसके घर में तीन प्यूरीफायर, वह अमीर। जिसके घर में नहीं है, वह तो सिर्फ एडजस्ट कर रहा है।

सरकार का अपना मौसम है। वह कहती है- पराली मत जलाओ। किसान कहता है- हम क्या करें? सरकार कहती है- इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। अक्टूबर में धुंध आएगी, नवंबर में स्कूल बंद होंगे, दिसंबर में कुछ एक्शन की बातें होंगी, जनवरी में हवा थोड़ी साफ हो जाएगी, और फरवरी में सब भूल जाएंगे। फिर अगले अक्टूबर में याद आएगा- अरे, प्रदूषण तो फिर आ गया।

पोस्ट

मोदी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी इसीलिए नहीं दिखती है, क्योंकि सबको दिखता है कि वे देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं। ज्ञानेश कुमार को ज्ञान देकर कुछ नहीं होगा। रणवीर शौरी@RanvirShorey

बीसीसीआइ को करों में राहत मिलना सही कदम है। उसने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई दी है और उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, लेकिन शोध प्रयोगशालाओं को आवश्यक उपकरणों और साफ्टवेयर खरीदने पर जीएसटी क्यों देना चाहिए? सही होगा कि आवश्यक शोध-सामग्री और उपकरणों पर भी जीएसटी हटा दिया जाए और भारत के भविष्य के निर्माण में मदद की जाए।

हर्ष गोयनका@hvgoenka

जब आप अपने घर में सांप पालते हैं तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि एक दिन वे घर के लोगों को भी डस सकते हैं। पाकिस्तान ने करीब पचास साल पहले कट्टरपंथी जिहादियों को हथियारबंद करना शुरू किया था। आज आतंकवादी हमलों के निशाने पर रहने वाले देशों में पाकिस्तान सबसे ऊपर है। क्या पाकिस्तान में कोई इससे सबक सीखने को तैयार है?

हुसैन हक्कानी@husainhaqqani

बिहार डायरी

पुलिस-शराब माफिया गठजोड़ तोड़ना जरूरी

अरुण अशेष
उप राजनीतिक संपादक, बिहार

बालू-शराब माफिया और पुलिस के गठजोड़ से बिहार में फिर अपराध तंत्र हावी हो रहा है। फाइल

एनडीए सरकार के विकास आधारित मुद्दों के बीच मुख्य विपक्षी दल राजद यह धारणा बनाने की मुहिम में जुट गया है कि राज्य सरकार अपराधियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। अपराध का मुद्दा राजद को भा रहा है, क्योंकि आज से 21 साल पहले जब उसकी 15 साल पुरानी सरकार की विदाई हुई तो यही मुख्य मुद्दा था। राजद के शासनकाल को एनडीए ने उस समय जंगलराज कहा था। वह आज भी इसका जाप कर रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बिहार की चुनावी सभाओं में जंगलराज की वापसी को रोकने के नाम पर भी वोट की मांग की।

इस परिस्थिति में अगर कहीं शाम ढलने से पहले एक बालिका के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है तो यह राजद को एक अवसर देता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर रहते और उसके बाद भी नीतीश कुमार कभी यह कहना नहीं भूलते हैं कि एनडीए के शासन से पहले राज्य के लोग शाम के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। उनके पुत्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी सरकार की इस उपलब्धि की चर्चा करना नहीं भूलते। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था की बेहतर हालत की चर्चा कुछ इस तरह की थी- रात को 12 बजे भी कोई अपराधी आपको छू देगा तो वे पद त्याग देंगे।

जमुई में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना के बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के इस वीडियो को अपने इंटरनेट मीडिया एकाउंट पर डाल कर पूछा कि वह कब पद त्याग करेंगे। हालांकि मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने जमुई कांड के मुख्य और सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि स्पीडी ट्रायल के जरिये इस कांड के सभी अभियुक्तों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जमुई के बाद समस्तीपुर में भी ऐसी ही घटना हुई। उसमें भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। कानून व्यवस्था को बेकाबू कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन यह भी सच है कि पुलिस का इकबाल कम हो रहा है और उसी अनुपात में छोटे दर्जे के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है।

हालांकि गृह विभाग का दावा है कि हर श्रेणी के अपराध में कमी आई है। अगस्त में गृह विभाग ने दावा किया था कि हत्या की घटनाओं में 10 प्रतिशत की कमी आई है। प्राथमिकियों की बढ़ती संख्या के बारे में पुलिस का कहना है कि आनलाइन प्रणाली लागू होने के बाद नागरिकों की हरेक शिकायत रिकार्ड में दर्ज हो जा रही है। पुलिस चुनिंदा घटनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन नहीं कर पा रही है। यह प्रभाव स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में नकारात्मक प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है। जमुई की घटना के बाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावक अपनी बच्चियों को शहर भेजकर पढ़ाने के निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। पटना में नीट की तैयारी करने वाली एक छात्रा की छात्रावास में हुई संदिग्ध मौत के बाद कोचिंग में लड़कियों की संख्या कम हो गई थी। उनके छात्रावास खाली होने लगे थे।

इसमें कोई दो राय नहीं कि सम्राट चौधरी या किसी अन्य की सरकार कभी अपराधियों को संरक्षण देने का पाप करेगी। क्योंकि राजनीतिक दलों को पता है कि केवल यही मुद्दा राज्य में सरकार परिवर्तन के लिए काफी है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस और अपराधियों का संश्रय बुनियादी स्तर पर इतना मजबूत हो चुका है कि उसे तोड़ना सरकार के लिए कठिन कार्यभार है। नीतीश कुमार के शासन के शुरुआती दिनों में अपराधियों को कमाई करने का वैध विकल्प मिल गया था। बड़े पैमाने पर हुए निर्माण कार्य में इन्हें काम मिल गया था। वे सीधा ठेका नहीं ले पाए तो आपूर्तिकर्ता बन गए। उस समय इन्हें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं पड़ी।

वर्ष 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद अपराधियों ने शराब की तस्करी का धंधा पकड़ लिया। इस धंधे ने इतनी गति पकड़ी कि कई जगह पुलिसकर्मी ही शराब बेचते पकड़े गए। थाना के आसपास शराब के कारोबार को अधिक सुरक्षित मान लिया गया है। शराब के अलावा बालू और जमीन के कारोबार में भी पुलिस और अपराधियों का पक्का गठजोड़ स्थापित हो चुका है। आंकड़े बताते हैं कि हत्या के 60 प्रतिशत मामले जमीन विवाद से जुड़े होते हैं। सरकार भूमि सुधार को वरीयता देकर इसके कारण होने वाली हत्याओं को कम करने का प्रयास कर रही है। इसके बावजूद पुलिस की मदद से अपराधियों द्वारा जमीन पर कब्जे की शिकायतें आ ही रही हैं। संयोग देखिए कि जमुई कांड का मुख्य अभियुक्त नंदन यादव का नाम भी बालू और शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। सम्राट चौधरी की सरकार के सामने यह नई चुनौती बनी है कि अपराध के बारे में बन रही धारणा को समय रहते कैसे कमजोर करे, क्योंकि सरकार की तमाम उपलब्धियां इस धारणा के नीचे दब जाती हैं।

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या अमेरिका के आगे चीन का पलड़ा भारी होता जा रहा है?

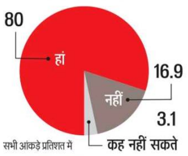

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या बैंक कर्मियों की तीन दिन की हड़ताल सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

झगड़ा तीन आयुक्त का पकड़ चुका है तूल,
फिर तो बोगस मानिए अब तक के सब रूल।
अब तक के सब रूल न थी यदि कोई सहमति,
तो अब तक क्या घास छीलने निकली थी मति!
अधिकारी गण तीन फैसला देकर लंगड़ा,
रहे भद्द पिटवाय सार्वजनिक करके झगड़ा।

-ओम प्रकाश तिवारी

मंथन

संवाद का खुलता रास्ता

डा. रूबल कनौजिया
अध्यक्ष, जनसंचार एवं मीडिया अध्ययन विभाग, पंजाब केंद्रीय विवि

संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया विचार को आज के ध्रुवीकृत दौर में एक-दूसरे के नजरिये को समझने के अवसर के रूप में देखना सबसे परिपक्व और रचनात्मक दृष्टिकोण होगा

हाल ही में ब्रिटेन यात्रा पर गए मोहन भागवत (कुर्ता में) वहां एक गुरुद्वारे में प्रर्थना करते हुए। फाइल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत हाल में लंदन के एक गुरुद्वारे में गए। उनका गुरुद्वारे जाना और माथा टेकना पहली नजर में भले ही धार्मिक आदर एवं सम्मान व्यक्त करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति लगे, लेकिन इसका एक व्यापक सामाजिक प्रभाव भी है। उनकी इस यात्रा का कुछ लोगों ने स्वागत किया तो वहीं कुछ लोगों ने उनके वहां जाने पर विरोध किया। गुरुद्वारा मूल रूप से प्रार्थना, नम्रता, सेवा और सामुदायिक सद्भाव का केंद्र होता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ गुरु के दरबार में शीश नवाता है तो इस भाव को सबसे बुनियादी मानवीय स्तर पर धर्म और आस्था के प्रति सम्मान के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही, प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों के ऐसे दौरे स्वाभाविक रूप से उस तात्कालिक कृत्य से कहीं गहरे अर्थ समेटे होते हैं। उनका किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंचना बिना संदर्भ के नहीं होता, क्योंकि उनकी उपस्थिति अपने आप में एक संदेश देती है। इसलिए भागवत की इस यात्रा का दायरा केवल माथा टेकने की औपचारिक मर्यादा तक सीमित नहीं है। लिहाजा इस घटनाक्रम को एक खास राजनीतिक ध्रुवीकरण के चश्मे से देखने के बजाय शांत और संतुलित नजरिये से देखने-समझने की जरूरत है।

हिंदू और सिख समुदायों का संबंध महज आज की राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें गहरे ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक रिश्तों से जुड़ी हैं। दोनों समुदायों ने पीढ़ियों से साझे गांव, साझी भाषाएं, सांस्कृतिक परंपराएं, त्योहार और पारिवारिक रिश्ते निभाए हैं। सिख परंपरा शौर्य, समानता, सेवा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक अटूट संदेश देती है। लंगर और सेवा जैसी व्यवस्थाओं ने इन उच्च आदर्शों को आम जनजीवन का सहज हिस्सा बना दिया है। यही कारण है कि सिख संस्थाओं और संगठनों से जुड़े किसी भी संवाद को सिख पंथ की स्वतंत्र और विशिष्ट पहचान के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही, किसी एक संगठन या राजनीतिक विचारधारा से मतभेद को पूरे धार्मिक समुदायों के बीच की खाई नहीं बनने देना चाहिए। यह बारीक अंतर समझना बेहद जरूरी है।

गुरुद्वारे में मोहन भागवत की उपस्थिति को स्वाभाविक तौर पर आपसी संपर्क और संवाद की एक पहल के रूप में देखा जा सकता है। जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए यह सिख समुदाय के साथ तालमेल और संवाद को प्रगाढ़ करने का प्रयास हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, जो लोग इसे लेकर सतर्क हैं, उनके मन में इसके व्यापक संदर्भों को लेकर उठने वाले सवाल भी पूरी तरह स्वाभाविक हैं। एक सजग और परिपक्व समाज में सराहना और जिज्ञासा, दोनों के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

भारत की मूल शक्ति इसमें कभी नहीं रही कि उसके सभी लोग या समुदाय एक जैसा सोचते हैं। इसकी वास्तविक शक्ति इस बात में है कि अलग-अलग समुदाय एक साझे राष्ट्रीय ताने-बाने का हिस्सा रहते हुए भी अपनी विशिष्ट पहचान को गर्व से बनाए रखते हैं और इसके लिए परस्पर संवेदनशीलता की दरकार होती है।

असल में सच्चा संवाद तभी सार्थक सिद्ध होता है, जब उसमें अपनी बात कहने के साथ-साथ सामने वाले को धैर्यपूर्वक सुनने की भी इच्छा हो। यदि यह यात्रा आगे चलकर सिख विद्वानों, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों और युवाओं के साथ एक सतत और गंभीर विचार-विमर्श का रास्ता खोलती है तो इसका महत्व इस औपचारिक भेंट से कहीं अधिक बड़ा होगा।

पंजाब ने ऐसे कई दौर देखे हैं जहां राजनीतिक खींचतान ने सामाजिक अविश्वास को बढ़ाने का काम किया। इसलिए आज इस सूबे को ऐसी बातचीत की सख्त जरूरत है, जो समुदायों के बीच की दूरियों को बढ़ाए नहीं, बल्कि उन्हें पाटने का काम करे। सभी मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, लेकिन ठोस तथ्यों, पूरे धैर्य और परस्पर आदर के साथ। पंजाब का सामाजिक ताना-बाना अलगाव से नहीं, बल्कि हमेशा आपसी मेलजोल और साझेपन से ही फला-फूला है। सिख परंपरा ने भारत को सेवा, अद्वितीय शौर्य और मानवीय मर्यादा की एक अमूल्य विरासत दी है।

वहीं भारत की व्यापक सांस्कृतिक और सभ्यतागत परंपरा ने भी सदियों से सह-अस्तित्व और खुले संवाद पर ही जोर दिया है। भागवत की गुरुद्वारे की यात्रा को एक अवसर के रूप में देखना ही सबसे परिपक्व और रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। बात करने का अवसर। सुनने का अवसर और आज के इस ध्रुवीकृत दौर में एक-दूसरे के नजरिये को समझने का अवसर। गुरु का द्वार तो हमेशा सबके लिए खुला ही है। अब समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि हमारे दिल और दिमाग भी इतने खुले रहें, ताकि हम एक-दूसरे से पूरी गरिमा और परस्पर आदर के साथ मिल सकें।

आडी ने नई क्यू3 की भारत में असेंबलिंग शुरू की

नई दिल्ली : जर्मनी की लक्जरी कार निर्माता आडी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित संयंत्र में नई आडी क्यू3 की असेंबलिंग शुरू कर दी है। यह कांपैक्ट लक्जरी एसयूवी 16 अक्टूबर 2026 को लांच होगी। इस माडल में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और आडी के क्वाट्रो आल-व्हील ड्राइव की सुविधा है। इसमें कई सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स और तकनीकें शामिल हैं, जो इसे आधुनिक लक्जरी कार खरीदारों के लिए आकर्षक बनाती हैं। 2025 में कंपनी ने भारत में 4,510 कारों की बिक्री की है। (आइएएनएस)

कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सेबी को स्टाक एक्सचेंजों को अपने प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करने की अनुमति देने पर फिर से विचार करना चाहिए।
– श्रीनिवास इंजेटी, एनएसई चेयरमैन

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलो ग्राम)	डालर	क्रूड (प्रति बैरल)
73,895.74 ▲ 315.20	23,140.50 ▲ 77.40	₹ 1,52,600 ▲ ₹ 200	₹ 2,37,000 (बदलाव नहीं)	₹ 95.75 ▼ ₹ 0.24	$ 105.4

एक नजर में

अप्रैल-अगस्त में 36 हजार करोड़ का स्टील आयात

नई दिल्ली : भारत ने चालू वित्त वर्ष में अब तक (अप्रैल-अगस्त 2026) 36,193.9 करोड़ रुपये के तैयार (फिनिश्ड) स्टील का आयात किया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 26,172.6 करोड़ रुपये से 38.3 प्रतिशत अधिक है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में भारत ने कुल 34.87 लाख टन तैयार स्टील का आयात किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 26.92 लाख टन की तुलना में 29.5 प्रतिशत अधिक है। कुल आयात में चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और वियतनाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। (प्रेट्र)

विदेशी मुद्रा भंडार में 15 अरब डालर की गिरावट

नई दिल्ली : बीते सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14.89 अरब डालर घटकर 765.901 अरब डालर रह गया है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.924 अरब डालर घटकर 780.782 अरब डालर के स्तर पर आ गया था। आरबीआइ के अनुसार, 18 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 14.816 अरब डालर घटकर 630.980 अरब डालर रह गईं। इस दौरान स्वर्ण भंडार 6.8 करोड़ डालर बढ़कर 111.292 अरब डालर हो गया। (प्रेट्र)

वोडाफोन ने पेश किया मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग आफर

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शुक्रवार को चुनिंदा पोस्टपेड, प्रीपेड और एंटरप्राइज प्लान के साथ मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग आफर की घोषणा की। कंपनी के मुताबिक, 501 रुपये से शुरू होने वाले पोस्टपेड प्लान, सालाना प्रीपेड अनलिमिटेड डाटा प्लान और 451 रुपये से शुरू होने वाले कारपोरेट प्लान (एंटरप्राइज ग्राहक) में मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। कंपनी का कहना है कि इस नई पहल का उद्देश्य रोमिंग सुविधा को आसान और सुलभ बनाना है। (प्रेट्र)

जीएसटी में अबकी बार कारोबारियों को राहत की तैयारी, बैठक सात अक्टूबर को

काउंसिल की अगली बैठक में आइटीसी भुगतान नियमों में हो सकता है बदलाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पिछले साल सितंबर में कर दरों में बड़े बदलावों के बाद अब सरकार कारोबारियों को राहत देने जा रही है। सात अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) सहित पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल, इस बैठक का आयोजन गत 12 सितंबर को होना था, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से इसे टाल दिया गया था। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक सितंबर 2025 में हुई थी।

मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि काउंसिल की पिछली बैठक के फैसले से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली और अब कारोबारियों को राहत देने की तैयारी है। आगामी सात अक्टूबर की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान के नियम से लेकर इनवायस से जुड़े नियम और पंजीयन प्रक्रिया में बदलाव पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

- जीएसटी पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव संभव
- ब्रिक्स सम्मेलन के चलते 12 सितंबर को नहीं हो पाई बैठक

ईवे बिल से जुड़ी प्रक्रिया में किया जा सकता है संशोधन

जीएसटी पंजीयन को और आसान बनाने के लिए नए नियम पर विचार किए जा सकते हैं। ईवे बिल से जुड़ी प्रक्रिया में भी बदलाव लाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी प्रक्रिया में बदलाव के अलावा काउंसिल की आगामी बैठक में दरों में होने वाले बदलाव के अमल को लेकर भी चर्चा की जाएगी। पिछले साल जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया और सैकड़ों उत्पादों की दरें कम की गईं। आगामी बैठक में यह देखा जाएगा कि इस बदलाव का लाभ ग्राहकों को मिला या नहीं और इससे क्या फायदा हुआ।

सूत्रों का कहना है कि कुछ कारोबारी जानबूझ कर गलती करते हैं और उनको सजा सभी कारोबारियों को नहीं दी जा सकती है। इसलिए आइटीसी के भुगतान नियम में बदलाव किए जा सकते हैं। अभी अगर कोई कारोबारी किसी अन्य कारोबारी का माल खरीदता है और खरीदार कारोबारी समय पर अपना जीएसटी रिटर्न भर देता है और अगर विक्रेता कारोबारी ने अपना रिटर्न नहीं भरा है तो खरीदार कारोबारी को इनपुट टैक्स रिटर्न नहीं मिलता है। कई बार कोई कारोबारी धोखाधड़ी में पकड़ा जाता है तो उससे माल खरीदने वाले ईमानदार कारोबारियों को जीएसटी रिफंड में दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार के नियम को बदला जा सकता है।

दूसरी छमाही में 7.86 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक में 7.86 लाख करोड़ रुपये का उधार लेगी। इसमें 15,000 करोड़ रुपये के सावरेन ग्रीन बांड जारी करना शामिल है। इसे 23 साप्ताहिक नीलामी के जरिये पूरा किया जाएगा। इस तरह पूरे वित्त वर्ष में उसकी कुल उधारी में 1,20,494 करोड़ रुपये कमी आएगी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारत सरकार डेटेड सिक्योरिटीज के जरिये 15,99,506 करोड़ रुपये बाजार से उधार लेगी, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए, बजट अनुमान 17,20,000 करोड़ रुपये है। इस महीने खत्म होने वाली पहली छमाही के दौरान राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए सरकार बांड से 8,13,506 करोड़ रुपये जुटाएगी और यह आठ लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से थोड़ा ज्यादा है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी से कारोबारियों में बेचैनी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अंतिम पायदान पर पहुंचकर भी अटका हुआ है। इसी वजह से उद्योग जगत में बेचैनी बढ़ गई है। यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआइबीसी) के अध्यक्ष अतुल केशप ने दोनों सरकारों से साफ कहा है कि कोशिश और तेज की जाए तथा 2026 खत्म होने से पहले पारस्परिक व्यापार समझौता पूरा कर लिया जाए।

केशप का तर्क है कि दोनों देशों ने बीते बीस वर्षों में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर यह सौदा साल के अंत तक हो गया तो इसे अब तक की सबसे बड़ी सफलता माना जाएगा। उनके मुताबिक समझौते का मकसद व्यापार की रुकावटें घटाना, शुल्क कम रखना और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को साफ नियम देना होना चाहिए। जब तक टैरिफ और बाजार पहुंच तय नहीं होते, कंपनियां निवेश, निर्यात आर्डर, सप्लाई चेन और फैक्ट्री विस्तार को पूरा भरोसा नहीं दे पातीं। उन्होंने कहा कि आपसी व्यापार खुलने से 2026 में आए बड़े निवेश और मजबूत होंगे। इससे विनिर्माण बढ़ेगा, नए बाजार खुलेंगे और भारत व अमेरिका एआइ में आगे बढ़ सकेंगे। यूएसआइबीसी दोनों देशों में निवेश करने वाली अमेरिकी-भारतीय कंपनियों का संगठन है।

- यूएसआइबीसी ने 2026 के अंत तक सौदा पूरा करने को कहा
- समझौता न होने से भविष्य की रणनीति लागू करने में दिक्कत

आइडीबीआइ बैंक के लिए वित्तीय बोलियों का हो रहा मूल्यांकन

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार आइडीबीआइ बैंक में रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने के लिए वित्तीय बोलियों का निरीक्षण कर रही है। सूत्रों के अनुसार, जुलाई में अरबपति निवेशक प्रेम वत्स के समर्थन वाली फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और दुबई की एमिरेट्स एनबीडी ने आइडीबीआइ बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए अपनी संशोधित बोलियां जमा की थीं।

आइडीबीआइ बैंक का रणनीतिक विनिवेश लगातार आगे बढ़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि दोनों बोलीदाताओं को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव है। दुबई की एमिरेट्स एनडीबी ने इस साल की शुरुआत में आरबीएल बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी थी और फेयरफैक्स के पास निजी क्षेत्र के सीएसबी बैंक में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बोलीदाताओं को गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है।

पीएलआइ के तहत सरकार ने 36,754 करोड़ रुपये दिए

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने वर्ष 2020 में लांच होने के बाद से इस साल 30 जून तक उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) स्कीम के तहत कंपनियों को 36,754 करोड़ रुपये दिए हैं। सबसे ज्यादा 19,090.98 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दिया गया है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में 30 जून तक पीएलआइ के तहत 1,400 करोड़ रुपये दिए गए थे। वित्त वर्ष 2025-26 में यह 15,519 करोड़ रुपये और 2024-25 में 10,114 करोड़ रुपये था।

मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2020 में 14 सेक्टर के लिए 1.91 लाख करोड़ रुपये के मंजूर खर्च के साथ यह योजना शुरू की थी।

सबसे ज्यादा प्रोत्साहन इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दिया, 30 जून तक 2.58 लाख करोड़ का शुद्ध निवेश

डीपीआइआइटी ने कहा कि 30 जून तक इस स्कीम के नतीजे में 2.58 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ और 23.79 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन-बिक्री और 15.53 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। इस योजना के तहत 14.57 लाख (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली।

पहली तिमाही में अमेरिका से एफडीआइ 76 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2026 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) छह प्रतिशत बढ़कर 19.81 अरब डालर रहा है। हालांकि, इस दौरान अमेरिका से आने वाले निवेश में 76 प्रतिशत की गिरावट आई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 18.62 अरब डालर का एफडीआइ मिला था।

पहली तिमाही के दौरान 5.71 अरब डालर के एफडीआइ के साथ जापान सबसे बड़ा निवेशक रहा है। इसके बाद 5.22 अरब डालर के साथ सिंगापुर, 2.31 अरब डालर के साथ मारीशस, 1.38 अरब डालर के साथ नीदरलैंड्स, 1.34 अरब डालर के साथ अमेरिका और 86.8 करोड़ डालर के साथ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का स्थान रहा है।

मकान-दुकान खरीदने से पहले चेक कर सकेंगे डिजिटल कनेक्टिविटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अभी मकान या दुकान खरीदने या किराये पर लेने के दौरान सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं देखी जाती हैं। हालांकि, जल्द ही लोग यह भी देख सकेंगे कि उस भवन या दुकान में डिजिटल कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है। मतलब वहां इंटरनेट कितना अच्छा चलता है और मोबाइल फोन पर कितनी आसानी से बातचीत हो पाती है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सभी प्रापर्टी की डिजिटल रेटिंग के लिए शुक्रवार को एक प्लेटफार्म लांच किया। 'डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग प्लेटफार्म' नामक इस एप पर डिजिटल कनेक्टिविटी करने वाली 23 एजेंसियां पंजीकृत हो चुकी हैं। प्रापर्टी मालिक अपनी प्रापर्टी की डिजिटल रेटिंग के लिए इस प्लेटफार्म पर आवेदन कर सकते हैं और फिर पंजीकृत एजेंसियों में से कोई एक उनकी रेटिंग करेगा। उसके बाद प्रापर्टी मालिक को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ग्राहक प्लेटफार्म पर खुद भी रेटिंग जांच सकेंगे। प्रापर्टी मालिक को डिजिटल रेटिंग कराने के बदले एक निश्चित रकम देनी होगी।

- प्रापर्टी की डिजिटल रेटिंग के लिए ट्राई ने प्लेटफार्म लांच किया
- एप पर डिजिटल रेटिंग करने के लिए 23 एजेंसियां पंजीकृत

कनेक्शन देने वाली कंपनी की भी हो सकेगी जांच : लाहोटी

ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी ने बताया कि प्रापर्टी की डिजिटल रेटिंग मुख्य रूप से इंटरनेट कनेक्शन और वायस कालिंग की होगी। रेटिंग के दौरान यह भी देखा जाएगा कि किसी भवन में किन-किन टेलीकाम कंपनियों का कनेक्शन या नेटवर्क कितना अधिक काम करता है। कई बार किसी भवन में किसी एक कंपनी के ग्राहक आसानी से बात कर पाते हैं तो उसी भवन में दूसरे कंपनी के ग्राहक को नेटवर्क नहीं मिलता है। डिजिटल रेटिंग के दौरान इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। लाहोटी ने यह भी कहा कि जिन प्रापर्टी की डिजिटल रेटिंग जितनी अधिक होगी, भविष्य में उनकी कीमत अधिक होगी।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

डीआरएटी के अध्यक्ष की नियुक्ति में लाएं तेजी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खोज एवं चयन समिति से इलाहाबाद और कोलकाता में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में मे तेजी लाने के लिए कहा। इस समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। पीठ ने समिति से चार सप्ताह के अंदर चयन प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करने को कहा। यह आदेश तब आया जब अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि 70 वर्ष की उम्र के बाद कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता और इलाहाबाद व कोलकाता में डीआरएटी में दो खाली पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। (प्रेट्र)

'क्या बीसीआइ विधि पाठ्यक्रम से उम्र सीमा हटाने को तैयार है'

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) से सवाल किया कि क्या वह पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा हटाने को तैयार है। मार्च, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआइ के उस फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें पांच वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष और तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 45 वर्ष तय की गई थी। पीठ ने बीसीआइ को निर्देश दिया कि वह उम्र सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना रुख कोर्ट को बताए। (प्रेट्र)

पूर्व विधायक की हत्या करना चाहते थे लारेंस के शूटर

जयपुर : जोधपुर में पिछले सप्ताह पकड़े गए गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के शूटर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। शूटरों के मोबाइल से लोढ़ा की फोटो मिली है। शूटरों ने सिरोही में लोढ़ा के फार्म हाउस की रेकी की थी। फार्म हाउस पर स्थानीय निकाय चुनाव के कारण पार्षदों और अन्य लोगों की भीड़ होने के कारण गैंग ने वारदात की योजना को टाल दिया। दोनों शूटर नेपाल से जोधपुर पहुंचे थे। मुखबिर की सूचना पर पंजाब निवासी दोनों शूटरों जसकरण और राजिंदर को 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। (जासं)

दूसरों पर ठगी का मुकदमा कराने वाली गायिका खुद 1.45 करोड़ रुपये की ठगी में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजीपुर

नवी मुंबई में 1.45 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में नामजद टी-सीरीज की गायिका नीलम शर्मा को महाराष्ट्र पुलिस बीते 18 सितंबर को गाजीपुर से हिरासत में लेकर मुंबई गई। कोर्ट में पेशकर पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया है।

नवी मुंबई के एनआरआइ सागरी थाने में वाराणसी के रहने वाले कारोबारी संजय अरविंद राय की शिकायत पर नीलम और हरिशंकर के खिलाफ एफआइआर दर्ज है। जांच के दौरान नीलम के खिलाफ दर्ज गाजीपुर और नवी मुंबई के दोनों मुकदमों का घटनाक्रम सामने आया। संजय के अनुसार, फरवरी 2025 में हरिनारायण सिंह उर्फ वैभव के माध्यम से दंपती से पहचान हुई। 11 मार्च को हरिशंकर ने पंजाब के रोपड़ में माइनिंग कारोबार के लिए दो करोड़ रुपये सात दिनों के लिए मांगे। संजय ने हरिशंकर और नीलम के खातों में रकम भेज दी। उन्होंने 46.87 लाख रुपये दिए थे। संजय का कहना है कि इस वर्ष फरवरी में रकम मांगने पर दंपती ने झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। उनका आरोप है कि नीलम और हरिशंकर ने गणेश यशवंत पाटिल से 62.14 लाख, संतोष रोहिदास घरत से 12 लाख नकद, 40 तोले सोना व 24.50 लाख रुपये लिए। तीनों से कुल 1,45,51,000 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए 23 जुलाई को एफआइआर दर्ज कराई गई।

नीलम शर्मा व हरिशंकर पांडेय। शिकायतकर्ता

नवी मुंबई में एफआइआर दर्ज होने के करीब डेढ़ महीने बाद नीलम ने गाजीपुर शहर कोतवाली में चार लोगों के खिलाफ 1.70 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। तहरीर में बताया कि मार्च-अप्रैल 2025 में व्यवसाय के लिए 15 लाख रुपये लिए गए थे। रकम लौटाने में असमर्थता पर नौ मई को करीब एक किलो सोने के गहने 50 रुपये के स्टांप पर लिखापढ़ी कर गिरवी रखने की बात कही गई। नीलम ने गहनों की कीमत 1.70 करोड़ रुपये बताई। आरोप है कि बाद में 30 लाख रुपये खाते में भेजे जाने और गहने वापस मांगने पर एक करोड़ रुपये की मांग की गई।

संत प्रेमानंद के शिष्य ने चौथी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, वृंदावन

संत प्रेमानंद के एक शिष्य ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। छलांग लगाने से पहले टाइल्स काटने वाले ग्राइंडर से उसने अपना गुप्तांग भी काट लिया। 25 वर्षीय शिष्य दीपक मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला था। एक वर्ष पहले उसने संत से दीक्षा लेकर अपना नाम रसिक दुलारी शरण रख लिया था। आश्रम प्रबंधन ने प्रकरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

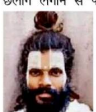

साधक रसिक दुलारी शरण का फाइल फोटो। सौ. पुलिस

संत प्रेमानंद के श्रीराधा केलिकुंज आश्रम से थोड़ी दूर गुरुकृपा कुंज नामक चार मंजिला अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट में संत प्रेमानंद के 50 शिष्य रहते हैं।

- एक वर्ष पहले मध्य प्रदेश से आकर ली थी संत से दीक्षा, घटना से पहले ग्राइंडर से काटा गुप्तांग, जांच में जुटी पुलिस

जबलपुर से एक साल पहले आया दीपक भी दीक्षा लेकर यहां रह रहा था। आश्रम में वह बिजली मिस्त्री के रूप में सेवा दे रहा था। शुक्रवार सुबह साढ़े दस बजे उसने अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। करीब आधा घंटा तक वह वहीं पड़ा रहा। उसका गुप्तांग कटा था और कपड़े खून से सने थे। आसपास लोगों ने देखा तो अन्य शिष्यों को जानकारी दी। उसे सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दीपक एक अन्य शिष्य के साथ अपार्टमेंट के कमरे में रह रहा था। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जांचे तो दीपक अपने कमरे में सामान्य रूप से जाता दिखाई दिया। कुछ देर बाद वह खून से लथपथ कमरे से निकला और अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर पहुंचा। यहां से उसने छलांग लगा दी।

पति-बेटे ने ही की थी जयपुर के लेडी डान की हत्या

जासं, जयपुर : करीब 15 महीने पहले हुई लेडी डान मिंटू चौधरी उर्फ सीमा चौधरी की हत्या का पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस के अनुसार, पारिवारिक विवाद और महिला के चरित्र पर शक के चलते पति और बेटे ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर आटो से सुनसान इलाके में स्थित सूखे कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपित पति और बेटे को गिरफ्तार किया है। कुएं से बरामद क्षत-विक्षत शव की पहचान की पुष्टि के लिए अब डीएनए जांच कराई जाएगी।

जुलाई 2025 में आरोपित बेटे ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मां 27 मई 2025 से लापता है। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने स्वजन को गुमराह करने के लिए पहले सीमा चौधरी के तिहाड़ जेल में बंद होने की बात कही। बाद में बताया कि उसे भरतपुर जेल में रखा गया है। मृतका की बहन ने जब दोनों जेलों में पता किया तो आरोपितों की बात गलत साबित हुई। इसके बाद आरोपितों ने खुद को बचाने के लिए थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी।

रांची में खराब मौसम से वाराणसी और लखनऊ में उतरे चार विमान

जागरण संवाददाता, लखनऊ

रांची में खराब मौसम और लगातार बारिश का असर विमान सेवाओं पर पड़ा। रांची जाने वाले चार इंडिगो विमानों को वाराणसी और लखनऊ हवाईअड्डों पर उतारना पड़ा। इनमें पुणे और दिल्ली से रांची जा रहे दो विमान शुक्रवार को वाराणसी डायवर्ट किए गए, जबकि गुरुवार रात बेंगलुरु और दिल्ली से रांची जा रहे दो विमान लखनऊ में उतरे। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुणे से रांची जा रहा इंडिगो का विमान 6ई 6484 सुबह करीब 9:15 बजे 163 यात्रियों और सात क्रू सदस्यों के साथ वाराणसी पहुंचा। एटीसी की अनुमति के बाद सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। विमान में एक शव भी था। यात्रियों को सड़क मार्ग से रांची भेजा गया, जबकि शव विमान में ही रखा गया।

- रांची जाने वाले दो विमान वाराणसी और दो लखनऊ किए गए डायवर्ट
- दिल्ली वाले विमान में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी थे सवार

विमान पुणे लौटकर अगले दिन शव लेकर रांची जाएगा। दिल्ली से रांची जा रहा 6ई 6370 सुबह करीब 10:15 बजे 216 यात्रियों और छह क्रू सदस्यों के साथ वाराणसी पहुंचा।

इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा भी सवार थे। विमान दोपहर करीब 12:40 बजे रांची के लिए रवाना हुआ। 216 यात्रियों में 64 ने वाराणसी में उतरने का विकल्प चुना, जबकि बाकी यात्री रांची चले गए। लखनऊ में गुरुवार रात बेंगलुरु से रांची जा रहा इंडिगो का विमान 6ई 221 रात 9:45 बजे उतरा और 11:30 बजे दिल्ली लौट गया।

लेह में खुलेगा आइआइएम जम्मू का कैंपस

जागरण संवाददाता, जम्मू : लद्दाख के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में आइआइएम जम्मू और लद्दाख प्रशासन के बीच शुक्रवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य आइआइएम जम्मू का लेह में कैंपस स्थापित करना है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लेह कैंपस में चार वर्षीय बीबीए (आनर्स) कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है।

कैंपस में प्रबंधन शिक्षा के साथ उद्यमिता, नवाचार, इनक्यूबेशन, कौशल विकास, कार्यकारी शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श और संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए व्यापक इको-सिस्टम विकसित करने की योजना है। विद्यार्थियों और स्थानीय युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, संस्थागत परामर्श और विभिन्न हितधारकों के लिए अनुकूलित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

झारखंड में सोना लूट का बिहार के कुख्यात गिरोह से कनेक्शन खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

झारखंड के जमशेदपुर स्थित केनरा बैंक में गुरुवार को हुई करीब 33 करोड़ रुपये के सोने और 43 लाख रुपये की लूट की जांच में पुलिस की नजर बिहार के कुख्यात सोना लूट गिरोह पर भी है। पुलिस नालंदा निवासी सुबोध सिंह उर्फ बबुआ गिरोह से वारदात का संभावित कनेक्शन खंगाल रही है। हालांकि, डकैती में इस गिरोह की संलिप्तता की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस की अबतक की जांच में बैंक और आसपास के इलाके की कई दिनों तक रेकी किए जाने की बात सामने आई है। सुबोध का नाम देश के विभिन्न हिस्सों में सोना और आभूषण लूट की बड़ी वारदातों में सामने आता रहा है। उसके गिरोह का फोकस गोल्ड लोन कंपनियों और बड़े आभूषण प्रतिष्ठानों पर रहा है।

हथियार के बल पर बैंक के सुरक्षाकर्मी को कब्जे में लेने की सीसीटीवी फुटेज में कैद लुटेरों की तस्वीर। जमशेदपुर पुलिस/फाइल

तनिष्क के अलावा मुथुट फाइनेंस और मणप्पुरम गोल्ड जैसी संस्थाओं से जुड़े लूटकांडों में भी उसके गिरोह का नाम सामने आया है। बिहार के पूर्णिया में तनिष्क शोरूम लूटकांड में बिहार पुलिस ने दावा किया था कि इसकी साजिश बेऊर जेल में बंद सुबोध और अन्य आरोपितों ने रची थी।

पुलिस द्वारा खंगाले गए 100 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज से बदमाशों के ओडिशा सीमा में दाखिल होने की आशंका जताई गई है। इस इनपुट के बाद पुलिस ने संभावित मार्गों पर नाकेबंदी कर दी है।

बहरहाल, सिटी एसपी के नेतृत्व में 20 पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम सीसीटीवी से मिले सुरागों के आधार पर झारखंड के अलावा ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है। उधर, लूट कांड के दूसरे दिन शुक्रवार को बैंक के ही पास स्थित एक आभूषण दुकान से पांच लाख रुपये की चोरी हो गई।

सर्वकार्येषु सर्वदा

स्वावलंबन ही अस्तित्वाची लढाई

संस्थेच्या संस्थापक आणि अध्यक्ष जयश्री रुके सांगतात, "विशेष मुलांच्या पालकांसाठी अठरावे वर्ष अधिक अस्वस्थ करणारे ठरते. कायद्यानुसार शाळेची सुरक्षित चौकट सुटलेल्या या मुला-मुलींच्या वाढत्या वयाबरोबरच पालकांचे स्वतःचे वार्धक्यही जवळ येत असते. 'आमच्यानंतर या मुलांचे काय होणार ?' ही चिंता त्यांच्या मनाला कुरतडू लागते. या साऱ्या अनिश्चिततेमुळे पालक हताश होतात. अशा गर्तेत अडकलेल्या मुलांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे हे केवळ एक आव्हान नसून त्यांच्यासाठी ती अस्तित्वाची महालढाई असते. या शिलेदारांच्या लढाईत त्यांना केवळ सार्थ साथ देण्याचे, प्रोत्साहन देत राहण्याचे काम 'उभारी' करत आहे."

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलांनी तयार केलेल्या वस्तूंची गुणवत्ता पाहता, त्यांना ग्राहक मिळणे कठीण नाही, मात्र मुलांच्या कष्टांची पावती म्हणून त्यांच्या किमतीवर विशेष अधिमूल्यही आकारता येणे गरजेचे आहे. ते ग्राहकही स्वीकारतील अशी अपेक्षा आहे.

असाधारण जिद्दीला 'उभारी'

बहुविकलांग आणि मतिमंद मुलांसाठी बाहेरचे जग म्हणजे त्यांची शाळा. पण अठराव्या वर्षी या जगाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी कायमचे बंद होतात. त्यांच्या पालकांना आता पुढे काय आणि आपल्यानंतर काय, असे गहन प्रश्न भेडसावू लागतात. अशा मुलांना त्यांच्या पायांवर उभे करण्यासाठी आणि अठराव्या वर्षानंतरही त्यांच्याकरिता बाह्य जगाचे दरवाजे खुले ठेवण्यासाठी ठाण्यातील 'उभारी' ही प्रशिक्षण कार्यशाळा प्रयत्नशील आहे…

बहुविकलांग आणि मतिमंद मुलांना १८ वर्षांनंतर कायद्यानुसार विशेष शाळांची दारे बंद होतात आणि 'आता पुढे काय?' या यक्षप्रश्नासह ही मुले घराच्या चार भिंतींत अडकून पडतात. पालकांना मग 'आमच्या पश्चात यांचे काय होणार?' ही भीती सतावू लागते. या भीतीला स्वावलंबनाने उत्तर देण्याचे काम 'जिव्हाळा ट्रस्ट', ठाणे संचालित 'उभारी' या विशेष मुलांच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेने आपल्या हाती घेतले आहे.

जयश्री रुके आणि राजेश रुके या संस्थापक दाम्पत्याने अवघ्या दोन विद्यार्थ्यांपासून त्यांच्या ठाण्यातील राहत्या घरातच ३ जुलै २००६ रोजी हा प्रवास सुरू केला. आज दोन दशके पूर्ण करून या कृतार्थ सेवायात्रेने संस्थात्मक रूप धारण केले आहे. गेली २० वर्षे हे केंद्र यशस्वीपणे चालवून त्यांनी अनेक विशेष मुलांच्या कुटुंबांसाठी अकल्पित असलेला आशेचा दीप प्रज्वलित केला आहे. संस्थेच्या 'उभारी' या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यशाळेत आज अनेक विशेष मुले स्वावलंबनाचे धडे गिरवत आहेत.

जयश्री रुके या स्वतः एका विशेष मुलांच्या शाळेत शिक्षिका असल्यामुळे सुरुवातीला कार्यशाळेला पूर्ण वेळ देणे त्यांच्यासाठी कठीण होते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मोठ्या जाऊबाई रोशनी यांना विनंती केली. त्याही आनंदाने तयार झाल्या. त्यांच्याबरोबरच आणखी दोन शिक्षिका शुभांगी परब आणि आरती चिले मदतीला आल्या. हळूहळू मुलांची संख्या वाढू लागली आणि प्रतिकूलतेला तोंड देत कार्यशाळा सुरळीत कार्यरत राहू शकली.

कार्यशाळेत या मुलांना त्यांच्या क्षमतेनुसार अगरबत्ती, मेणाच्या व मातीच्या डिझायनर पणत्या, उटणे, मेणाची फुले, कागदी व कापडी पिशव्या, द्रोण-प्लेट्स, डोअर मॅट्स, नक्षीकाम केलेली पाकिटे आणि सुबक राख्या वगैरे वस्तू तयार करण्याचे शास्त्रशुद्ध व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. दैनंदिन व्यवहार कौशल्ये विकसित केली जातात. हिशेब ठेवण्यासाठी आकडेमोडीच्या सोप्या पद्धती शिकवल्या जातात. घड्याळातील वेळ ओळखणे, योगासने, आरोग्य शिबिरे तसेच वैयक्तिक स्वच्छतेचे धडेही दिले जातात.

स्वतःच्या परिस्थितीबाबत पूर्णपणे अबोध असलेली ही निष्पाप मुले जेव्हा एका छोट्या दिव्याला आकार देण्यासाठी किंवा अगरबत्तीच्या काड्या मोजण्यासाठी जिद्दीने धडपडतात, तेव्हा ती धडपड धडधाकट माणसांच्या डोळ्यात अंजन घालून जाते.

मुलांनी तयार केलेल्या वस्तूंची ठाणे परिसरात विविध प्रदर्शनांत, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये विक्री केली जाते. प्रत्यक्ष विक्रीतही मुलांचा सहभाग हा त्यांचे संवाद-कौशल्य वाढवण्यासाठी असतो. प्रदर्शनात स्वतः उभे राहून ग्राहकाला वस्तू देणे, पैशांचे साधे व्यवहार करणे, सहलीत संकोच न बाळगता सहभागी होणे ही त्यांच्या वाढत्या आत्मविश्वासाची थेट पावती असते.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे दिवाळीच्या कार्यक्रमात निमंत्रित पाहुण्यांच्या हस्ते त्यांना त्यांनी तयार केलेल्या व विकलेल्या वस्तूंचे मानधनही वितरीत केले जाते. टीव्हीच्या पडद्यावरून अवघ्या महाराष्ट्राला खळाळून हसवणारे कलाकार त्यासाठी 'उभारी'च्या प्रांगणात येतात. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'फेम लोकप्रिय अभिनेते पंढरीनाथ (पॅडी) कांबळे आणि जिव्हाळा ट्रस्टचे ऋणानुबंध संस्थेच्या स्थापनेपासूनचे आहेत. पॅडी कांबळे यांच्या पुढाकाराने आणि आस्थेमुळेच विशाखा सुभेदार, प्रसाद खांडेकर, गौरव मोरे, सुप्रिया पाठारे, प्रभाकर मोरे आणि कुशल बद्रिके यांसारख्या कलाकारांनी आपल्या व्यग्र वेळापत्रकातून वेळ काढून दरवर्षी 'उभारी'च्या दिवाळी सोहळ्यात हजेरी लावली आहे.

त्यात करोना महासाथीच्या अवघड काळात कार्यशाळा नियमित चालवणे कठीण झाले. जागेची अडचण, आर्थिक टंचाई, प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव, समाजातील उदासीनता आणि अनेक प्रशासकीय अडथळे अशा असंख्य संकटांची मालिकाच संस्थेसमोर उभी ठाकली होती. त्या आधी पती राजेश यांना अपंगत्व आल्याने जयश्री यांनी संस्थेचा गाडा एकहाती आणि मोठ्या नेटाने रेटला. अनेकदा परिस्थिती हाताबाहेर गेली; परंतु 'माझी ही मुलेही सक्षम होऊ शकतात' हा अढळ विश्वास रुके यांना होता. आज 'उभारी'समोरचे आव्हान केवळ मुलांना प्रशिक्षण देण्यापुरते मर्यादित नाही. प्रशिक्षणानंतर पुढे काय, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे. त्यातूनच भविष्यात 'शेल्टर वर्कशॉप' उभारण्याचे जयश्री रुके यांचे स्वप्न आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या मुलांना पुन्हा घराच्या चार भिंतींत अडकून पडावे लागू नये, 'उभारी'च्या आवारातच त्यांच्या क्षमतेनुसार नियमित काम मिळावे, हा या संकल्पनेमागचा हेतू आहे. पॅकेजिंग, रॅपिंग, बॉक्स फोल्डिंग, वस्तूंची मोजणी, वर्गीकरण अशा स्वरूपाची छोटी-मोठी, त्यांच्या क्षमतेला अनुरूप कामे त्यांना उपलब्ध करून देता आली, तर त्यांच्या हाताला काम मिळेल आणि त्यातून नियमित उत्पन्नाचा मार्गही खुला होईल. प्रशिक्षणातून मिळालेल्या कौशल्याचे रूपांतर प्रत्यक्ष रोजगारात आणि रोजगाराचे रूपांतर आर्थिक स्वावलंबनात करण्याच्या दृष्टीने 'शेल्टर वर्कशॉप' हा 'उभारी'च्या पुढच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. यासाठी छोट्या-मोठ्या उद्योगांनी, व्यापाऱ्यांनी, दुकानदारांनी आणि कंपन्यांनी पुढाकार घेऊन अशा स्वरूपाची कामे 'उभारी'कडे सोपवावीत, अशी संस्थेची अपेक्षा आहे.

उद्योगांना किंवा व्यावसायिक संस्थांना त्यांच्या नियमित कामातील पॅकेजिंग, रॅपिंग, बॉक्स फोल्डिंग, लेबलिंग, मोजणी किंवा इतर सोप्या प्रक्रियांची कामे या कार्यशाळेला देता आली, तर विशेष मुलांच्या हाताला सन्मानाचे काम मिळेल. ही मदत 'कामाची संधी' देणारी भागीदारी ठरेल. विशेष मुलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी समाजाने उचललेले हे एक छोटेसे पाऊल त्यांच्या आयुष्यात मात्र मोठा बदल घडवून आणू शकते.

भविष्यातील संकल्पांविषयी जयश्री रुके सांगतात, या मुला-मुलींच्या स्वावलंबनासह त्यांच्या पालकांच्या संघटनेसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. जेणेकरून एक 'कम्युनिटी' म्हणून आपसांत सुसंवाद, अनुभवांची देवाणघेवाण आणि प्रसंगी पालकांचे समुपदेशन या नितांत आवश्यक गोष्टी करता येतील. नवीन व्यावसायिक यंत्रसामग्री आणि अत्याधुनिक उपकरणांची कार्यशाळेला गरज आहे. जेणेकरून अधिकाधिक बहुविकलांग तरुण-तरुणींना मोफत व्यावसायिक प्रशिक्षण व कच्चा माल पुरवणे शक्य होईल. त्याचबरोबर स्व-मालकीची जागा आणि मुलांची ने-आण करण्यासाठी वाहनही आवश्यक आहे. विशेष मुलांसाठी फिजिओथेरपी आणि समुपदेशन सुविधांची गरज आहे. त्यासाठी त्या त्या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ व संस्थांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. 'शेल्टर वर्कशॉप' हा या साऱ्या सुविधांना जोडणारा दुवा ठरेल आणि मुलांचे प्रशिक्षण संपले, तरी त्यांच्या हातांना काम मिळणे सुरूच राहील. हे महत्त्वाचे आहे कारण, स्वावलंबन ही त्यांच्यासाठी केवळ पोट भरण्याची क्षमता नाही, आत्मसन्मानाची जाणीव आहे.

–निलेश पानमंद

संस्थेपर्यंत कसे जाल?

'जिव्हाळा ट्रस्ट, ठाणे' संचालित 'उभारी' मतिमंद व बहुविकलांग मुलांची कार्यशाळा ठाणे शहरातील दादोजी कोंडदेव स्टेडियमच्या गाळा क्रमांक ८ येथे नियमितपणे सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत सुरू असते. ठाणे रेल्वे स्थानकाच्या पश्चिम बाजूने बाहेर पडल्यानंतर, हे ठिकाण अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावर असून तिथे चालत जाण्यासाठी साधारण १२ ते १५ मिनिटे लागतात.

जिव्हाळा ट्रस्ट ठाणे

JIWHALA TRUST THANE

या नावाने धनादेश काढावा. धनादेशामागे किंवा त्याबरोबर देणगीदाराने आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी तसेच भ्रमणध्वनी क्रमांक लिहावा. संस्था ८० जी करसवलत पात्र आहे.

ऑनलाइन देणगीसाठी तपशील

- **बँकेचे नाव :** द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, ठाणे
- **चालू खाते क्रमांक :** ०४०१००१०१५२९७
- **आयएफएससी :** सीओएसबी००००४०

लोकसत्ता
सर्वकार्येषु सर्वदा
बँकिंग पार्टनर
कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. (मल्टिस्टेट शेड्युल्ड बँक)

धनादेश येथे पाठवा… एक हजार किंवा त्याहून अधिक रुपयांची देणगी देणाऱ्यांची नावे 'लोकसत्ता'त प्रसिद्ध केली जातील.

मुंबई कार्यालय
लोकसत्ता, संपादकीय विभाग, मफतलाल सेंटर, सातवा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई - ४०००२१, ०२२-६७४४०२५०

महापे कार्यालय
संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंड. एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई - ४००७१०. ०२२-२७६३९९००

ठाणे कार्यालय
संपादकीय विभाग, फ्लॅट नं.५, तिसरा मजला, होशबानो मॅन्शन, तनिष्क शोरूमच्या वर, गोखले रोड, नौपाडा ठाणे (प.) ४००६०२. ०२२-२५३८५१३२

पुणे कार्यालय
संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस हाउस, प्लॉट नं. १२०५/२/६, शिरोळे रस्ता, पुणे- ४११००४. ०२०-६७२४११२५

नागपूर कार्यालय
संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ३८, अॅडिसन ट्रेड सेंटर, अंबाझरी, नागपूर - ४४००१०, ०७१२ - २२३०४२१

दिल्ली कार्यालय
संपादकीय विभाग, द इंडियन एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बी१/ बी, सेक्टर १०, नॉएडा-२०१३०१. ०१२०- २०६६५१५००

कुतूहल

इअरफोन वापरावेत का?

आज इअरफोन आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग झाले आहेत. संगीत ऐकणं, फोनवर बोलणं, ऑनलाइन बैठका किंवा व्हिडीओ पाहणं यासाठी त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. पण इअरफोन सुरक्षित आहेत का, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. खरं तर याचं उत्तर त्यांच्या वापरावर अवलंबून आहे. किती वेळ, किती मोठ्या आवाजात आणि कोणत्या परिस्थितीत इअरफोन वापरले जातात यावर ते सुरक्षित आहेत की नाहीत हे ठरतं.

इअरफोनचे अनेक फायदे आहेत. आजूबाजूच्या लोकांना त्रास न देता संगीत किंवा संभाषण ऐकता येतं. ऑनलाइन शिक्षण, कार्यालयीन बैठका आणि व्हिडीओ कॉलसाठी ते उपयुक्त ठरतात. प्रवासातही ते सोयीचे असतात. 'नॉईज कॅन्सलेशन' असलेल्या इअरफोनमुळे बाहेरील गोंगाट कमी होतो. त्यामुळे कमी आवाजातही स्पष्ट ऐकता येतं आणि कानांवरील ताणही कमी होतो.

परंतु इअरफोनचा अयोग्य वापर आरोग्यासाठी हानीकारक ठरू शकतो. सतत मोठ्या आवाजात संगीत ऐकल्यानं श्रवणशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. बराच वेळ इयरबड्स कानात राहिल्यास घाम आणि ओलावा साचून जिवाणू किंवा बुरशी वाढण्याची शक्यता असते. इयरबड्स स्वच्छ न ठेवल्याने किंवा एकाचे इअरबड्स इतरांनी वापरल्याने संसर्गाचा धोका वाढतो. तसेच रस्ता ओलांडताना किंवा वाहन चालवताना इअरफोन वापरल्यास हॉर्न, सायरन किंवा इतर इशाऱ्यांचे आवाज ऐकू येत नाहीत. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता वाढते.

श्रवणतज्ज्ञ इअरफोन वापरणाऱ्यांना एक सोपा नियम सांगतात. त्याला ६०/६० नियम म्हणतात. याचा अर्थ, इअरफोनचा आवाज शक्यतो कमाल क्षमतेच्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवू नये आणि सलग ६० मिनिटांपेक्षा जास्त वापर करू नये. त्यानंतर किमान पाच ते दहा मिनिटे कानांना विश्रांती द्यावी. हा साधा नियम दीर्घकाळ श्रवणशक्ती सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतो. त्याचबरोबर नॉईज कॅन्सलेशन असलेले इअरफोन वापरणं फायद्याचं ठरतं. हे बाहेरील गोंगाट कमी करतात. त्यामुळे कमी आवाजातही संगीत किंवा संभाषण स्पष्ट ऐकू येतं आणि कानांवरील ताण कमी होतो.

दीर्घकाळ इअरफोन वापरायचे असल्यास 'ओव्हर द इअर' हेडफोन अधिक योग्य ठरतात. ते कानावर कमी दाब देतात, त्यामुळे अधिक आरामदायक असतात. तसेच त्यामध्ये कानाची स्वच्छताही तुलनेने चांगली राखली जाते. इन-इअर इअरफोन आकाराने लहान आणि सोयीचे असले, तरी दीर्घकाळ वापरासाठी ओव्हर-इअर हेडफोन हा अधिक सुरक्षित पर्याय मानला जातो.

इअरफोन वापरणं हानीकारक नाही. मात्र मोठ्या आवाजात आणि दीर्घकाळ वापरणं धोकादायक ठरू शकतं. आवाजाची मर्यादा, मर्यादित वापर, नियमित विश्रांती आणि स्वच्छता या सवयी पाळल्यास इअरफोन सुरक्षितपणे वापरता येतात.

– गिरीश घाटे
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

राजवाडे विचारविश्व

पंढरपूरची दोन पर्यायी नावे

'चौऱ्यांयशीच्या शिलालेखा'बद्दल राजवाड्यांनी जो ३८ पानी लेख १९०६ साली 'ग्रंथमाले'मधून प्रकाशित केला होता, त्यातल्या आणखी दोन रंजक नोंदींबद्दल थोडक्यात माहिती घेता येईल. पहिली नोंद होती, पंढरपूरच्या दुसऱ्या संभाव्य नावांबद्दलची. त्यांनी लिहिले, 'पंढरपुराला फागनिपूर असे दुसरे एक नाव होतेसे दिसते. 'फागनि' हे फाल्गुनि या संस्कृत शब्दाचे प्राकृत रूप आहे. फाल्गुन महिन्याला हिंदीत फागन म्हणतात. फाल्गुनि हे सध्याचे पंढरपूर व गोपाळपूर यांच्यामधील ओढ्याचे अथवा नदीचे नाव असावे. त्या ओढ्याजवळ असणारे जे गांव ते फागनिपूर. परंतु हे नाव पंढरपूर ह्या नांवापेक्षा फार जुने दिसते; इतके जुने की शक ११९५मध्ये (इसवी सन १२७३ मध्ये) प्रौढ भाषेने गांवाच्या नांवाचा उच्चार करावयाचा असला म्हणजे पंढरी, पंढरपूर ह्या सापेक्षतेने आधुनिक नावांना टाकून फागुनिपूर असे जुने अतएव प्रौढ नाव उच्चारीत व लिहीत'…

आणखी एका पर्यायी नावाबद्दलचा सप्रमाण खुलासा करीत राजवाड्यांनी पुढे लिहिले, 'बाकी शक ११९५त फागनिपुराचे लौकिक व व्यावहारिक नांव 'पंडरिगे' होते, असे म्हणण्याला आधार आहे. विठोबाच्या देवळातील सोळखांबीच्या पुढे गणपतीच्या पुढील दोन खांबांवरील एका आडव्या शिळेवर तिन्ही बाजूंनी कोरलेला एक लेख आहे व चौऱ्यांयशीच्या शिळेच्या पाचपन्नास वर्षे पूर्वीचा आहे. त्यांत श्रीविठ्ठलाचे देऊळ ज्या गावांत आहे त्याला पंडरिगे म्हणून म्हटले आहे. म्हणजे ११९५ पूर्वीपासून ह्या गांवाचे नांव पंडरिगे होते, हे उघड आहे. हिपरगे, कवलगे, बिळगे वगैरे कर्नाटकी ग्रामनामांप्रमाणेच हे पंडरिगे नांव कानडी आहे. त्यावरून 'पंडरिगे विठाबाई। मला ठाव द्यावा पायीं।' ह्या अभंगातील 'पंडरिगे विठाबाई' ह्या शब्दाचा अर्थ यथास्थित लागतो. 'पंडरिगे विठाबाई' म्हणजे पंडरिगे गांवची विठाबाई!'

राजवाड्यांनी त्या लेखात केलेली दुसरी रंजक, लक्षवेधी नोंद होती विठोबाच्या मूर्तीची विटेवरती मूळ स्थापना करणाऱ्या पुंडलीकाबद्दलची. त्यांनी लिहिले, 'ज्ञानेश्वर व हेमाद्रि यांच्याहि अगोदर पुंडलीक झाला. त्याच्या मातापित्यांची नावे शुद्ध मराठी आहेत, ती पंढरीची राहणारी होती. चौऱ्यांयशीच्या शिलेच्या अगोदरच्या एका लेखात पुंडलीकाचे नाव व विठोबाच्या मूर्तीची विटेवरती मूळ स्थापना त्याने केल्याची कथा आलेली आहे. हा अगोदरचा शिलालेख चौऱ्यांयशीच्या शिळेपूर्वी ३०-४० वर्षे खोदला गेला होता, तेव्हा जर पुंडलीकाची गोष्ट कथारूप झाली होती, तर पुंडलीकाला लौकिकांत संतपणा प्राप्त होऊन बरीच म्हणजे पाचपन्नास, कदाचित शंभरदीडशे वर्षे झाली असली पाहिजेत. पुंडलीक हा अर्वाचीन मराठी संत मंडळातला पहिला होय. 'पुंडलीकवरदे हरिविठ्ठल' हा पुंडलिकाच्या नांवाचा गजर समाराधनांतून दररोज गावगन्ना अठरापगड जातींत दुमदुमत आहे. अभंग, ओवी, आर्या, श्लोक, भूपाळी, संस्कृत शिलालेख वगैरे नाना स्थली ह्या भगवद्भक्ताचे नाव पदोपदी आढळत आहे. अशा ह्या महापुरुषाचा नेमका काल ठरविणे मात्र अगत्याचे आहे…'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

व्यक्तिवेध

दक्षिणेत, म्हैसूरमध्ये राहून हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतातील आग्रा घराण्याची शिष्यावळ तयार करणारे गानगुरू आणि गायक पंडित इंदुधर निरोदी हे पनवेलनजीक, बेलापुरात २२ सप्टेंबर रोजी निवर्तले. शास्त्रीय संगीत शिकवण्याच्या सुमारे शतकभर जुन्या 'भातखंडे पद्धती'तील 'क्रमिक पुस्तक माला' कागदावरून श्राव्य स्वरूपात 'सीडी'वर आणणारे, असा त्यांचा लौकिक होता. भातखंडे यांनी जमवलेल्या सर्व १८९६ बंदिशी २०१५ मध्ये - म्हणजे वयाची ऐंशी गाठत असताना स्वतः गाऊन, दोन डिजिटल कॉम्पॅक्ट डिस्कच्या संचात सर्व स्तरांवरल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करणे, हे कार्य मोठेच. पण त्याआधी-२०१४ सालीच त्यांना एकंदर संगीतसेवेसाठी 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार' मिळाला, इतकी महत्ता त्यांनी कमावली होती.

पं. इंदुधर निरोदी

पण कलावंत म्हणून नावाजले जाण्याऐवजी गुरू म्हणूनच त्यांची ओळख राहिली, हे खरे. उतारवयातच कारकीर्द बहरू लागल्यामुळेही असेल, पण गाण्याच्या बैठकांसाठी मोठे दौरे त्यांनी फारसे केले नाहीत. मुळात भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) नोकरी सांभाळून त्यांनी गाणे टिकवले. जन्म १९३५ सालचा, उडुपी भागातला. कर्नाटकाच्या उत्तरेकडल्या काही जिल्ह्यांत किराणा आणि आग्रा घराण्याची मुळे टिकवून ठेवणारे गायक भरपूर. दिनकर कायकिणी उडुपीचेच, पं. के. जी. गिंडे यांचे आजोळ बेळगावचे. एससीआर भट्ट शिराळीचे, चिदानंद नगरकर बेंगळूरुचे… हे सारे रातंजनकर बुवांचे शिष्य आणि या सर्वांकडून इंदुधर निरोदी शिकले. व्यासमूर्ती कट्टी, वीरभद्रय्या हिरेमठ, आदिती कायकिणी हे शिष्य इंदुधरबुवांनी तयार केले. त्यातही हिरेमठ हे बुवांच्या मागे बसणारे.

म्हैसूरला स्थायिक होण्याचा निर्णय त्यांनी २००२ मध्ये घेतला. तोवर मुंबईपासून अनेक ठिकाणी नोकरीनिमित्त राहाणे झाले होते. याच काळात 'आयटी' क्षेत्र बेंगळूरुमध्ये बहरले आणि तोवर सत्तरीला पोहोचलेले इंदुधरबुवाही यात रस घेऊ लागले. संगणक वापरायला तर शिकलेच, पण याचा वापर संगीतासाठी कसा होईल, या प्रश्नाचा पाठपुरावा करू लागले. वयाच्या पंच्याहत्तरीनंतर, साउंड फाइलचे एडिटिंग ते घरच्याघरी करू लागले. याचे फलित म्हणजे भातखंडे यांनी जमवलेल्या सर्व १८९६ बंदिशीचे सादरीकरण डिजिटल स्वरूपात करणे. आग्रा आणि ग्वाल्हेर घराणी भातखंडे पद्धतीच मानतात. 'गांधर्व महाविद्यालयां'तील शिक्षण पलुस्कर पद्धतीने, तर मुंबई/ दिल्ली/ बनारस आदी विद्यापीठांतील संगीत अभ्यासक्रम भातखंडे पद्धतीने चालतात. पण या पद्धतींमधली भिन्नता कागदावर स्वर/ श्रुतींची नोंद कशी करायची, याबद्दलचीच. इंदुधरबुवांनी सर्व रागांची, सर्व छटांची लक्षणगीते प्रत्यक्ष गाऊन हा भेदही एक प्रकारे मिटवला!

काय काय झाकणार?

'एक्स्प्रेस' वृत्ताने निवडणूक आयोगाची लाज काढली; तर न्या. दत्ता यांनी 'असा' आयोग नेमणाऱ्या सरकारची लाजिरवाणी मानसिकता सर्वोच्च न्यायालयात उघड केली...

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळातील एखादा मंत्री खुद्द पंतप्रधानांविरोधात मत नोंदवेल काय, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी विचारला आणि केंद्र सरकारच्या वकिलास लाजेकाजेस्तव 'बहुधा नाही' असे उत्तर द्यावे लागले हे किती लाजिरवाणे आहे. खरे तर निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात हा असा प्रश्न विचारण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली ही बाब विद्यमान व्यवस्थेने सर्व काही कसे खुंटीवर टांगलेले आहे हे दाखवून देते. तथापि त्यावर आपल्यातील कर्तव्यबुद्धी शाबूत असल्याचे न्या. दीपंकर दत्ता यांनी दाखवून दिले. हे दृश्य विलोभनीय. न्या. दत्ता यांच्या समोर मुद्दा होता मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आणि अन्य दोघा आयुक्तांची नेमणूक करणाऱ्या कायद्यास देण्यात आलेले आव्हान. सध्याचा कायदा २०२३ साली अस्तित्वात आला. या कायद्यातील सातव्या कलमास आव्हान देण्यात आले आहे. कारण या कलमान्वये या महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींची निवड करणाऱ्या समितीत सरन्यायाधीशांऐवजी केंद्रीय मंत्र्याचा अंतर्भाव केला गेला. म्हणजे हा बदल होण्याआधी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश या तिघांची समिती या पदांवरील नेमणुकांचा निर्णय घेत. नरेंद्र मोदी सरकारने त्यातून सरन्यायाधीशांस डच्चू दिला आणि त्या जागी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील एखाद्या मंत्र्याची वर्णी लावली. कहर म्हणजे वर शहाजोगपणे अशा बदलामुळे मुख्य वा निवडणूक आयुक्तांच्या निष्पक्ष निवडीवर काहीच परिणाम होत नसल्याचा दावा सरकार करते. जनतेच्या मूर्ख बनण्याच्या क्षमतेवर ठाम विश्वास असल्याखेरीज हे तर्कट पुढे करता येणे अवघड. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. दत्ता यांनी तेच उघडे पाडले; ही कमालीची स्वागतार्ह बाब. निवडणूक आयोग-नामे कथित घटनात्मक, सार्वभौम इत्यादी यंत्रणेचे जाहीर वस्त्रहरण होत असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयानेही आयोगाच्या ऱ्हासास जबाबदार असणाऱ्याबाबत अंगुलिनिर्देश केला ही बाब कोणाही सच्च्या लोकशाहीप्रेमीस सुखावणारी असेल. याचे कारण सांगावेही लागू नये इतके हे सामान्य ज्ञान. पण अलीकडे किमान नैतिकता आणि सामान्यज्ञानही दैवदुर्लभ झालेले असल्याने न्या. दत्ता यांच्या विधानांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने या पदांवर ज्या व्यक्तीची शिफारस केलेली आहे त्यास पंतप्रधानांच्याच हाताखाली काम करणारा एखादा दुय्यम मंत्री मुख्य आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीमध्ये कसा काय विरोध करू शकेल? यातील मुद्दा इतकाच. पण इतका साधा विचारही विद्यमान सरकारने केला नाही आणि सरन्यायाधीशांच्या सहभागास मंत्री हा पर्याय दिला. त्यामुळे या नेमणुका दोन विरुद्ध एक अशाच होणार याचा अंदाज शालेय बुद्धीधारकांसही येईल. कारण या समितीत सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात मत फक्त विरोधी पक्षनेत्याचेच असेल. त्यामुळे ते नेहमीच अल्पमतात राहतील. किंबहुना ते तसेच राहावेत याच हेतूने या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्याचा कट या सरकारने शिजवला आणि कायद्याचे स्वरूप देऊन तो अमलात आणला. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील सुनावणीत न्या. दत्ता यांनी विचारलेले प्रश्न आणि मांडलेले मुद्दे असा कट रचणाऱ्यांचे बुद्धिवैभव प्रदर्शित करतात. ''निवडणूक आयोग केवळ निष्पक्ष असून चालणारे नाही, तो तसा निष्पक्ष आहे हे सर्वांस दिसावे लागेल'', असे मत व्यक्त करून न्या. दत्ता यांनी वरील प्रश्न विचारला. न्या. दत्ता यांस विद्यमान नेतृत्वाची कार्यशैली ठाऊक आहे किंवा काय, हे कळावयास मार्ग नाही. परंतु त्यांनी ''पंतप्रधानांविरोधात मत व्यक्त करून एखादा मंत्री या समितीचे सदस्यत्व संकटात आणण्याची शक्यता नाही'', असेही निरीक्षण नोंदवले. त्यांच्या विधानाचा प्रत्यक्षातील अर्थ 'पंतप्रधानांविरोधात मत व्यक्त करून कोणता मंत्री स्वतःचे मंत्रीपद धोक्यात आणेल?', असा आहे. मुख्य आणि अन्य दोन आयुक्त निवडण्याच्या तीन सदस्यीय समितीतील दोन सदस्य तर सरकारचेच प्रतिनिधित्व करणारे आहेत; त्यामुळे त्यांचाच शब्द अंतिम ठरणार, असेही निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. त्याच बरोबर ''सध्याचा कायदा 'धारणा चाचणी'च्या मुद्द्यावर (पर्सेप्शन टेस्ट) अनुत्तीर्ण ठरतो'' हे मत व्यक्त करून, हा कायदा रदबातल करण्याची गरज त्यांनी दाखवून दिली. तथापि तसे होऊ शकणार नाही. कारण न्या. दत्ता यांच्या समवेत सदर पीठाचा भाग असलेले न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांची या मुद्द्यावर सहमती होऊ शकलेली नाही. सबब हे प्रकरण आता अधिक मोठ्या पीठाकडे सोपवले जाईल.

> 'एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानंतर केंद्र सरकारने ज्ञानेश कुमार यांच्या या अल्पमतातील निर्णयांची चौकशी जाहीर करण्याचा मोठेपणा दाखवायला हवा होता. तसे काही न करता, घेतले गेलेले निर्णयच कसे बहुमताचे होते हे दाखवण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न सरकार करत राहिले...

त्याआधी सरकारच्या वतीने या संदर्भात करण्यात आलेले युक्तिवाद उच्चपदस्थांची मानसिकता दर्शवतात. सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पंतप्रधानपदाशी सगळी घटनात्मकता कशी एकवटलेली आहे आणि त्यांच्या निर्णयावर शंका घेणे कसे अयोग्य आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तो अगदीच केविलवाणा ठरला. कारण तो अमान्य करताना न्या. दत्ता यांनी 'राज्यघटनेतील उच्च तत्त्वे' कशी अजूनही अंमलाविना पडून आहेत आणि त्यास सत्ताधीशांतील 'संविधानाधिष्ठित नैतिकता' वा तिचा अभाव (कॉन्स्टिट्यूशनल मोरॅलिटी) कसा कारणीभूत आहे हे बोलून दाखवले. विद्यमान पद्धतीत निवडले गेलेले आयुक्त तटस्थ नसतीलच असे नाही; पण त्यांची निवड पारदर्शी पद्धतीने व्हायला हवी, हे न्या. दत्ता यांचे म्हणणे नाकारणे अवघड. त्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी खेळातील पंचाची निवड एखाद्या क्रीडासंघाच्या हाती दिली आणि अंतिमतः तोच संघ विजयी ठरला तर त्या पंचाच्या प्रामाणिकपणाविषयी कसा संशय घेतला जाईल, हे उदाहरण दिले. खरे तर ही बाब इतकी सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट आहे की तिच्या समर्थनार्थ न्यायालयाचा वेळ दवडण्याचे काहीही कारण नाही. हे किमान शहाणपण. कोणाही सज्ञानाच्या ठायी असणे गरजेचे आहे. पण तरीही हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि एका तरी न्यायाधीशाने हे वास्तव मांडण्याची हिंमत दाखवली. त्याची गरज होती.

ती का, हे 'द इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्ताने उडालेली खळबळ दाखवून देते. यातही एक लबाडी अशी की मुख्य वा अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा निर्णय केंद्र सरकार दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने घेणार आणि त्याच वेळी ही निवडणूक आयोगाची यंत्रणा मात्र या बहुमताच्या तत्त्वाकडे दुर्लक्ष करून एककल्ली निर्णय घेणार. ते कसे घेतले जात होते हे 'एक्स्प्रेस'चे वृत्त दाखवून देते. या तीन-सदस्यीय आयोगातील दोघांनी विरोधी मत नोंदवूनही मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आपले घोडे दामटत राहिले. हे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर खरे तर बहुमताची इतकी चाड असलेल्या केंद्र सरकारने ज्ञानेश कुमार यांच्या या अल्पमतातील निर्णयांची चौकशी जाहीर करण्याचा मोठेपणा दाखवायला हवा होता. तसे काही झाले नाही. उलट घेतले गेलेले निर्णयच कसे बहुमताचे होते हे दाखवण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न सरकार करत राहिले. त्यामागील मानसिकता सर्वोच्च न्यायालयात जे काही घडले त्यातून दिसून येते. न्या. दत्ता त्यावर योग्य वेळी बोट ठेवतात.

हे दोन्हीही एकाच वेळी घडले; हे लोकशाहीसाठी उत्तम. 'एक्स्प्रेस' वृत्ताने निवडणूक आयोगाची लाज चारचौघांत काढली आणि न्या, दत्ता यांनी 'असा' निवडणूक आयोग नेमणाऱ्या सरकारची लाजिरवाणी मानसिकता सर्वोच्च न्यायालयात चव्हाट्यावर आणली. ते पाहिल्यावर सरकार आता काय काय आणि कसे कसे झाकणार, हा प्रश्न.

आरोग्यदायी भविष्यासाठी हवेत सक्षम औषधतज्ज्ञ

लेख

प्रा. मंजिरी घरत
symghar@gmail.com

> २५ सप्टेंबर हा जागतिक औषधतज्ज्ञ दिवस. त्यानिमित्त 'आरोग्यदायी भविष्यासाठी औषधतज्ज्ञांना सक्षम करणे' हे इंटरनॅशनल फार्मास्युटिकल फेडरेशनचे यंदाचे ब्रीदवाक्य आहे. पण सक्षम औषधतज्ज्ञ घडविण्याची व्यवस्था आपण उभी केली आहे का?

लीनाला आदल्या दिवसापासून वारंवार लघवीला जावे लागत होते. लघवी करताना जळजळ होत होती. कॅनडातील ऑन्टेरियोमध्ये कार्यालयीन प्रकल्पासाठी गेलेल्या लीनाने डॉक्टरांकडे जाण्याऐवजी जवळच्या औषधांच्या दुकानाचा रस्ता धरला. डॉक्टरांची वेळ मिळण्यास काही दिवस लागले असते. औषधतज्ज्ञांना (फार्मासिस्ट) काही ठरावीक आजारांमध्ये उपचार करण्याची परवानगी असल्याचे तिने वाचले होते. औषधतज्ज्ञांनी तिची लक्षणे, वैद्यकीय इतिहास आणि आवश्यक माहिती विचारली. मार्गदर्शक नियमांनुसार औषध दिले. औषध कसे, किती दिवस घ्यायचे, कोणती काळजी घ्यायची आणि कोणती लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांकडे जाणे आवश्यक आहे, हेही समजावून सांगितले. तीन-चार दिवसांत लीना बरी झाली. ना डॉक्टरांच्या वेळेची प्रतीक्षा, ना अनावश्यक विलंब- औषधांच्या दुकानातच योग्य वेळी योग्य मार्गदर्शन मिळाले.

समजा मुंबईत असताना तिला असा मूत्रमार्गाचा संसर्ग झाला असता तर? तर कदाचित डॉक्टरकडे ओपीडीच्या ठरावीक वेळेत जाऊन गर्दीत बराच वेळ बसावे लागले असते. वेळ आणि पैसे दोन्ही खर्च झाले असते, आणि समजा थेट औषधांच्या दुकानात जाऊन सांगितले असते तर तेथील विक्रेत्या व्यक्तीने औषध जरूर दिले असते, कदाचित प्रतिजैविकांच्या दोन गोळ्या स्ट्रीपमधून कापून दिल्या असत्या. औषध मिळाले असते, नाही असे नाही. पण दुकानातील व्यक्ती नेमकी औषधतज्ज्ञ होती का, मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे औषध आणि औषध समुपदेशन मिळाले असते का, तसे आपल्या औषधतज्ज्ञाचे प्रशिक्षण झालेले असते का असे अनेक प्रश्न तिला सतावून गेले. तेथील (कॅनडामधील) औषधांच्या दुकानामध्ये लावलेला एक फलक तिच्या नजरेत भरला 'थिंक हेल्थ, थिंक फार्मसी' लीनाला ते वाक्य भावले. भारतात हे असे का होऊ नये, असे तिच्या मनात आले. पण हा केवळ एका रुग्णाचा प्रश्न नाही. तो आपल्या संपूर्ण आरोग्यव्यवस्थेसमोर उभा असलेला प्रश्न आहे.

२५ सप्टेंबर हा जागतिक औषधतज्ज्ञ दिवस. इंटरनॅशनल फार्मास्युटिकल फेडरेशन (एफआयपी)चे यंदाचे घोषवाक्य आहे, 'आरोग्यदायी भविष्यासाठी औषधतज्ज्ञांना सक्षम करणे (एम्पॉवरिंग फार्मासिस्ट फॉर हेल्दीअर फ्युचर)' या निमित्ताने एक मूलभूत प्रश्न आपण विचारायला हवा, सक्षम औषधतज्ज्ञ घडविण्याची व्यवस्था आपण उभी केली आहे का?

जग बदलत आहे; औषधतज्ज्ञाची भूमिकाही...

कोणत्याही देशाची आरोग्यव्यवस्था परिपूर्ण नाही. कोणाला मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते आहे, कुठे आरोग्य व्यावसायिकांवरील कामाचा ताण वाढतो आहे. औषधतज्ज्ञही यास अपवाद नाहीत. मात्र अनेक देशांमध्ये यासंदर्भात एक महत्त्वाचा फरक स्पष्टपणे दिसतो. अनेक देशांमध्ये औषधतज्ज्ञांना आवश्यक शिक्षण, प्रशिक्षण, कायदेशीर अधिकार, योग्य आर्थिक मोबदला आणि प्रतिष्ठा मिळते. ते आरोग्यव्यवस्थेतील अविभाज्य घटक आहेत, ही मान्यता आहे. औषधतज्ज्ञ हे केवळ औषधांचे विक्रेते नसून ते नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध, प्रशिक्षित आणि विश्वासार्ह आरोग्य व्यावसायिक म्हणून काम करतात. किरकोळ आजारांमध्ये रुग्णांचे मूल्यमापन व उपचार करण्याची परवानगी त्यांना आहे. ते रक्तदाब, रक्तातील साखर, बीएमआय यांसारख्या तपासण्या करतात. कोविडच्या काळातही फार्मसीने कोविडचाचण्या आणि लसीकरणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. व्यसनमुक्तीसाठी उपक्रम, मुदतबाह्य औषधांचे संकलन आणि विल्हेवाट, दीर्घकालीन आजारातील औषध व्यवस्थापन अशा अनेक जबाबदाऱ्या औषधतज्ज्ञ पार पाडतो. इंग्लंडमधील 'फार्मसी फर्स्ट'सारख्या उपक्रमांमधून काही सर्वसामान्य आजारांसाठी नागरिकांनी प्रथम कम्युनिटी फार्मसीकडेच जावे असा आग्रह शासन धरते. यामागचा उद्देश डॉक्टरांची भूमिका कमी करणे हा नसून, रुग्णाला योग्य, सोयीस्कर सेवा मिळवून देऊन आरोग्यव्यवस्थेवरील अनावश्यक ताण कमी करणे हा आहे.

भारतामध्ये क्षमता आहे; पण...

कम्युनिटी फार्मासिस्ट म्हणजे समाजाभिमुख औषधतज्ज्ञ. भारतातही औषधतज्ज्ञांची क्षमता मोठी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात किमान साडेआठ लाख औषध दुकाने आहेत. अनेक वेळा रुग्ण डॉक्टरांपेक्षाही आधी औषधतज्ज्ञांकडे पोहोचतो. मग या उपलब्धतेचा सार्वजनिक आरोग्यासाठी अधिक प्रभावी वापर का होऊ नये? मात्र औषधतज्ज्ञाला सक्षम करण्यासाठी आधी सक्षम औषधतज्ज्ञ घडवावे लागतील. आजचे फार्मसी शिक्षणाचे चित्र काय आहे? एका अंदाजानुसार उर्वरित जगात मिळून चार ते पाच हजार औषधतज्ज्ञतेचा अभ्यासक्रम शिकवणारी महाविद्यालये आहेत. साधारण तेवढीच म्हणजे चार ते पाच हजार महाविद्यालये एकट्या भारतात आहेत. इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक महाविद्यालये आहेत. महाविद्यालयांची वाढलेली संख्या आणि कमी-अधिक शैक्षणिक दर्जा या साऱ्याचा रुग्णसुरक्षिततेशी संबंध आहे असा विचार कोणाच्या गावीही नसतो. कारण फार्मसी शिक्षण आणि आरोग्यव्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य यांचा एकत्रित विचार होत नाही.

घरचेच दुकान असले तर ठीक अन्यथा...

'कम्युनिटी फार्मसी' हा फार्मसी विद्यार्थ्यांमध्ये पहिला करिअर पर्याय नसतोच. कारण शिक्षण त्यांना यासाठी तयार करत नाही आणि फार्मसी प्रॅक्टिसची स्थितीही उत्साहवर्धक नाही. धंद्याच्या चढाओढीत, ऑनलाइनच्या स्पर्धेत, सवलतीच्या गदारोळात आज हा व्यवसाय त्रासला आहे. स्वयंस्फूर्तीने काम करणारे थोडेफार रुग्णमित्र 'औषधतज्ज्ञ' सोडले तर बाकी सारे बहुशः औषधविक्रीपुरते मर्यादित आहेत. दिवसरात्र औषध पुरवठा करण्याचे यांचे कामही महत्त्वाचे आहे, पण औषधविक्री हे औषधव्यवसायाचे एक प्रमुख परिमाण (डायमेंशन) आहे. अंतिम ध्येय नाही. औषधतज्ज्ञांना सक्षम करून त्यांची भूमिका विस्तारायची असेल तर त्यासाठी एक संपूर्ण साखळी मजबूत करावी लागेल. दर्जेदार शिक्षण, कौशल्याधारित प्रशिक्षण, निरंतर शैक्षणिक कार्यक्रम, अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि मर्यादा याबाबत स्पष्टता, कायद्यांची कडक अंमलबजावणी, योग्य मोबदला या साऱ्याची यासाठी आवश्यकता आहे.

औषधतज्ज्ञांसाठी फार्मसी काऊन्सिल, इंडियन फार्मास्युटिकल असोसिएशन यांनी अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले आहेत, त्याचा नक्कीच फायदा होत आहे. निदान औषधतज्ज्ञांना आपली भूमिका काय असावी कळते आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनेक आव्हाने असली तरी या दिशेने प्रयत्न काहीजण करताहेत हेही कौतुकास्पद आहे.

भारतात जीवनशैलीमुळे होणाऱ्या आजारांचे (लाईफ स्टाईल डिसिजेस) म्हणजे मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांचे प्रमाण वाढते आहे. नागरिकांचे आयुर्मान वाढले आहे. पण ते निरोगी राहिलेले नाही. हे लक्षात घेता अशा प्रशिक्षित कम्युनिटी फार्मसी सेवा महत्त्वाच्या ठरू शकतात. शासनातर्फे आरोग्यकार्यक्रम राबवले जातात. आशा सेविका, आरोग्य कर्मचारी यांच्यामार्फत मोहीम सुरू असते. त्यात इच्छुक औषधतज्ज्ञांनाही प्रशिक्षण आणि योग्य भूमिका मिळायला हवी. क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमात अनेक औषधतज्ज्ञांनी उत्तम कार्य केले होते.

लीनाला कॅनडातील औषध दुकानामध्ये मिळालेली सेवा ही केवळ एका रुग्णाची गोष्ट नाही. औषधतज्ज्ञांना सक्षम करून त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करण्यासाठी आरोग्यव्यवस्था कशी उत्सुक आहे याची ती झलक आहे. आपल्याकडेही औषधतज्ज्ञ आहेत. औषध दुकाने आहेत. गरज तर प्रचंड आहे. मग उणीव कुठे आहे? कदाचित आपल्या दृष्टिकोनात. औषधतज्ज्ञ आरोग्यसाखळीतील महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यांना सर्वतोपरी सक्षम करण्यासाठीचे बदल पद्धतशीरपणे घडवून आणले तर केवळ औषधतज्ज्ञांचे नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याचेही भवितव्य उज्वल असेल. डॉक्टर, औषधतज्ज्ञ, नर्सेस आणि इतर आरोग्य व्यावसायिकांनी आपापल्या कौशल्याच्या क्षेत्रात काम करून एकमेकांना पूरक ठरणे हीच प्रभावी आरोग्यव्यवस्थेची गरज आहे.

सर्दीच्या औषधामुळे सापडलेला उच्च रक्तदाब

औषधतज्ज्ञाला योग्य प्रशिक्षण, साधने दिली आणि त्यांची भूमिका स्पष्ट केली, तर तो आरोग्यव्यवस्थेतील महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. जीवनशैलीने होणाऱ्या आजारांचा प्रतिबंध, लवकर निदान आणि उपचार यासाठी एफआईपीतर्फे भारतात औषधतज्ज्ञांचे प्रशिक्षण करण्यात येत आहे. या उपक्रमातील हा अनुभव बोलका आहे. एक ५२ वर्षीय व्यक्ती सर्दीचे औषध घेण्यासाठी एका औषध दुकानामध्ये आली होती. प्रशिक्षित महिला औषधतज्ज्ञाने रक्तदाब तपासला. तो खूप जास्त म्हणजे १९०/१०० आला. पुन्हा तपासला, रुग्णाला न घाबरवता अधिक विचारपूस केली. त्या व्यक्तीला धूम्रपानाची सवय होती. कुटुंबात उच्च रक्तदाबाचा इतिहास होता आणि तिचे वजन वाढलेले होते. औषधतज्ज्ञाने जीवनशैलीतील बदलांबाबत मार्गदर्शन केले आणि ताबडतोब डॉक्टरांकडे जायला सांगितले. त्याप्रमाणे व्यक्ती डॉक्टरांकडे गेली आणि तिला रक्तदाबाच्या गोळ्या सुरू झाल्या. औषधतज्ज्ञाच्या जागरूक संवादामुळे हृदयविकाराचा झटका किंवा पक्षाघाताचा बळी होण्याचा धोका टाळता आला. सर्दीचे औषध देऊन विषय संपवणे ही दुकानदारकी; रुग्णाशी संवाद साधून त्याच्या आरोग्याचा धोका ओळखणे ही औषध विक्रेतीची खरी जबाबदारी. येथे औषधतज्ज्ञाने तपासणी, धोका ओळखणे, समुपदेशन, डॉक्टरांकडे पाठवणे आणि पाठपुरावा ही आपली भूमिका योग्य प्रकारे पार पाडली.

अन्वयार्थ

कानउघाडणी कानात घुमेल का?

यंदाच्या संपूर्ण उत्सवादरम्यान गाजलेल्या ध्वनिप्रदूषण या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अनंत चतुर्दशीच्या विसर्जन मिरवणुका निघण्यापूर्वी दोन दिवस काही आदेश दिले. उत्सवापूर्वी नागरिकांनी ध्वनिमर्यादाभंगाच्या विरोधात स्वयंस्फूर्तीने काढलेले मोर्चे, केलेली आंदोलने, यंत्रणांना कारवाईसाठी वारंवार दिलेली निवेदने आणि उत्सव संपता संपता आलेले उच्च न्यायालयाचे हे आदेश. ध्वनिप्रदूषण हा मुद्दा सार्वजनिक आयुष्यात किती उपद्रवी ठरतो आहे, याचे हे लक्षण. तो तडीस जावा, अशीच सार्वत्रिक अपेक्षा आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशांची चर्चा गरजेची.

आधी न्यायालयाच्या आदेशाबद्दल. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने 'स्वयंस्फूर्त' याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान फटाक्यांवर, डीजे यंत्रणेच्या 'आव्वाजा'वर, लेझर झोतांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. कारवाई म्हणून काय करायचे, तेही न्यायालयाने सांगितले. 'ध्वनिमर्यादा ओलांडणाऱ्यांची उपकरणे, वाद्ये जप्त करा', असेच हे आदेश म्हणतात. जबाबदारी निश्चतीसाठी मिरवणूक आयोजन करणाऱ्यांची नावे, पत्ते आणि मोबाइल क्रमांक मिरवणुकीत दर्शनी भागात लावणे, पोलिसांनी डेसिबल पातळी तपासणे, ध्वनियंत्रणेत ध्वनिमर्यादा यंत्र बसविणे, ध्वनियंत्रणेला परवानगी देताना परिणामांचा अभ्यास करून परवानगी देणे, अशा बाबी अनिवार्य असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

या सगळ्याबरोबरच एक महत्त्वाची टिप्पणी न्यायालयाने केली, ती म्हणजे, 'ध्वनी आणि वायू प्रदूषण न करताही सण साजरे केले जाऊ शकतात. मिरवणुका आणि उत्सव अधिक सन्मानजनक व सभ्य पद्धतीने आयोजित करणे ही काळाची गरज आहे.' कर्कशता टाळून उत्सव साजरे करा, हा याचा मथितार्थ. वास्तविक ध्वनिमर्यादाभंगाबाबत आधीपासूनच नियम असल्याची कल्पना आता सरकार-सरकारी यंत्रणांबरोबर सामान्यजनांनाही आहे. असलेल्या नियमांचे पालन करण्यात सरकार आणि त्यांच्या यंत्रणा कमी पडताहेत, हे या वेळी न्यायालयाने अधिक जोरकसपणे अधोरेखित केले, ज्याच्या परिणामांची परीक्षा आजच्या अनंत चतुर्दशीस होईलच.

या परीक्षेत यंत्रणा लगेच उत्तीर्ण होईल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. पण या निमित्ताने किमान पुढील उत्सवांपूर्वी यंत्रणा अधिक उत्तम तयारी करतील, इतकी अपेक्षा ठेवण्याइतकी तरी कामगिरी यंत्रणांनी करावी, अशी आशा. ध्वनिप्रदूषणाने ग्रासलेल्या सामान्यजनांना अशाच आशेवर राहावे लागते. ते का, याचे उत्तर न्यायालयानेच आपल्या टिप्पणीतून दिले आहे, हे या वेळच्या आदेशातील वेगळेपण.

'ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत संबंधित यंत्रणा गांभीर्य दाखवत नाहीत, नागरिकांना उत्सवकाळात ध्वनी आणि हवा प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. सरकार मात्र, 'सर्व काही ठीक चालले आहे,' असा आभास निर्माण करते.' - या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली आहे. याचा अर्थ असा की, नियमांची माहिती असूनही यंत्रणा निष्क्रिय राहते आणि ती तशी राहिली, तरी सरकार सांगते, 'ठीक चालले आहे.' आता यात यंत्रणा आपण होऊन निष्क्रिय राहते, की तसा त्यावर दबाव आणला जातो, याचे वेगळे उत्तर देण्याची गरजही नाही. परिणामी, उपद्रव चालूच राहतो. म्हणूनच प्रश्न पडतो तो असा, की उत्सवी गोंगाट चालणारच, तो नागरिकांनीही चालवून घ्यावा, त्याची एकदा सवय झाली, की ते अंगवळणी पडेल, असे सरकारला, 'ठीक चालले आहे,' या उत्तरातून सुचवायचे असते का?

या प्रश्नाचे उत्तर 'हो' असावे, इतका बेदरकारपणा उत्सवकाळात सर्वत्र दिसतो. राज्यभरात पुण्याच्या विद्यानंद बापट यांच्या निमित्ताने ध्वनिमर्यादाभंग हा विषय ऐरणीवर आला. त्याला पाठिंबाही मिळाला. लोकभावना ध्वनिवर्धकांविरोधात आहे, हेही स्पष्ट झाले. पण, प्रत्यक्षात गोंगाट कमी होताना दिसत नाही. 'उत्सव आहे, आनंदासाठी झाला जरा आवाज, तर काय एवढे' अशी उत्तरे त्यावर तयार असतात. कमी 'आव्वाजा'तही आनंद साजरा करता येतो, याचे भान संपले आहे, याचा हा परिणाम. त्यांना भानावर आणण्यासाठी असलेली यंत्रणा निष्क्रिय राहत असल्याने 'हे तर चालतेच की' असा दृढ होणारा समज ही त्याची पुढची पायरी. न्यायालयाने यावरही बोट ठेवले आहे.

अर्थात, प्रत्येक वेळी सगळाच दोष यंत्रणेचा असतो असेही नाही. कारण, कर्कशता हा आता आयुष्याचा भाग बनला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये चक्क सरकारी रुग्णालयाच्या आवारात, म्हणजे जे शांतता क्षेत्र असणे अपेक्षित आहे, तेथेच ढोल वाजवून मिरवणूक काढली गेली, हे त्याचे उदाहरण. अशा या वातावरणात आज - अनंत चतुर्दशीला - विसर्जन मिरवणुका निघतील, तेव्हा न्यायालयाने केलेल्या कानउघाडणीतील सर्व वाक्ये सरकार आणि सरकारी यंत्रणांच्या कानात घुमतील, अशी अपेक्षा तेवढी करायची.

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

'निवडक अयोग्यां'चे प्रताप

'द इंडियन एक्स्प्रेस समूहा'चे अभिनंदन करून एक गोष्ट सांगावी लागेल- धूर सर्वांना जाणवत होता, आग नेमकी कुठपर्यंत लागली आहे या समूहाने शोधून काढले. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी, यांनी काही महिन्यांपूर्वी दावा केला होता की त्यांना निवडणूक आयोगाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांचे फोन येत आहेत आणि ज्या थराला गोष्टी गेल्या आहेत त्यामुळे एक भीती निर्माण झाली आहे. त्यात तथ्य नव्हते असे आता म्हणता येणार नाही. मुळात एकूणच देशाचा बुद्ध्यांक खाली आणून, अंधभक्त निर्मितीच्या माध्यमातून आपण काहीही करू शकू या सरकारच्या गृहीतकाला अखेर धक्का बसला आहे, असे म्हणता येते. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून झालेली उघड लूट, केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रादेशिक पक्षांत पाडली गेलेली फूट आणि गुजरातस्थित पाच बोगस पक्षांनी जमवलेली अफाट माया हे सारेच विषय अतिशय गंभीर आहेत. 'लोकसत्ता'च्या अग्रलेखाने यंत्रणेच्या इंग्रजी नावाला 'कमिशन' ऐवजी 'ओमिशन'चा पर्याय दिला होताच, तसे मराठीत या आयोगाला 'निवडक अयोग्यांचा संच' का म्हणू नये?

■ **कपिल देव**

सरकारसाठी आयोग ही ढाल?

'सरकार-जीवी स्वायत्त!' हा अग्रलेख (२४ सप्टेंबर) वाचला. निवडणूक आयोग हा सरकारचा भाग नाही. ती स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे सरकार थेट आयोगाची चौकशी करू शकत नाही. मात्र गंभीर आरोप होतात तेव्हा सरकारने तटस्थ राहून न्यायालयाला किंवा स्वतंत्र तपासात मदत करणे अपेक्षित असते. थेट पाठराखण करणे योग्य नाही, पण इथे तर सरकार आयोगाची ढाल करून स्वतःलाच वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्यासारखे चित्र दिसते. हे लोकशाहीसाठी अतिशय घातक आहे.

■ **दिनेश पांथरे**, धाराशिव

दाद कोणाकडे मागावी?

'सरकार - जीवी स्वायत्त' हा अग्रलेख वाचला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह संपूर्ण आयोगाच्या यंत्रणेविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जावी. न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या आधारे चौकशी करण्यात यावी. आणि एका स्वतंत्र न्यायालयीन खंडपीठापुढे या सर्वांची चौकशी करण्यात यावी. स्वायत्त मुख्य निवडणूक आयोगाची पुनर्स्थापना सुधारित तरतुदींसह करावी. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेतली नाही तर सर्व विरोधी पक्षांनी रस्त्यावर उतरावे. अर्थात कुंपणच शेत खात असल्यामुळे दाद कोणाकडे मागावी, हा प्रश्नच आहे.

■ **विश्वजित मिठबावकर**, कल्याण

विरोधकांकडून अपेक्षा व्यर्थ

'सरकार-जीवी स्वायत्त!' (२४ सप्टेंबर) या अग्रलेखात विरोधी पक्षांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, परंतु अनेक पक्ष 'उप' पदे मिळवून सत्ताधीशांचे अंकीत झाले आहेत. त्यांनी आपले झेंडे गुंडाळून ठेवलेत, काहींचे न्यायालयात जमा आहेत. काही नेते कुठलाही पक्ष सत्तेत येवो, आपला झेंडा घेऊन सत्तेत सहभागी होतात. श्रमिक कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यांवर उतरणारे 'लाल बावटे' आज दुर्बीण, भिंग लावून शोधावे लागतील. त्यामुळे विरोधकांकडून अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

■ **गो. पि. लांडगे**, धुळे

धावपळ कशासाठी?

'सरकार-जीवी स्वायत्त!' (२४ सप्टेंबर) हा अग्रलेख वाचला. गेली दोन वर्षे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याभोवती निर्माण झालेले संशयाचे धुके आता अधिक गडद झाले आहे. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त घटनात्मक संस्थेच्या अंतर्गत कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर ही बाब केवळ राजकीय वाद म्हणून झटकून टाकता येणार नाही. त्यातही आयोगाच्या बचावासाठी भाजपला एवढे आकांडतांडव वा धावपळ करण्याची गरज का भासावी, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोग लोकशाहीचा पहारेकरी आहे. त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर त्याची झळ संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेला बसते. त्यामुळे राजकीय पक्षाने आयोगाचा बचाव करण्यापेक्षा आयोगाने स्वतःच्या पारदर्शकतेने आणि निष्पक्षतेने आपली विश्वासार्हता सिद्ध करणे हीच खरी गरज आहे.

■ **दिलीप कदम**

प्रेरणा

खुश रहना और संतुष्ट रहना युवा बने रहने के सर्वश्रेष्ठ तरीके हैं। - चार्ल्स डिकेंस

संपादकीय

ट्रम्प ने चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ क्यों स्थगित किया?

राष्ट्रपति ट्रम्प का शी जिनपिंग के स्वागत में कुछ ज्यादा 'मोटी लाल-कालीन बिछाना', पाकिस्तान में चुने हुए पीएम से ज्यादा फील्ड मार्शल को तरजीह देकर पारिवारिक बिजनेस करना और तुर्किये के अधिनायकवादी शासक एर्दोगन की यूएन पटल से प्रशंसा करना भारत के लिए चिंता का विषय है। सवाल यह नहीं कि बहु-पक्षीय दोस्ती में खोट है। समस्या यह है कि तीनों देश ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति वैमनस्यता दिखाते रहे हैं। जिन तर्कों के आधार पर ट्रम्प ने चीन और भारत सहित कुछ देशों पर 100% टैरिफ लगाने की कानूनी शक्ति हासिल की, वे आज भी कायम हैं। फिर क्यों चीन के खिलाफ 100% टैरिफ को अगले साल जनवरी तक स्थगित कर दिया गया? क्या चीन ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? इसका कारण है कि ट्रम्प की हेकड़ी केवल कमजोरों पर चलती है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और इटली यह समझ गए। जैसे ही वे तन कर खड़े हुए, ट्रम्प को नाटो को धमकाने, कनाडा को यूएस में शामिल करने जैसा राग धीमा करना पड़ा। चीन ट्रम्प की मजबूरी है, क्योंकि दुनिया में 90% रेयर-अर्थ की सप्लाई उसके ही पास है। सोयाबीन और मक्का किसान ट्रम्प के प्रमुख वोटर्स हैं और चीन इन उत्पादों का प्रमुख खरीदार। लेकिन क्या 'मोटी लाल-कालीन' भावशून्य जिनपिंग को लचीला बना पाएगी?

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

हम शास्त्रों से काम की बात निकाल कर बच्चों को सौंपें

शास्त्रों को शुद्ध रखना कठिन काम है। अपने-अपने समय में लोग इनमें घट-जोड़ करते रहेंगे और जरूरी नहीं है कि यह काम विद्वान ही करें। जिसमें जितनी अक्ल होगी, वह शास्त्रों को वही रूप दे देगा। एक शास्त्र है गीता। इसके साथ खूब प्रयोग हुआ, खूब व्याख्याएं की लोगों ने। लेकिन जिसको गीता समझ में आई, वह उसमें कुछ नहीं जोड़ता। क्योंकि, उसका मानना है कि जो मिल गया, वही मिलना था। और जो मिलना था, वह मिल गया तो फिर क्या घट-जोड़। यहां हम एक खेल का उदाहरण लें- वॉलीबॉल। 'वॉली' शब्द का अर्थ है प्रहार करके उछालना। लोगों ने शास्त्रों के शब्दों के साथ अपनी विद्वता को लेकर वॉलीबॉल खेलना शुरू किया और अधिकांश शास्त्रों के साथ यही हो रहा है। उनके शब्दों को समझने, जीने की जगह बस उछाला जा रहा है। इसीलिए नई पीढ़ी शास्त्रों से दूर हो रही है। उनका कहना है, इतना क्लिष्ट हो गया है सबकुछ कि हमें समझ नहीं आता। तो हम अपने शास्त्रों में घट-जोड़ करने की जगह जो काम की बात है वो निकालें और अपने बच्चों को सौंपें। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

डिफ्रेंट एंगल • कास्ट पहचान की दीवार नहीं बने

जहां जात से कोई छोटा नहीं, मेरा आदर्श भारत है वही...

समरसता

रश्मि बंसल

लेखिका और स्पीकर

mail@rashmibansal.in

मेरे पिताजी साइंटिस्ट थे, और मैं बंबई में पली-बढ़ी। हमारी कॉलोनी में हर तरह के लोग थे- बंगाली, मराठी, साउथ इंडियन। मेरी पढ़ाई भी ऐसे स्कूल में हुई, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई- सब साथ पढ़ते थे। मिल-जुल कर रहना हमारे लिए आम बात थी।

हां, मेरे पड़ोसी सांभर खाते हैं, और हम अरहर की दाल। लेकिन यह तो अच्छी बात है ना? वो अपने घर पर हल्दी-कुमकुम रखते हैं, और जन्माष्टमी पर मेरे घर पर सजती है झांकी। यह हुई ना बात। घर पर हम अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं और बाहर अंग्रेजी, कोई वाद-विवाद नहीं।

औरों का खान-पान, भेष, बोली या धर्म मुझसे अलग होना आम बात है। यही बंबई शहर की खासियत थी। जबकि स्मॉल टाउन में रहने वाले मेरे रिश्तेदारों को आश्चर्य होता था। क्योंकि उस वक्त उन्हें इतना एक्सपोजर नहीं था। वो एक दायरे के अंदर, 'अपने जैसों' के बीच बंधकर रहते थे।

शायद मैं बारह साल की थी, जब मैं ट्रेन से सफर कर रही थी और किसी ने मुझसे पूछा- तुम्हारा कास्ट क्या है? अब स्कूल में पढ़ा तो था कि चार कास्ट होते हैं और पापा से डिस्कस भी किया था कि हमारा कास्ट कौन-सा है। लेकिन मेरे मन में था कि कास्ट तो एक ऐतिहासिक मामला है, आज के इंडिया में इसका क्या लेना-देना।

खैर, वो मेरी मासूमियत समझिए या बुद्धूपन। मुझे सचमुच जात-पात, भेदभाव का कोई एहसास नहीं था। हमारे घर पर कामवाली आती थी, शायद उनका कास्ट हमसे अलग होगा, लेकिन इसका जिक्र मेरे घर पर कभी हुआ नहीं। हम 'बेस्ट' बस में अकसर जाते थे, बगल में कौन बैठा है किसे पता।

क्या मैं अपने खयालों की आदर्श दुनिया में रहती थी? जब मंडल कमीशन ने ओबीसी कोटा की घोषणा की और दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने बवाल खड़ा किया, तब पता चला कि यह देश का एक अहम मुद्दा है। उस समय मेरी सोच थी कि रिजर्वेशन सही नहीं है, सीट उसे मिलनी चाहिए जो अव्वल नंबर लाए।

आज मैं दोनों तरफ से सिचुएशन को देख सकती हूं, समझ सकती हूं। एक लेखक होते हुए मुझे दूर-दराज क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनीं। ओडिशा में कंधमाल जिला हो या छत्तीसगढ़ का बस्तर, विकास तो हुआ है, लेकिन अब भी बहुत काम बाकी है।

गांव-कस्बे में कास्ट का दबदबा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अगर यहां के होनहार बच्चों को लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले तो रिजर्वेशन का सही उपयोग है। जब इन परिवारों में से कोई एक बाहर की दुनिया में कदम रखेगा तो उनके पूरे समाज को प्रेरणा मिलेगी। एक आशा जगेगी।

इन्हीं बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। ताकि पांचवीं क्लास से एक माहौल मिले, वो तालीम मिले, जिससे वो अपने बल पर आगे बढ़ पाएं। लेकिन क्या यह काफी है? शायद नहीं। कास्ट का लेबल कभी-कभी बच्चे की साइकी पर बोझ बन जाता है। आत्मविश्वास को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है।

इस संदर्भ में मैंने इंस्टाग्राम पर एक अजूबा अकाउंट देखा, जिसका नाम है @चमारस्टूडियो। सुधीर राजभर इस कम्युनिटी से आते हैं, जो कभी चमड़े का काम करते थे, अछूत माने जाते थे, लेकिन सुधीर राजभर ने उलटा किया।

मैं इस कम्युनिटी से हूं, मुझे गर्व है, वो कहते हैं।

एक लेखक होते हुए मुझे दूर-दराज क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनीं। ओडिशा में कंधमाल जिला हो या छत्तीसगढ़ का बस्तर, विकास तो हुआ है, लेकिन अब भी बहुत काम बाकी है।

हमें अपने हाथों से काम करना आता है और यह काम बढ़िया है। उन्होंने कई सारे कारीगरों को जोड़कर एक कंपनी खोली है, जो अव्वल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि हैंडबैग, फर्नीचर इत्यादि। उनकी एक फेमस कुर्सी है, जो पॉपस्टार रिहाना ने भी पसंद की है। और हां, वो चमड़े का नहीं, रबर के पुराने टायर और कैनवास के मिश्रित मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दुनिया में आज वीगन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। सुधीर राजभर को आज एक आर्टिस्ट और इनोवेटर के रूप में जाना जाता है। उनकी अपनी एक पहचान है, कोई हीनभावना नहीं।

कहने का मतलब यह कि जो दबे हुए हैं, उन्हें अच्छे घरों के बच्चों से कॉम्पीट करने में मदद मिलनी चाहिए। लेकिन आईआईटी-आईईएम-आईएएस के आगे भी दुनिया है। सुधीर राजभर ने अपनी कास्ट को अपनी पहचान की दीवार नहीं, अपनी पहचान का हिस्सा बनाया। जहां जात से कोई छोटा नहीं, मेरा आदर्श भारत वही।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

नजरिया • फूड पैकेट पर चेतावनी सही, लेकिन...

स्वस्थ भारत लेबल से ही नहीं, बेहतर खाद्य व्यवस्था से बनेगा

हेल्थ

डॉ. चन्द्रकांत लहारिया

जाने-माने चिकित्सक और 'पिल-फ्री' किताब के लेखक

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों के सामने चेतावनी लेबल लगाने की दिशा में प्रगति हुई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने प्रस्ताव दिया है कि जिन खाद्य पदार्थों में चीनी, नमक या संतृप्त वसा अधिक हो, उनके पैकेट के सामने लाल षट्कोण में 'हाई शुगर', 'हाई साल्ट' या 'हाई फैट' जैसी चेतावनी लिखी जाए। उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि वह जो खरीद रहा है, उसमें स्वास्थ्य के लिए चिंता पैदा करने वाले तत्व कितनी मात्रा में हैं।

अभी किसी बिस्किट, नमकीन, खाद्य या पेय की पैकिंग के सामने बड़े अक्षरों में 'हाई प्रोटीन', 'मल्टीग्रेन', 'नेचुरल' या 'विटामिन युक्त' लिखा होता है, जबकि चीनी, नमक और वसा की जानकारी पीछे छोटे अक्षरों में छिपी रहती है। सामान्य ग्राहक मार्केट में खड़े होकर पोषण तालिका का गणित नहीं करता। इसलिए पैकेट के सामने चेतावनी उपभोक्ता के अधिकार का प्रश्न है। कनाडा में जनवरी 2026 से ऐसे पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर सामने स्पष्ट प्रतीक अनिवार्य हैं, जिनमें संतृप्त वसा, शुगर या सोडियम तय सीमा से अधिक है। चिली, मैक्सिको और कई अन्य देशों ने भी चेतावनी-आधारित मॉडल अपनाए हैं। चिली में 2016 में चेतावनी चिह्न लागू होने के बाद मीठे पेयों की खरीद में गिरावट देखी गई। जब जानकारी साफ और तुरंत समझ आने वाली हो, तो वह व्यवहार को प्रभावित कर सकती है।

लेकिन प्रस्ताव में कमियां भी हैं। पहले चरण में चेतावनी तभी लगाने की बात है जब तीन चिंताजनक पोषक तत्वों में से कम से कम दो निर्धारित सीमा से अधिक हों। इस प्रावधान के साथ समस्या है, जैसे कि अत्यधिक चीनी वाला कोई उत्पाद केवल इसलिए चेतावनी से बच जाए क्योंकि उसमें नमक और वसा कम हैं। सिद्धांत सरल होना चाहिए- यदि चीनी अधिक है तो चीनी की चेतावनी, नमक अधिक है तो नमक की, और संतृप्त वसा अधिक है तो उसकी। चेतावनी इतनी बड़ी और स्पष्ट हो कि खरीदते समय दिखाई दे।

यह भी याद रखना होगा कि अभी प्रस्ताव कानून नहीं बना है। भारत में फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग पर चर्चा एक दशक से चलती रही है। अनेक मसौदे, समितियां और परामर्श हुए, लेकिन अंतिम निर्णय टलता रहा। ऐसे उपाय अनिश्चितकालीन विचार-विमर्श में नहीं फंसने चाहिए। उद्योग को बदलाव के लिए उचित समय मिले, पर समयसीमा स्पष्ट हो। फिर भी चेतावनी लेबल को बढ़ते मोटापे और अस्वस्थ खान-पान की जादुई दवा समझना गलती होगी। भोजन का चुनाव कीमत, उपलब्धता, विज्ञापन, आदत, परिवार, स्वाद और सामाजिक परिवेश से तय होता है। जिस बच्चे को दिन भर विज्ञापनों में जंक फूड दिखाया जा रहा हो, उसके लिए पैकेट का लाल निशान पर्याप्त नहीं होगा।

इसलिए समाधान समग्र होना चाहिए। अस्वस्थ खाद्य विज्ञापनों पर कड़े नियम हों, स्कूलों के आसपास स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो, मीठे पेयों और अत्यधिक अस्वस्थ उत्पादों पर कर जैसे उपायों पर विचार हो, कंपनियों को उत्पादों में नमक, चीनी और वसा घटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और फल, दाल, दूध, मोटे अनाज तथा कम-प्रोसेस्ड भोजन को सुलभ बनाया जाए। पोषण शिक्षा जरूरी है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उपभोक्ता पर डालना अनुचित है। लेबल के साथ ऐसी नीतियां भी चाहिए जो उद्योगों को स्वास्थ्यकर उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करें।

भारत में फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग पर चर्चा एक दशक से चलती रही है। अनेक मसौदे, समितियां व परामर्श हुए, लेकिन अंतिम निर्णय टलता रहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऐसे उपाय अनिश्चितकालीन विचार-विमर्श में नहीं फंसने चाहिए।

फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी न तो खाद्य उद्योग के खिलाफ अभियान है, न यह तय करती है कि कोई खाद्य पदार्थ कभी खाया ही न जाए। इसका उद्देश्य इतना है कि खरीद का फैसला भ्रम या चमकदार विज्ञापन के बजाय स्पष्ट जानकारी के साथ हो।

इसलिए हमें दो अतियों से बचना चाहिए- यह कहना कि लेबल सब बदल देगा और क्योंकि वह सब नहीं बदल सकता, इसलिए उसकी जरूरत नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में अकसर परिणाम किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि कई छोटे और सही कदमों के साथ आने से बनते हैं। भारत को इसे स्पष्ट, मजबूत और शीघ्र लागू करना चाहिए। साथ ही समझना चाहिए कि स्वस्थ भारत केवल बेहतर लेबल से नहीं, बेहतर खाद्य व्यवस्था से बनेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

26 सितंबर के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में

इकोनॉमिस्ट ने मुख्य खबर में मिडिल ईस्ट से अमेरिका की वापसी की संभावनाओं का विश्लेषण किया है। स्मार्ट ग्लास का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजनाओं पर स्पेशल स्टोरी भी की है।

The Economist

दैनिक भास्कर

अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

ऑस्ट्रेलिया में डेटा सेंटरों पर 15 लाख करोड़ रु. होंगे खर्च

ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनाने की तैयारी है। निवेशकों की इन पर करीब 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इससे अधिक निवेश केवल अमेरिका (178 लाख करोड़) और चीन (28.25 लाख करोड़) में हो रहा है। अमेरिका में डेटा सेंटरों के बढ़ते विरोध के बीच ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को में एआई कंपनियों से चर्चा की। 16 सितंबर को एंथ्रोपिक ने ऑस्ट्रेलिया में 2.16 गीगावाट क्षमता का बिजलीघर लीज पर लेने का समझौता किया।

डेनमार्क ने नाटो देशों पर रूसी हमले की चेतावनी दी

डेनमार्क की विदेशी खुफिया एजेंसी ने नाटो देशों पर रूस के छोटे हमले का खतरा बताया है। एजेंसी का कहना है, रूस, यूक्रेन की मदद करने वाले बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है या पड़ोसी देशों की सीमा पर सैनिक तैनात कर सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में बड़े हमले की संभावना बहुत कम बताई गई है। पिछले सप्ताह पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि रूस का इरादा यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर ड्रोन या मिसाइल हमले करने का है। इसके बाद वह दावा करेगा कि ये हमले दुर्घटनावश हो गए।

चीन ने अमेरिका को दो बड़े पांडा देने का एलान किया

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से वार्ता के बाद बताया कि दो भीमकाय पांडा जल्द ही अटलांटा स्थित जू में पहुंचेंगे। पिंग पिंग और फू शुआंग नामक नर, मादा का जोड़ा उन चार पांडा की जगह लेगा जो 2024 में यूएस से चीन लौट गए हैं। चीन लंबे समय से दुर्लभ और खूबसूरत प्राणी पांडा को कूटनीति के तहत मित्र देशों को अस्थायी तौर पर देता है। जब संबंधित देश से रिश्ते बिगड़ते हैं तब पांडा वापस ले लिए जाते हैं जैसा कि जनवरी में जापान के साथ हुआ है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

समरनीति • अमेरिका सैनिकों और सैन्य अड्डों की मौजूदगी घटाने की तैयारी में, सीरिया-इराक से वापसी जारी

मिडिल ईस्ट से पीछे हट रहा अमेरिका, ईरान तुर्किये और इजरायल यहां बढ़ा सकते हैं प्रभाव

अमेरिका के मध्य-पूर्व से अपनी सैन्य मौजूदगी घटाने की संभावना बढ़ रही है। हाल के कुछ संकेत बताते हैं कि वह मध्य-पूर्व और यूरोप में तैनात सैनिकों की संख्या कम कर सकता है और लैटिन अमेरिका तथा एशिया पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है।

अमेरिका मध्य-पूर्व क्षेत्र में अपने सैन्य अड्डों के आकार और मौजूदगी की भी समीक्षा कर रहा है। बहरीन और कतर में उसके बड़े सैन्य अड्डों को लेकर समीक्षा चल रही है, जबकि सीरिया और इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी जारी है। हालांकि मध्य-पूर्व से पीछे हटने के बावजूद अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की तरह क्षेत्र से पूरी तरह अलग नहीं होगा। वह अपने हितों के लिए, खासकर आतंकवाद विरोधी अभियानों में, जरूरत पड़ने पर सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसकी प्रमुख भूमिका खत्म हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से ईरान को लेकर कड़े बयानों के बावजूद अमेरिकी वापसी के संकेत मिल रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन में हूतियों पर हमला करने से इनकार किया। इसके बजाय उसने हूतियों से अमेरिकी जहाजों पर हमले रोकने को लेकर अलग बातचीत की। 2013 में सीरिया में संघर्ष रोकने में नाकामी और खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया की कमी ने भी उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। अमेरिका के पीछे हटने पर ईरान, तुर्किये और इजरायल क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। वहीं ईरान इराक, सीरिया और लेबनान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, जबकि तुर्किये अरब देशों से संबंध मजबूत कर रहा है। उसने पिछले महीने पाकिस्तान और सऊदी अरब से सुरक्षा समझौते किए। इजरायल ने अब्राहम समझौते के तहत यूएई के साथ करीबी रिश्ते बनाए हैं। इन तीनों शक्तियों के बीच स्थायी शांति की संभावना कम मानी जा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव अरब देशों पर पड़ सकता है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था धन और कारोबार पर केंद्रित है, जिसके लिए लंबे समय से अमेरिकी सुरक्षा महत्वपूर्ण रही है। अमेरिका की वापसी उन्हें अधिक स्वतंत्र भूमिका का अवसर दे सकती है, लेकिन पुराने विवाद और दुश्मनी बनी रहेगी।

यूरोप से 40 हजार तक सैनिकों की वापसी के आसार

एनबीएस टीवी ने खबर दी है कि अमेरिका यूरोप से भी अपने 25 हजार से 40 हजार सैनिकों को हटा सकता है। ट्रम्प प्रशासन का फोकस लेटिन अमेरिका सहित उत्तर अमेरिका पर है। सुरक्षा विशेषज्ञ चीन से बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से अमेरिका को तैयार रखना चाहते हैं। इस सप्ताह ट्रम्प-शी जिनपिंग की वार्ता ने बताया है कि दोनों देशों की होड़ एक-दूसरे के अस्तित्व के प्रति सतर्कता और खुली आक्रामकता के बीच झूल रही है।

अमेरिका की तेल पर निर्भरता घट गई है

सवाल है, मिडिल ईस्ट में रहने से अमेरिका को क्या मिलेगा? 2020 तक अमेरिका तेल का आयातक था। आज वह बड़े पैमाने पर तेल निर्यात करता है। अब उसकी तेल पर निर्भरता घट गई है। पहले भारी तेल आयात के कारण उसकी क्षेत्र में दिलचस्पी थी। वहीं अब चीन खाड़ी देशों के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है। स्वेज नहर से उसका माल यूरोपीय बाजारों में पहुंचता है। फिर भी चीन के मिडिल ईस्ट पर हावी होने की संभावना नहीं है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

जीवनस्तर

जापान में भी गरीबी, बच्चों को स्कूलों में मुफ्त खाना

जापान को दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में वहां 11% बच्चे अपेक्षाकृत गरीबी में जी रहे थे। इन बच्चों के परिवारों की खर्च करने योग्य आय राष्ट्रीय मध्यम आय के आधे से भी कम, यानी करीब 16.76 लाख रुपए (17,500 डॉलर) थी। 2020 के बाद से खाद्य पदार्थों की कीमतों में 30% वृद्धि ने कम आय वाले परिवारों की मुश्किल बढ़ा दी है। कई परिवारों में प्रति व्यक्ति रोज का भोजन खर्च 335 रु. से भी कम रह गया है। गरीब बच्चों को स्कूलों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मियोशी शहर में एनजीओ उस्नोवा ने ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें अग्रिम ऑनलाइन भुगतान के जरिए कम आय वाले परिवारों के बच्चे बिना पहचान जाहिर किए मुफ्त भोजन ले सकते हैं। जापान में एकल-अभिभावक परिवारों में गरीबी दर 44.7% है, जो ओईसीडी के अमीर देशों में सबसे अधिक दरों में शामिल है। करीब 90% एकल माताएं काम करती हैं, लेकिन ज्यादातर कम वेतन और अनियमित नौकरियों में हैं। तलाक के 90% मामलों में बच्चों की जिम्मेदारी माताओं को मिलती है। सेव द चिल्ड्रन जापान के सर्वे में खाद्य सहायता मांगने वाले करीब 90% लोगों ने महंगाई को इसकी वजह बताया।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

टेक्नोलॉजी • विवाद के बावजूद 6 महीनों में 42 लाख स्मार्ट ग्लास की सप्लाई

पेन, रिंग्स और बैग जैसे रूपों में आएंगी एआई डिवाइस

स्मार्ट ग्लासेस के गुप्त वीडियो बनाने और लोगों के उत्पीड़न में इस्तेमाल होने के मामले आने के बावजूद टेक कंपनियों ने इनका उत्पादन बंद नहीं किया है। इसके उलट मेटा और अन्य बड़ी कंपनियां इस तकनीक को और आगे बढ़ा रही हैं। मेटा और एसिलॉर-लक्सोटिका के 'रे-बैन मेटा' ग्लासेस को ऐसे मामलों के बाद 'परवर्ट ग्लासेस' यानी विकृत चश्मे तक कहा जाने लगा है। प्राइवेसी की चिंता के बीच स्मार्ट ग्लासेस का पता लगाने के लिए 'नियरबाई ग्लासेस' और 'जक ऑफ' जैसे ऐप बनाए गए हैं। ये ब्लूटूथ सिग्नल के जरिए आसपास मौजूद डिवाइस का पता लगाते हैं।

टेक फर्म ओम्डिया के अनुसार, इस साल जून तक छह महीनों में एआई स्मार्ट ग्लासेस की वैश्विक सप्लाई दोगुने से अधिक बढ़कर 42 लाख यूनिट हो गई। हालांकि दुरुपयोग रोकने के लिए कंपनियां कुछ कदम भी उठा रही हैं। मेटा ने रिकॉर्डिंग एलईडी से छेड़छाड़ होने पर कैमरा बंद करने और नियम तोड़ने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने जैसे उपाय किए हैं। कंपनी ने पहला बिना कैमरे वाला 'रे-बैन वीडियो' मॉडल भी पेश किया है, जिसमें उसका व्यक्तिगत एआई एजेंट 'म्यूस' शामिल है। मेटा वर्ष के अंत तक 100 स्मार्ट-ग्लास मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। स्नैप ने एआर ग्लासेस लॉन्च किए हैं, जबकि चीन में अलीबाबा, शाओमी और आईएनएमओ तेजी से बाजार बढ़ा रहे हैं। मेटा की वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 81% है। हालांकि, एआई एजेंट्स को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए कैमरों की जरूरत बनी रहेगी। ऐसे में एआई ग्लासेस के बढ़ते इस्तेमाल के साथ निगरानी और प्राइवेसी की चुनौतियां भी बनी रहने की संभावना है।

हेल्थ केयर और इंडस्ट्री में जगह बना सकते हैं स्मार्ट ग्लास

क्वैलकॉम कंपनी का मानना है कि एआई डिवाइस केवल चश्मों तक सीमित न रहकर पेन, पेंडेंट, रिंग्स और बैग जैसे अन्य रूपों में भी आएंगे। क्वैलकॉम को उम्मीद है कि अनब्रांडेड स्मार्ट ग्लास फैशन, हेल्थ केयर, शिक्षा और इंडस्ट्री में जगह बना लेंगे।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

शिक्षा • दुनियाभर के स्कूली छात्रों का टेस्ट

मैथ्स और साइंस में चीनी छात्र अव्वल, रीडिंग में सिंगापुर के छात्रों से पिछड़े

2025 के स्कूली छात्रों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) में चीन के 15 वर्षीय छात्रों ने मैथमैटिक्स और साइंस में दुनिया में पहला स्थान हासिल किया, जबकि रीडिंग में वे सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि, इस परीक्षा में पूरा चीन शामिल नहीं था। सिर्फ बीजिंग, शंघाई, जिआंगसू और झेजियांग के छात्रों ने हिस्सा लिया।

करीब 20 करोड़ आबादी वाले इन चारों क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 9.30 लाख रुपए सालाना है, जो चीन के राष्ट्रीय औसत से 60% अधिक है। इसलिए इनका प्रदर्शन पूरे चीन का प्रतिनिधित्व नहीं करता। विश्व बैंक और 'द इकोनॉमिस्ट' के आय और परीक्षा परिणामों के संबंध पर किए विश्लेषण के अनुसार, पूरा चीन शामिल होता तो उसका अनुमानित मैथ्स स्कोर 579 रहता, अभी 612 है। हालांकि, महामारी और तकनीक के असर से वैश्विक स्तर पर छात्रों के प्रदर्शन में गिरावट को ध्यान में रखते हुए समायोजन करने पर चीन का अनुमानित मैथ्स स्कोर 536 होता। इस आधार पर वह दुनिया में चौथे स्थान पर रहता। तीनों विषयों का औसत अनुमानित स्कोर 501 होता, जिससे चीन सातवें स्थान पर रहता। इसके बावजूद तीनों विषयों में उनका प्रदर्शन मजबूत रहा। आंकड़ों के आधार पर पूरा चीन भी अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

भास्कर एनालिसिस 18.5% टैक्स से सोना आयात घटा; सप्लाई कम, त्योहारों में और बढ़ सकती हैं कीमतें

भारत में सोना दुनिया के मुकाबले 9% महंगा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

इस साल मई से आयात शुल्क बढ़ने के बाद भारत में सोना वैश्विक कीमतों के मुकाबले करीब 9% महंगा हो गया है। इससे आधिकारिक आयात में तेज गिरावट आई है। नतीजतन मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ सकता है। ऐसे में सोने की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार को देश में 24-कैरेट सोने की औसत कीमत 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जो गुरुवार की तुलना में 1,328 रुपए ज्यादा है। दरअसल सरकार ने 13 मई से सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% से 10% और कृषि सेस 1% से 5% कर दिया है। इसमें जीएसटी मिलाकर कुल प्रभावी टैक्स 18.5% हो गया है, जो पहले 9.2% था। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट कहती है कि इसके चलते सोने के मासिक आयात में मई से लगातार गिरावट आ रही है, जबकि कीमतें फरवरी से ही लगभग स्थिर हैं।

भारत में सोने का आधिकारिक आयात और सप्लाई घटने के असर ऐसे समझें...

त्योहारों में सोना खरीदारों पर

घरेलू बाजार में सोना और महंगा हो सकता है। इसके स्पष्ट कारण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 18.5 फीसदी भारी-भरकम टैक्स के चलते सोने का आधिकारिक आयात लगातार घट रहा है। इससे सप्लाई जरूरत से कम रह सकती है। दूसरी तरफ त्योहारों में सोने की मांग बढ़ने की संभावना है।

मौजूदा टैक्स ढांचा		कोटक का सुझाव	
सीमा शुल्क	जीएसटी	सीमा शुल्क	जीएसटी
15%	3%	05%	08%
केंद्र-राज्यों को कुल आय (करोड़ में)		केंद्र-राज्यों को कुल आय (करोड़ में)	
₹1,24,300		₹1,30,800	

टैक्स ढांचा बदले तो सरकार को सीधे ₹6,500 करोड़ का फायदा

निवेशकों पर...कीमतें बढ़ने पर निवेश भी बढ़ने का ट्रेंड

गोल्ड ईटीएफ में निवेश इसका साफ संकेत दे रहा है। 2025 की दूसरी छमाही में दाम बढ़ने पर ईटीएफ में निवेश तेजी से बढ़ा था, लेकिन फरवरी 2026 के बाद कीमतें स्थिर रहने से निवेश घट गया। यदि आगे दाम बढ़ते हैं तो निवेश भी बढ़ेगा। केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया ने कहा कि सोने में तेजी की बुनियादी वजहें अब भी मौजूद हैं।

देश की अर्थव्यवस्था पर... सरकार का घाटा कम होगा

सोना आयात घटने से चालू खाता घाटा कम होता है। कोटक ने 2026-27 में यह घाटा जीडीपी का 1.2% रहने का अनुमान लगाया है। लेकिन यदि कारोबार अनौपचारिक तरीकों (जैसे तस्करी) से बढ़ा, तो सरकार को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी से आय का नुकसान होगा। लेकिन यदि आयात शुल्क तर्कसंगत बनाया गया तो सरकार की आय बढ़ेगी।

ऐतिहासिक रुझानः आयात शुल्क बढ़ने के कुछ समय बाद बढ़ती है मांग

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक, पहले भी जब-जब सोने पर शुल्क (ड्यूटी) बढ़ा है, आयात में शुरुआती गिरावट के बाद धीरे-धीरे रिकवरी देखी गई। यानी मौजूदा गिरावट अस्थायी भी हो सकती है। यदि सरकार ड्यूटी में राहत देती है, तो देश में सोने मांग तेजी से बढ़ भी सकती है।

मांग बढ़ सकती है

सोने के सालाना आयात में उछाल लगभग तय

वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का कुल आयात 72 अरब डॉलर (₹6.9 लाख करोड़) का रहा था। कोटक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 88 अरब डॉलर (₹8.4 लाख करोड़) के सोना आयात का अनुमान लगाया है। यानी मासिक गिरावट के बावजूद सालाना आधार पर आयात बिल बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की संभावना है।

महंगाई बढ़ाएगी सोने की मांग, स्थिरता टूटेगीः केडिया

केडिया के मुताबिक, भारत समेत दुनियाभर में महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में डॉलर मजबूत होने के बावजूद निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ेगी। ऐसे में बाजार की स्थिरता टिकने की संभावना कम है। कीमतों में तेजी का रुझान जल्द लौट सकता है।

एविएशन • सिर्फ 4 साल पहले आई कंपनी स्पर्धा बढ़ाएगी

अकासा एयर 200 विमानों का ऑर्डर देने की तैयारी में

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

देश की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन अकासा एयर 200 से ज्यादा बोइंग 737 मैक्स विमानों के ऑर्डर की तैयारी कर रही है। इससे एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा तेज होने और किराया कम होने के आसार हैं।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अकासा की नई डील पर फैसला अगले साल की शुरुआत में होने की उम्मीद है। शर्तें 2027 की दूसरी छमाही में तय होंगी। यह ऑर्डर अकासा के बेड़े को 2032 के बाद भी बढ़ाने में मदद करेगा। 2022 में शुरू हुई मुंबई की इस बजट एयरलाइन के पास फिलहाल 43 बोइंग 737 मैक्स विमान हैं। अगले एक दशक की डिलीवरी के लिए 226 और विमानों का ऑर्डर पहले से दिया जा चुका है। अकासा ने मार्च 2027 तक क्षमता 30% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी योजना में शामिल होने पर भी विचार कर रही है।

92% बाजार पर कब्जा सिर्फ 2 एयरलाइन का... डीजीसीए आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 65%, जबकि एयर इंडिया ग्रुप की 26.7% रही। यानी 91.7% बाजार हिस्सेदारी सिर्फ दो कंपनियों के पास है। इनके मुकाबले अकासा एयर की हिस्सेदारी 5.5% ही रही। नए बड़े ऑर्डर से अकासा इंडिगो और एयर इंडिया के दबदबे को चुनौती देगी।

तीन साल में सिर्फ स्पाइसजेट की बाजार हिस्सेदारी घटी, एअर इंडिया की स्थिर

एयरलाइन	अक्टूबर-23	अगस्त-26	बढ़ी/घटी
इंडिगो	62.6%	65%	▲2.4 पीपी
एअर इंडिया	27%	26.7%	लगभग स्थिर
अकासा एयर	4.2%	5.5%	▲1.3 पीपी
स्पाइसजेट	5%	1.2%	▼3.8 पीपी

नोटः पीपी मतलब पर्सेंटेज पॉइंट, स्रोतः डीजीसीए

विस्तार पर जोरः भारतीय एयरलाइंस के कुल ऑर्डर 2,426 विमान तक पहुंच जाएंगे

एविएशन ए2जेड के मुताबिक, इंडिगो अकेले दुनिया में किसी भी एक एयरलाइन के सबसे बड़े ऑर्डर बुक की मालिक बन चुकी है। इसमें करीब 1,400 विमान शामिल हैं। वहीं एअर इंडिया विहान डॉट एआई प्रोग्राम के तहत करीब 600 विमानों के ऑर्डर दे चुकी है।

नोटः अकासा एयर के आंकड़े में उन 200 विमानों के ऑर्डर शामिल हैं, जिनकी बातचीत चल रही है।

इतने बड़े ऑर्डर बुक के दम पर भारत दुनिया के सबसे बड़े विमान-खरीदार बाजारों में शुमार हो चुका है।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा का दिलचस्प असर... डेली एयरफेयर ट्रैकर के मुताबिक, 2026 में भारत में घरेलू किराए में साफ बंटवारा दिखा है। देश के 20 सबसे व्यस्त रूटों में से 18 पर इकोनॉमी किराया बढ़ा है, जबकि इन्हीं में से 16 रूट्स पर बिजनेस क्लास का किराया घटा है।

उपलब्ध सीट आय 12% घटी....आंकड़ों से संकेत मिले हैं कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कमजोर मांग के चलते घरेलू यात्रियों से विमानन कंपनियों की प्रति उपलब्ध सीट आय तिमाही आधार पर 12% घट गया था।

बिजनेस ब्रीफ

टाटा मोटर्स कारों के दाम फिर 5% तक बढ़ाएगी

मुंबई | इनपुट लागत बढ़ने से आगामी दिनों में टाटा मोटर्स की कारें 5% तक महंगी हो सकती हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी-सीईओ शैलेश चंद्रा शुक्रवार को कहा कि उत्पादन लागत बढ़ने से मार्जिन पर दबाव है। हालांकि, मांग पर असर न पड़े इसके लिए कीमतें छोटी किस्तों में बढ़ाई जाएंगी। कंपनी ने सितंबर में भी दाम बढ़ाए थे, लेकिन बढ़ती इनपुट लागत के कारण फिर दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है।

एलआईसी से वीआरएस, पंत अब इरडा के मेंबर

नई दिल्ली | एलआईसी के एमडी दिनेश पंत ने 37 साल की सर्विस के बाद गुरुवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले ली।

अब सरकार ने उन्हें बीमा नियामक इरडा में होल-टाइम मेंबर (एक्चुअरी) नियुक्त किया है। वे पूरे बीमा सेक्टर में जोखिम प्रबंधन की निगरानी करेंगे। उनके साथ न्यू इंडिया एश्योरेंस की पूर्व सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यन को भी इरडा का मेंबर बनाया गया है।

डाबर-सेसा केयर के मर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी

नई दिल्ली | डाबर इंडिया को आयुर्वेदिक हेयर केयर ब्रांड सेसा केयर के मर्जर के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। डाबर ने अक्टूबर, 2024 में सेसा केयर की मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीदी थी। मई, 2025 में विलय की योजना बनाई गई थी। शेयरधारकों और लेनदारों की सहमति के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस मर्जर से डाबर को हेयर केयर पोर्टफोलियो और नेटवर्क मजबूत करने में मदद मिलेगी।

नियम बदले तो एनएसई की सेल्फ-लिस्टिंग संभव

मुंबई | एनएसई के चेयरमैन श्रीनिवास इनजेटी ने कहा कि नियमों में बदलाव के साथ भविष्य में एक्सचेंजों की सेल्फ-लिस्टिंग संभव है। लेकिन नियामकी जिम्मेदारियों की रक्षा कमर्शियल हितों से ऊपर रहेगा, पर अंतिम फैसला सेबी का होगा। प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बीएसई पर एनएसई की लिस्टिंग के बाद उन्होंने ये राय दी। मौजूदा नियम स्टॉक एक्सचेंज को अपने ही प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग की अनुमति नहीं देते हैं।

क्रेज • शंघाई में 10 घंटे में बिके 3.8 करोड़ के कैरेक्टर खिलौने

जापानी कार्टून सीरीज चीकावा में नौकरियों के संघर्ष की कहानी... इससे जुड़े सामान पर युवा हर महीने ₹24,400 तक खर्च कर रहे

टोक्यो/शंघाई | जापान का मासूम दिखने वाला कार्टून कैरेक्टर 'चीकावा' बड़ा ग्लोबल बिजनेस ब्रांड बन गया है। शंघाई के एक स्टोर ने महज 10 घंटों में इस कैरेक्टर से जुड़े खिलौने-सामान की 3.8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री की। जापानी आर्टिस्ट नागानो ने 2020 में एक्स (ट्विटर) पर यह कार्टून सीरीज शुरू की थी, जिसके आज 55 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दिखने में प्यारा यह कैरेक्टर अपनी कार्टून फिल्मों में युवाओं में नौकरी को लेकर संघर्ष, कठिन परीक्षाओं और जीवन की कड़वी सच्चाइयों को दर्शाता है। एशिया में 18.9% बेरोजगारी और पढ़ाई के तनाव से जूझ रहे युवा इसमें अपनी जिंदगी देखते हैं। इसी वजह से फैंस हर महीने इसके सामान पर ₹24,400 तक खर्च कर रहे हैं। अब कैरेक्टर मैनेजमेंट कंपनी स्प्राइलक्यूट इसे अमेरिकी बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है।

दो कंपनियों ने लगाए दांव

आईडीबीआईः हिस्सेदारी बेचने आगे बढ़ी सरकार

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

सरकार और एलआईसी आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक हिस्सेदारी बेचने के लिए मिली बोलियों का मूल्यांकन कर रही हैं। दिग्गज निवेशक प्रेम वत्स की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल और दुबई की एमिरेट्स एनबीडी ने जुलाई में संशोधित बोलियां जमा की थीं। दोनों बोलीदाताओं को गृह मंत्रालय से सिक्युरिटी क्लीयरेंस और आरबीआई से 'फिट एंड प्रॉपर' की मंजूरी मिल चुकी है। सैमको सिक्युरिटीज के रिसर्च हेड अपूर्व शेठ के मुताबिक, सरकारी बैंक का निजीकरण लंबी अवधि में निवेशकों के लिए फायदेमंद रहता है। सरकार लंबे समय से आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने का प्रयास कर रही है। अब देखना है कि यह डील कब तक पूरी होती है। अभी सरकार के पास 45.48% और एलआईसी के पास 49.24% मिलाकर कुल 94.71% हिस्सेदारी है। केंद्र 30.48% और एलआईसी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी।

रिकवरी • शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग से तेजी

बैंक, ऑयल-गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो शेयरों में तेजी के चलते सेंसेक्स 315 अंक चढ़ा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

शेयर बाजार में शुक्रवार को रिकवरी आई। ब्लू-चिप बैंकिंग, ऑयल-गैस और ऑटो शेयरों में वैल्यू बाइंग से बाजार संभल गया। सेंसेक्स 315 अंक चढ़कर 73,896 पर और निफ्टी 77 अंकों की तेजी के साथ 23,140 पर बंद हुआ। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि अब मजबूत घरेलू लिक्विडिटी (मार्केट में कैश) शेयर बाजार में बड़ी गिरावट रोकेगी।

विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी

एमएंडएम, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक और टाइटन के शेयरों में तेजी रही। गुरुवार को सेंसेक्स 1,248 अंक और निफ्टी 384 अंक टूट गए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बीते हफ्ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बाजार में गिरावट का रुझान देखा गया था। इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में कुछ कमी आई, लेकिन बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण बेंचमार्क इंडेक्स नीचे फिसल गए। लार्जकैप की तुलना में मिडकैप शेयरों में ज्यादा गिरावट आई।

उपलब्धि • पहले मोबाइल फोन मंगाते थे, अब बेच रहे

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 39% बढ़ा, इसमें 60% समार्टफोन

सुरजीत दास गुप्ता | नई दिल्ली

देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात इस साल सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर बन गया है। स्मार्टफोन की मजबूत मांग ने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया।

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, अप्रैल-अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 39.4% बढ़कर 26.66 अरब डॉलर (₹2.55 लाख करोड़) तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 19.08 अरब डॉलर (₹1.83 लाख करोड़) था। इसमें अकेले स्मार्टफोन की हिस्सेदारी करीब 60% रही। यह बढ़ोतरी इसलिए अहम है क्योंकि इसकी रफ्तार दूसरे नंबर पर मौजूद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की निर्यात वृद्धि से भी थोड़ी ज्यादा रही।

प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में हम आयातक से निर्यातक बने

इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) रही, जो ₹13,993 करोड़ तक पहुंच गई। इसमें सालाना आधार पर 2,913% बढ़ोतरी हुई। यानी यह सेगमेंट, जो पहले लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर था, अब तेजी से घरेलू उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है।

टॉप-10 इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 53% उछाल... इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉप-10 श्रेणियों में कुल निर्यात 53.4% बढ़कर 21.97 अरब डॉलर (₹2.1 लाख करोड़) हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 14.39 अरब डॉलर (₹1.4 लाख करोड़) थी।

भास्कर नॉलेज | इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात क्यों बढ़ा?

2021 में शुरू हुई स्मार्टफोन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के बाद से भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात लगातार बढ़ रहा है। मध्य-2025 में शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से अब पुर्जों और सब-असेंबली का निर्यात में योगदान बढ़ने लगा है।

सबसे बड़े खरीदार देश कौन हैं? भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 19.8% रही, इसके बाद यूएई (6.3%) और चीन (4.5%) का स्थान रहा। भारत का कुल वस्तु निर्यात अप्रैल-अगस्त में 17.85% बढ़कर 215.91 अरब डॉलर (₹20.7 लाख करोड़) तक पहुंच गया।

टोक्यो दुनिया का टॉप शहर

लग्जरी घरः मुंबई पूरी दुनिया में आठवें नंबर पर

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

मुंबई में लग्जरी घर खरीदना अब और महंगा हो गया है। नाइट फ्रैंक के मुताबिक, 2026 की दूसरी तिमाही में शहर में लग्जरी घरों के दाम सालाना 6.2% बढ़ गए। इसके साथ ही यह दुनिया के टॉप-10 प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट में 8वें नंबर पर पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 46 शहरों के वैश्विक औसत 2.6% से दोगुने से भी ज्यादा है। बेंगलुरु 4.5% बढ़त के साथ 12वें और दिल्ली 4% तेजी के साथ 17वें स्थान पर है। टोक्यो में दाम रिकॉर्ड 50.7% बढ़े और पहले टॉप पर रहा।

सख्ती • 2026 बैच के छात्रों को दिए 150 से ज्यादा जॉब ऑफर पूरे नहीं करने पर एक्शन

आईआईटीः ओरेकल समेत 22 कंपनियों पर कैंपस भर्ती की रोक

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

देश के सभी 23 आईआईटी ने 22 कंपनियों के साथ अगले दो साल कैंपस भर्ती में सहयोग बंद करने का फैसला किया है। इन कंपनियों ने 2026 बैच के छात्रों को दिए 150 जॉब ऑफर पूरे नहीं किए। आईआईटी की साझा प्लेसमेंट कमेटी (एआईपीसी) 30 सितंबर तक इन कंपनियों को चिट्ठी भेजकर बताएगी कि वे दो प्लेसमेंट सीजन में कैंपस भर्ती नहीं कर सकेंगी। कमेटी ने इसे 'ब्लैकलिस्ट' नहीं 'नॉन-कोऑपरेशन' यानी असहयोग की कार्रवाई कहा है।

ऑफर देकर भर्ती न करने वाली कंपनियों में ओरेकल सबसे आगे

- अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल ने करीब 40 ऑफर पूरे नहीं किए, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा इंटरव्यू किकस्टार्ट, सुपर एजीआई और कई स्टार्टअप्स भी लिस्ट में शामिल हैं।
- पूरी 22 कंपनियों की लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है। जोस के मुताबिक ओरेकल ने इस साल अब तक आईआईटी से भर्ती के लिए संपर्क ही नहीं किया। कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
- ओरेकल इन दिनों बड़े पैमाने पर पुनर्गठन कर रही है। कंपनी ने हाल ही में बताया था कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के चलते इस साल पुनर्गठन की लागत बढ़कर करीब ₹26,836 करोड़ तक पहुंच सकती है, जिसमें छंटनी शामिल है।

पहले भी 10 से ज्यादा कंपनियों को मिल चुकी चेतावनी... जून में एआईपीसी ने समेत समेत 10 से ज्यादा कंपनियों को कहा था कि वे या तो ऑफर पूरा करें या छात्रों को 3 महीने की सैलरी बतौर मुआवजा दें। तब करीब 100 छात्र प्रभावित थे। कंपनियों को 15 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया, फिर 15 सितंबर तक छात्रों को जॉइन कराने की डेडलाइन दी गई। लेकिन नतीजा नहीं निकला, तो एक्शन लिया गया।

20-30% प्रभावित छात्रों को दूसरी जगह नौकरी मिली... आईआईटी-गुवाहाटी के प्रोफेसर और एआईपीसी के संयोजक जॉन जोस के मुताबिक, करीब 20-30% छात्रों को दूसरी जगह नौकरी मिल चुकी है। पिछले साल 10-11 कंपनियां ऑफर पूरा नहीं कर पाई थीं।

योजना • नई कार बनाने का समय 48 से घटाकर 24 महीने करेगी

चीन से होड़, दोगुनी तेजी से कारें बनाएगी सुजुकी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्प कार डेवलपमेंट का समय आधा करने की योजना बना रही है। सीईओ तोशीहिरो सुजुकी के मुताबिक, कंपनी दशक के अंत तक डेवलपमेंट अवधि 40-48 महीने से घटाकर 24 महीने करना चाहती है। चीनी कंपनियों की तेज गति का मुकाबला करने के लिए यह कदम जरूरी है। सुजुकी भारत को मुख्य विकास इंजन मानती है और 2030 तक यहां उत्पादन क्षमता 40 लाख यूनिट तक बढ़ाने की योजना है। तोशीहिरो सुजुकी ने टोक्यो में कहा कि चीनी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए रफ्तार बढ़ानी होगी। 2012 में अमेरिका और 2018 में चीन से निकलने के बाद सुजुकी भारत को सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट मानती है।

चुनौती • चीनी ब्रांड्स से मिल रही कड़ी टक्कर

बीवाईडी, शाओमी जैसी चीनी कंपनियां सॉफ्टवेयर-फर्स्ट डिजाइन, लेटेस्ट बैटरी तकनीक और कम डेवलपमेंट टाइम से नया बेंचमार्क बना रही हैं। इसी वजह से पारंपरिक ऑटो कंपनियों को काम का तौर-तरीका बदलना पड़ रहा है।

एसबीआई कार्ड्स • खर्च वृद्धि एक तिहाई रह गई

क्रेडिट कार्ड 9.5% बढ़े, खर्च बढ़ने की दर घटकर 5.5%

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

क्रेडिट कार्ड से खर्च की रफ्तार अगस्त में धीमी पड़ गई, जबकि नए कार्ड जारी होने की गति तेज बनी रही। इस बीच एसबीआई कार्ड्स की बाजार हिस्सेदारी में साफ गिरावट देखी गई। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड खर्च में सालाना बढ़ोतरी घटकर अगस्त में 5.5% रह गई, जो जुलाई में 7.1% थी। दूसरी तरफ इसी बीच जारी कार्ड्स की संख्या 9.5% बढ़ गई। सबसे बड़ा झटका एसबीआई कार्ड्स को लगा। इसके खर्च की रफ्तार जुलाई के 22% से घटकर सिर्फ 7% रह गई।

सर्कुलेशन • चार बड़े बैंकों की कार्ड ग्रोथ 8-9%

बैंक/कंपनी	अगस्त-25	अगस्त-26	बढ़ा/घटा
एचडीएफसी बैंक	250	271	+8%
एसबीआई कार्ड्स	213	230	+8%
ICICI बैंक	182	198	+9%
एक्सिस बैंक	153	163	+6%
कोटक महिंद्रा बैंक	46	49	+7%
इंडसइंड बैंक	32	30	-7%
इंडस्ट्री (कुल)	1121	1227	+10%

07% घट गई एक्सिस बैंक से नए कार्ड जारी होने की रफ्तार। अन्य बैंकों की बढ़ी।

नोटः आंकड़े लाख में

खर्चः इंडसइंड से खर्च में 50% की भारी कमी आई

बैंक/कंपनी	अगस्त-25	अगस्त-26	बढ़ा/घटा
एचडीएफसी बैंक	5.39	6.13	+14%
ICICI बैंक	3.45	3.23	-6%
एसबीआई कार्ड्स	3.31	3.53	+7%
एक्सिस बैंक	2.18	2.30	+6%
इंडसइंड बैंक	0.94	0.47	-50%
कोटक महिंद्रा बैंक	0.56	0.68	+21%
इंडस्ट्री (कुल)	19.11	20.17	+5.50%

नोटः आंकड़े करोड़ रुपए मे, स्रोतः रिजर्व बैंक, जेफरीज

बिजनेस एंकर देश का हेयर-कलर बाजार 7,390 करोड़ का; अब नए रंगों का ट्रेंड, ₹15 का छोटा पैक बना ग्रोथ का जरिया

बालों की सफेदी छिपाने का दौर खत्म, फैशन स्टेटमेंट बना हेयर कलर

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश में अब बालों की सफेदी छिपाने का दौर खत्म हो गया है। हेयर कलर फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। बीते चार साल (जून 2022 से जून 2026) में 6.5 करोड़ नए परिवार इस बाजार से जुड़े हैं। अब लोग उम्र छिपाने के बजाय नए लुक और ट्रेंड के लिए बाल रंग रहे हैं। यह बदलाव दिखाता है कि भारतीय उपभोक्ता केवल जरूरत के बजाय जीवनशैली और पसंद जाहिर करने की ओर बढ़ रहे हैं। आसान इस्तेमाल, 15 रुपए के छोटे पैकेट और फैशन शेड्स नए खरीदारों को खींच रहे हैं। कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म वर्ल्डपैनल के 80 हजार परिवारों की ट्रैकिंग पर आधारित आंकड़ों के मुताबिक, इस बीच देश में हेयर कलर की पहुंच 51.5% से बढ़कर 65% तक पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म यूरोमॉनिटर की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय बाजार 2020 के ₹4,330 करोड़ से बढ़कर 2025 में ₹7,390 करोड़ तक पहुंच गया। 2030 तक जिसके 9,020 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है।

सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि नई डिमांड जनरेट करने वाला जरिया

फैशन कलर ब्रांड पैराडाइज की फाउंडर युषिका जॉली के मुताबिक, ऑनलाइन वीडियो देखकर युवा फौरन नया लुक अपना रहे हैं। यह रुझान दिखाता है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि नई डिमांड जनरेट करने वाला जरिया बन चुका है। मार्केट इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म ट्रैक्सन के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में पैराडाइज की कमाई 182% बढ़कर ₹39.4 करोड़ हो गई, जबकि मुनाफा ₹5.3 करोड़ रहा।

गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (जीसीपीएल) के सीईओ आसिफ मालबारी के मुताबिक, प्रीमियम हेयर कलर पोर्टफोलियो इस बाजार का विस्तार कर रहा है। वहीं लोरियल ग्रुप के सीईओ निकोलस हिरोनिमस के मुताबिक, गार्नियर और लोरियल पेरिस ब्रांड्स का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इस बीच बाजार में क्रीम आधारित रंगों की पहुंच 15.3% से बढ़कर 34.5% हो गई है, जबकि पारंपरिक मेहंदी 9.4% से बढ़कर 11% तक पहुंच पाई है। ये आंकड़े बताते हैं कि ग्राहक अब टिकाऊ और तुरंत असर वाले विकल्प अपना रहे हैं। वर्ल्डपैनल के साउथ एशिया कमर्शियल डायरेक्टर मनोज मेनन का कहना है कि क्रीम से जल्दी और सटीक नतीजे मिलते हैं।

जीसीपीएल की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 15 रुपए के पैकेट बड़ी बिक्री दिला रहे है। 40 ग्राम से छोटे क्रीम पैक की पैठ 0.6% से बढ़कर 19.4% हो गई है। केवल ग्रामीण भारत में ही हेयर कलर खरीदने वाले परिवार 9.6 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो चुके हैं। स्ट्रीक्स और वासमोल बनाने वाली हाइजीनिक रिसर्च की एसवीपी प्रियंका पूरी के कहती है कि पहले खरीद सिर्फ जरूरत से तय होती थी, लेकिन अब युवा शादियों और त्योहार में नए लुक के लिए रंग आजमा रहे हैं। छोटे शहरों में ब्यूटी ट्रेंड्स अब एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री का मुख्य इंजन बन रहे हैं।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

ट्रंप और शी का मिलना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। एक अच्छी आवाज, जो दोनों नेताओं की भेंट से उपजी है, वह दुनिया में हर कान तक पहुंचनी चाहिए। अमेरिका और चीन कमोबेश इस बात पर सहमत दिखे हैं कि दोनों को परस्पर होड़ करना है, मगर लड़ना नहीं है। ये दोनों महाशक्तियां अगर परस्पर लड़ाई का मौका न आने दें, तो यह दुनिया पर मेहरबानी होगी। दोनों देश गाहे-बगाहे साम्राज्यवादी मनसूबे का इजहार करते रहते हैं। ऐसे में, दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है कि दोनों देश एक-दूसरे की राह में न आ जाएं। दोनों अगर कभी और कहीं न लड़ें, तो यह सुखद बात है। इसी कड़ी में यह भी जोड़ने की जरूरत है कि दोनों महाशक्तियों की यह जिम्मेदारी है कि वे दुनिया में देशों को परस्पर न लड़ने दें। दुनिया के अनेक युद्धों या छद्मयुद्धों में इन दोनों देशों का प्रत्यक्ष या परोक्ष हाथ होने का युग अब लद जाना चाहिए। दोनों देश अगर मिलकर काम करेंगे, तो संयुक्त राष्ट्र भी ठीक से कार्य कर सकेगा और दुनिया में अमन-चैन की बहाली होगी।

बहरहाल, शी जिनपिंग का अमेरिका में जिस तरह स्वागत हुआ है, वह गौरतलब है। पिछले 64 वर्षों में किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाशिंगटन पहुंचने वाले किसी विदेशी नेता का हवाई अड्डे पर इस तरह स्वागत नहीं किया था। इसी साल चीन में ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ था, लेकिन ट्रंप ने भव्यता में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जाहिर है, खुद को फिर महान बनाने की कोशिश कर रहा अमेरिकी प्रशासन चीन के व्यापक महत्व को समझता है। वैसे, यात्रा के तमाम मकसद पूरे नहीं हुए हैं, दोनों देश अपनी-अपनी नीतियों से डिगे नहीं हैं, लेकिन मित्रता का प्रदर्शन ऐतिहासिक ढंग से हुआ है और इसके संदेश को कोई भी समझ सकता है। दुनिया जानती है, दोनों देशों के बीच पिछले साल आर्थिक युद्ध-विराम हुआ था, जो इस वर्ष नवंबर में खत्म होने वाला था। शी जिनपिंग की इस यात्रा से आर्थिक युद्ध-विराम का समय बढ़ गया है। चीन की इच्छा इसे ट्रंप के पूरे कार्यकाल तक बढ़वाने की थी, लेकिन अमेरिका दो महीने के विस्तार के लिए ही तैयार हुआ है। अमेरिका और चीन को अब 10 जनवरी तक का वक्त मिल गया है। दोनों को स्थायी आर्थिक युद्ध-विराम के लिए राजी होना चाहिए।

चीनी राष्ट्रपति की अमेरिका यात्रा के कुछ ही मकसद पूरे हुए हैं, दोनों देश अपनी-अपनी नीतियों से डिगे नहीं हैं, लेकिन मित्रता का प्रदर्शन भव्यता से हुआ है।

स्वागतयोग्य है कि दोनों देशों के बीच तालमेल बेहतर होता दिख रहा है। वैसे, यह देखने वाली बात होगी कि दो महाशक्तियों के बीच होने वाला तालमेल अन्य देशों को कहीं नुकसान न पहुंचाने लगे। यहां विशेष रूप से एआई पर दोनों देशों का रुख एक मिसाल है। दोनों देश खुद को एआई के मामले में आगे मान रहे हैं और उनकी इच्छा एआई को अपने-अपने ढंग से नियंत्रित करने की है। ध्यान रहे, नियंत्रण की ऐसी इच्छा ही असंतोष और संघर्ष को जन्म देती है। अधिकार जमाने की इच्छा ही हमें युद्ध तक पहुंचाती है। दोनों देशों को ज्यादा संवेदनशील और व्यावहारिक होना पड़ेगा। यह मानकर चलना चाहिए कि बड़े मामलों में दोनों देशों का परस्पर सहमत होना आसान नहीं है। बताया जा रहा है, पहले दिन दोनों देशों के बीच घोषित एकमात्र नया समझौता यह हुआ कि चीन अटलांटा के एक चिड़ियाघर को दो बड़े पांडा भेंट करेगा। निस्संदेह, दुनिया को छोटे के साथ बड़े समझौतों की भी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए शायद और इंतजार करना पड़ेगा। भारत को हमेशा की तरह सतर्क रहना होगा, ताकि चीन या अमेरिका के साथ स्वतंत्र रूप से संबंध निभाते हुए किसी तरह का नुकसान न हो।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 26 सितंबर, 1951

मुद्गल प्रकरण

मुद्गल प्रकरण पर पटाक्षेप हो गया। श्री मुद्गल भारतीय संसद के सदस्य थे। प्रधानमंत्री के पास उनके आचरण के सम्बन्ध में कतिपय गम्भीर शिकायतें पहुंची थीं। प्रधानमंत्री ने अनुभव किया कि यदि श्री मुद्गल के विरुद्ध की गयी शिकायतों में सचाई हो, तो इनका आचरण ऐसा मानना होगा जो भारतीय संसद के किसी भी सदस्य के लिए शोभास्पद नहीं माना जा सकता। अतः उनके प्रस्ताव पर भारतीय संसद ने संसदीय सदस्यों की एक जांच कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी के सामने जो भी गवाही प्रस्तुत हुई, उसके फलस्वरूप वह इस नतीजे पर पहुंची कि श्री मुद्गल का आचरण व्यावहारिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से आपत्तिजनक था। श्री मुद्गल को पूरा अवसर प्राप्त था कि वह उनके विरुद्ध पेश की गयी गवाही का साधार खण्डन करते अथवा बचाव में अपनी ओर से निर्विवाद गवाही पेश करते। उन्होंने जो भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, यह इतना लंगड़ा था कि उनकी निर्दोषिता को प्रमाणित नहीं कर सकता था। जांच कमेटी के सदस्य प्रामाणिक व्यक्ति थे और उनकी श्री मुद्गल से कोई व्यक्तिगत शत्रुता न थी। जांच कमेटी का निर्णय सर्वांश में श्री मुदगल के विरुद्ध रहा।

इसी सोमवार को संसद के सामने प्रधानमन्त्री ने एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि संसद जांच कमेटी के इन निष्कर्ष को स्वीकार करती है कि श्री मुद्गल का आचरण संसद की प्रतिष्ठा को गिराने वाला है और उस मापदण्ड के अनुकूल नहीं है, जिसकी संसद अपने सदस्यों से आशा करती है। प्रस्ताव में यह निश्चय भी प्रकट किया गया था कि श्री मुद्गल को संसद से बहिष्कृत कर दिया जाये। प्रधानमंत्री ने संसद को बताया कि किस प्रकार श्री मुद्गल ने संसद का सदस्य निर्वाचित होते ही करीब दो सौ व्यापारिक फर्मों को एक गश्ती पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपने को संसद में उनका प्रवक्ता बताया था, हालांकि वह किसी व्यवसायी निर्वाचन क्षेत्र से नहीं चुने गये। इसके बाद उन्होंने सोना-चांदी के व्यापारियों की एसोसियेशन से सौदा पटाया। उन्होंने एसोसियेशन का प्रचार और प्रकाशन करने, मंत्रियों से मुलाकातों की योजना तैयार करने और अन्य प्रकार से संसदीय सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक बड़ी रकम की मांग की और कुछ हजार रुपये वसूल भी किया।

बिहार के जमुई में एक किशोरी के उत्पीड़न का घिनौना वीडियो क्या वायरल हुआ, ऐसे मामलों की जैसे झड़ी-सी लग गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बलात्कार की दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आई हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या समाज में दुस्साहसी लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? महिला सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए क्या कुछ करने की दरकार है? पेश है, इस ज्वलंत मुद्दे पर दो विचार :

आमने-सामने

लड़कियों की असुरक्षा के लिए तंत्र जिम्मेदार

यहां स्कैन करें

प्रोमिला शंकर | पूर्व आईएएस अधिकारी

- समाज के पश्चिमीकरण से हमारे संस्कारों और मूल्यों में गिरावट आई है।
- आज भी माता-पिता को अपने बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए।
- 'मेरा शरीर, मेरी मर्जी' वाली सोच हमारी संस्कृति नहीं है।

बिहार से लेकर राजधानी दिल्ली तक लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और बलात्कार की कई घटनाओं ने एक बार फिर पूरे देश में महिला सुरक्षा के विषय को सुर्खियों में ला दिया है। जाहिर है, इस पर समाज में रोष है और लोग (खासकर बच्चियां, महिलाएं) इस स्थिति से जल्द से जल्द निजात चाहते हैं।

सवाल है, ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं। पश्चिमी प्रभाव व समाज के पश्चिमीकरण के कारण हमारे संस्कारों और मूल्यों में गिरावट आई है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी वारदातें नहीं होती थीं, लेकिन हमारे समाज की मजबूत नैतिक नींव ने काफी हद तक इन पर लगाम लगाए रखी। गांवों में हरेक लड़के और लड़की को यही सिखाया-समझाया जाता कि सभी आपस में भाई-बहन हैं। अगर कभी कोई ऐसी गलत बात सामने आती थी, तो पंचायतें तुरंत सक्रिय हो जाती थीं, जिसमें दोषी व्यक्ति का गांव बहिष्कार कर देता था। आज भी माता-पिता को अपने बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए।

देश में नैतिक मूल्यों में हर तरह से गिरावट आई है। सोशल मीडिया के फायदे के साथ-साथ कुछ नुकसान भी हैं। आज किशोरों-युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन-इंटरनेट हैं। ऐसी कई आपत्तिजनक सामग्रियां उन तक पहुंच रही हैं, जो उनके दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। परिवार भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं। पैसे के लिए वे कुछ भी अनैतिक करने को तैयार हैं। ऐसा कई बार होता है, जब आपराधिक मामलों में भी आरोपी पैसे का लालच देता है और पुलिस समझौता कराने को तैयार हो जाती है। वह मजबूत केस नहीं बनाती। आपने ऐसे भी कई मामले सुने होंगे, जब कोई पीड़िता दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई और पुलिस स्टेशन में उन लोगों द्वारा ही उसका 'रेप' कर दिया गया, जिनकी वैधानिक जिम्मेदारी उसके अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि आरोपी को उचित सजा मिल सके।

न्यायपालिका में भी स्थिति बेचैन करने वाली है। यौन-उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाती है और मुकदमे लंबे खिंचते चले जाते हैं। ऐसे में, आरोपी जमानत पर बाहर आने के बाद पीड़िता को डराने-धमकाने, गवाहों को तोड़ने के ही काम करते हैं। यौन अपराध के आरोपियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसकी त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। दुर्योग से ऐसे मुकदमों के फैसले में सालों लग जाते हैं, जिसके कारण अपराधियों में कोई डर नहीं रह जाता।

भारत में रेप और हत्या के दोषी बहुत कम अपराधियों को मौत की सजा दी गई है। ऐसे फैसले उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। मुझे हमेशा से ऐसा लगता आया है कि हमारा सिस्टम आरोपी के पक्ष में झुका हुआ है और पीड़िता, उसके परिवार व उनके जीवन भर के सदमे को भुला दिया जाता है। यह याद रखने की जरूरत है कि ऐसे आरोपियों की मानसिक स्थिति को बदला नहीं जा सकता और यह मुमकिन है कि वे फिर से इस प्रवृत्ति का प्रदर्शन करें।

यह स्थिति इसलिए भी बनी हुई है कि हमारी राजनीति और राजनेताओं का इसमें सीधा अमल-दखल है। कई नेता हैं, जिनके विरुद्ध ऐसे मामले लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन वे फिर भी राजनीति में सक्रिय हैं। इस माहौल में उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अगर वे स्वयं किसी मामले के आरोपी हैं, तब तो सुबूत मिटाने और दबाने के लिए हर स्तर पर दखल की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। रेप और हत्या के मामलों को आत्महत्या बताकर रफा-दफा कराने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। दिशा सालियान के मामले में क्या हुआ? उनके परिजन आज भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मामले में लंबे और लगातार विरोध-प्रदर्शन के बाद कार्रवाई हो पाई। सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सत्तारूढ़ नेताओं के निर्देश पर कदम उठाती हैं। कई बार सियासी फायदा उठाने के लिए मामले को बंद कर दिया जाता है या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है या फिर राजनीतिक विरोधियों के सिर पर 'तलवार' की तरह लटकाए रखा जाता है, ताकि उनसे मर्जी के काम करवाए जा सकें।

हालांकि, लड़कियों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि वे कहीं पर असुरक्षित हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए आत्मरक्षा के तरीके सीखना बहुत जरूरी है। मैं 'मेरा शरीर, मेरी मर्जी' वाली बात में विश्वास नहीं करती। यह हमारी संस्कृति की सोच नहीं है। हमारी संस्कृति मानिनी, स्वाभिमानी महिलाओं की है। इसलिए अपनी मर्यादा का ख्याल उन्हें भी रखना होगा। निस्संदेह, अब ज्यादा महिलाएं काम पर निकलती हैं। भविष्य में यह संख्या बढ़ेगी। मेरा अनुभव कहता है, यदि आप खुद को सम्मानजनक तरीके से रखते हैं और आपके आस-पास के लोग जानते हैं कि आप शालीन महिला हैं और किसी आपत्तिजनक बात की अनदेखी नहीं करेंगी, तो आपको किसी भी अवांछित प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। मैं जिला न्यायाधीश की अदालत में एक मुकदमे की गवाह रही हूं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि वहां मुकदमे से संबंधित सभी लोगों के लिए उसके ब्योरे को सुनना बेहद असहज करने वाला था। यह अच्छी बात है कि अब उन्हें कैमरे पर सुना जाता है।

महिला सुरक्षा के मामले में तब तक प्रभावी असर नहीं दिखेगा, जब तक सिस्टम में ईमानदारी नहीं आएगी। हमारा समाज पूरी तरह भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। इसलिए न्याय पाना मुश्किल हो गया है। आज आम लोगों पर तरस ही खाया जा सकता है, जिनकी कोई जान-पहचान नहीं होती और जिन्हें ऐसी शर्मनाक स्थिति से निपटना पड़ता है। जब जनता सड़क पर आती है या मीडिया चर्चा करता है, तब जाकर उस पर कार्रवाई होता है। निस्संदेह, सिस्टम में ईमानदार लोग भी हैं, पर वे अपवाद स्वरूप ही हैं।

यौन-उत्पीड़न के मुकदमों की समय-बद्ध सुनवाई होनी चाहिए और बच्चियों से बलात्कार व हत्या के मामले में मौत की सजा अनिवार्य होनी चाहिए।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

बेटियों को बुरी नजरों से कैसे बचाया जाए

यहां स्कैन करें

मनीषा प्रियम | विशिष्ट प्रोफेसर, मोनाश यूनिवर्सिटी

- कॉलेज का खुला प्रांगण अपनी ही बच्चियों को क्यों आहत कर रहा?
- निर्भया कांड के जनांदोलन के बावजूद नीच कर्म की पुनरावृत्ति हो रही।
- चेहरा स्कैन कर अपराधियों को पकड़ने वाले सुरक्षा वैन बेकार साबित हो रहे।

यह खेद की बात है कि संस्कार के युग में व्यभिचार का दौर चल गया। खेद है कि समता पर आधारित हमारे भारत राष्ट्र में, असम्माननीय कर्म चलन-सा बनता जा रहा। खेद यह भी है कि जो बालिका साइकिल पर बैठ स्कूल चल पड़ी थी, उसी को दरिंदों ने समूह बनाकर अपना निशाना बनाया। उसे कभी न भूलने वाली पीड़ा दे दी।

सन् 1985 में भारतीय रेल के साधारण दर्जे में बाबूजी (बैद्यनाथ पांडेय) की धोती की कोर पकड़े मैं भी लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा बनी थी। बस एक ही उम्मीद थी मेरी और बाबूजी की भी कि खूब पढ़ूं, खूब लिखूं और जीवन में कुछ बनूं। हर हफ्ते मां पोस्टकार्ड पर अपनी भावनाएं दर्ज कर पोस्ट बॉक्स में डाला करतीं। कॉलेज में दोपहर के भोजनावकाश के समय डाकिया खादी की थैली लेकर आता और मैं इस उम्मीद में टकटकी बांधे रहती कि मां के कुछ शब्द पढ़ने को मिल जाएंगे। यदा-कदा बाबूजी ट्रेन का भाड़ा जुटाकर कभी ठेकुआ ले आते, तो कभी सतुआ। कपड़ों के नाम पर खादी भवन में छूट के दरम्यान खरीदे गए कुछ कुर्ते होते थे और सबसे बड़ी धरोहर होती थीं, कॉलेज के बुक बैंक से दी गई कुछ अच्छी पुस्तकें। उन्हीं से सीखा था कि केंद्र क्या है और धुरी क्या? वहीं तो यह सोचना सीखा कि सम्मान से जीना और अपने अधिकारों की चादर ओढ़ना एक विशिष्ट नारीवादी जीवन है। यह भारतीय भी है।

उस वक्त लेडी श्रीराम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ सुंदर मोहिनी लूथरा थीं। वह हमेशा खादी पहनती थीं और सिर्फ इस बात पर अपना ध्यान लगाए रहतीं कि कैसे कॉलेज की छात्राएं विश्वविद्यालय में टॉप करें। वह चाहती थीं कि विश्व के अच्छे विश्वविद्यालयों में यहां के बच्चे जाएं। आईएएस-आईपीएस बनें। कई तो आईआईएम भी गईं। उसी जीवन का सपना था, जो बच्चियों को पढ़ने के लिए इस कॉलेज की ओर खींचा करता।

अब ऐसा क्या हुआ कि उसी कॉलेज का खुला प्रांगण अपनी ही बच्चियों को आहत कर गया? मैं यहां की पूर्व छात्रा हूं, समझ नहीं पा रही कि अपनी भावनाओं से कैसे उस लेडी श्रीराम कॉलेज का खाका खींचू, जो औरतों को निडर बनाना सिखाता था। 1987 में रूपकंवर सती कांड हुआ था। उसकी कहानी सुनकर हम छात्राएं हिल गई थीं। कितनी देर वह जली होगी, कितना कष्ट हुआ होगा और महिलाओं को अपने जीवन पर कितना अधिकार है- जैसे तमाम सवाल हमारे मन में उमड़ आए थे। हमने प्रिंसिपल साहिबा से अनुरोध करके यह मंजूरी मांगी कि कॉलेज से मंडी हाउस तक हम पैदल-मार्च करेंगे। तो, क्या गलत और क्या सही, सब कुछ इसी कॉलेज में सीखा। अब इस अशोभनीय घड़ी में क्या भूलूं और क्या याद करूं?

कैसे संजोऊं अपनी सोच इस को दिल्ली के बारे में, जो भारत की राजधानी है और तमाम युवक-युवतियां अपनी आंकाक्षाओं को पूरा करने जहां आते हैं। उनका सपना होता है कि इस शहर में उन्हें अच्छी पढ़ाई मिलेगी; कि खुली सोच का समर्थन होगा; कि शहर के पार्कों में शालीमार जैसा मजा आएगा। यहीं तो भारत की तरुणाई लक्ष्यों तक पहुंचेगी; यहीं तो नए युग का निर्माण होगा। मगर क्या बात है कि इसी शहर में, जहां निर्भया कांड के बाद इतना बड़ा जनांदोलन खड़ा हुआ, लगातार नीच कर्म की पुनरावृत्ति हो रही है।

देश भर से अबोध बच्चियां पढ़ने की उम्मीद में राजधानी दिल्ली आती हैं और कॉलेज के नजदीक ही हॉस्टलों में रहती हैं, लेकिन उनको निशाना बनाने वाले शोहदों के टिड्डी दल घूमते रहते हैं। क्या कर रहे थे दिल्ली पुलिस के वे वाहन, जो चेहरा स्कैन करके अपराधियों को पकड़ लेते हैं। जंतर-मंतर पर घूमने वाले 'इक्षणा' वैन कहां छिपे हैं? हम तो आश्वस्त हो चुके थे कि उन्नत और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जरिये महज चेहरे से दहशतगर्द और दरिंदे पकड़ लिए जाएंगे। हर कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। ऐसे में, कौन सी चूक हुई कि उच्चकों के समूह ने मिलकर एक छोटी बच्ची की प्रतिष्ठा और सम्मान का हनन करते हुए अपनी दरिंदगी का प्रदर्शन किया?

क्या शर्म नहीं आती कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे नारों के साये में पलने वाली बच्चियां भी सम्मानजनक जीवन से महरूम हो गई हैं? तो चलिए, हम हार मानते हैं। अब आप ही बताइए कि किस दायरे में जिए हम? अब आप ही बताइए, कहां-कहां और किस तरह से पर्दा करें हम? अब आप ही बताइए कि कैसे हवाई अड्डे पर इस भरोसे में हम अपना शरीर पहचान-पत्र बना दें कि आपके एयरपोर्ट महफूज हैं? जब हमारे शरीर पर हैवानियत होगी, तो फिर क्या फायदा आपकी डिजी यात्रा से?

अब मैं सपना नहीं देखना चाहती। केवल जीना चाहती हूं, इसलिए कि मैं पैदा तो हो चुकी हूं उस भारत में, जिसमें भ्रूण हत्या को पाप बताया गया था। और, जब मैं छोटी थी, तब हर अष्टमी के दिन मेरी पूजा भी होती थी। छठ में जब-जब मां ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, तब-तब यह मांगा कि हे सूर्य भगवान, मुझे एक रुनकी-झुनकी बेटी देना। मां की मन्नत से मैं आई, उसकी ममता में पली-बढ़ी, मगर अब यही एहसास हो रहा कि गलती तो मेरी ही है।

आप भले नए-नए समझौते करते रहिए, लेकिन संविधान की स्मृति-मात्र भी अब लड़कियों और औरतों के मन से मिटा दीजिए और बताइए कि 'मोरल पुलिसिंग' के तहत क्या हैं वे नियम, जिनको यदि हम मानें, तो हम सुरक्षित रह सकेंगे? इतिहास के पन्नों ने तो यही समझाया था कि जौहर तो तब हुआ, जब मध्य एशिया से हब्शी घोड़ों पर सवार आए थे। जौहर तो तब हुआ, जब लूटपाट की बुरी मंशा से दरिंदों ने भारतमाता को अपमानित किया था। लेकिन अब क्या? यह तो वह भारतमाता है, जिनकी वंदना करते हम नित्य सुबह जागे, और जिनकी कल्पना हमने श्वेत वस्त्रों में की, स्वच्छ-निर्मल विद्यादायिनी। आखिर क्या भूल हुई कि इस श्वेत वस्त्र पर दरिंदगी के दाग लगे? अब तो निःशब्द हूं और आगे की कोई राह भी नहीं दिखती। अब आप ही बताइए कि किन शब्दों से मैं आपकी उपासना करूं?

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ध्यान किसे कहते हैं

जब मन को देह के भीतर या बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के निमित्त प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसको उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होने की शक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था का नाम है ध्यान। जब ध्यान-शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को छोड़कर केवल उसके अंतर्भाग या अर्थ की ओर एकाग्र हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं।

धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ मिलाकर संयम कहते हैं। किसी का मन पहले किसी वस्तु में एकाग्र हो सकता है। उस एकाग्रता की अवस्था में वह कुछ समय तक रह सकता है और उसके बाद दीर्घ एकाग्रता की अवस्था में वह अनुभूति के केवल आंतरिक भाग पर, जिसका ध्येय-वस्तु केवल कार्य है, अपने आपको लगाए रखे, तो ऐसे शक्तिसंपन्न मन के वशीभूत सभी कुछ हो जाता है।

जीव की जितने प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें ध्यानावस्था ही सर्वोच्च है। जब तक वासना रहती है, तब तक यथार्थ सुख नहीं आ सकता। जब कोई व्यक्ति ध्यानावस्था से, साक्षी-भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है, केवल तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त होता है।

पृथ्वी के अन्य प्राणी इंद्रियों में सुख पाते हैं, मनुष्य बुद्धि में और देवमानव आध्यात्मिक ध्यान में। जो लोग ऐसी ध्यानावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पास यह जगत अत्यंत सुंदर रूप से प्रतीयमान होता है। उस जगत में वासना नहीं होती, वह सर्व विषयों में निर्लिप्त है, उसके पास प्रकृति के ये विभिन्न परिवर्तन एक महान सौंदर्य और उदात्त भाव की छवि मात्र हैं।

स्वामी विवेकानंद

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

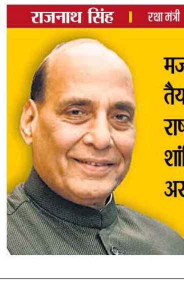

मजबूत अर्थव्यवस्था हमारी रक्षा तैयारियों को शक्ति देती है और सुरक्षित राष्ट्र विकास को गति देता है। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी अखंडता, संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए सदैव तैयार है।

अनुलोम-विलोम

चुनाव आयोग

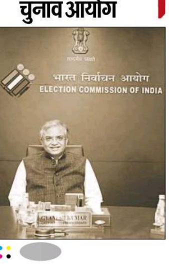

चुनाव आयोग की साख पर बड़े सवाल

एक राष्ट्र की लोकतांत्रिक इमारत जिन स्तंभों पर टिकी होती है, उनमें चुनाव आयोग का स्थान सबसे ऊपर आता है। यह वह संस्था है, जो मतदान की पवित्रता की रखवाली करती है, जो हर पांच वर्ष में सत्ता के हस्तांतरण को शांतिपूर्ण और वैध बनाता है, किंतु जब इस प्रहरी संस्था के भीतर से कलह की आवाजें बाहर रिसने लगती हैं, तब यह केवल एक प्रशासनिक खबर नहीं रह जाती, यह उस विश्वास की नींव को हिला देती है, जिस पर करोड़ों मतदाताओं का लोकतंत्र खड़ा है। बुधवार को जो समाचार सामने आया, उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। यहां टकराव महज विचारधारा का नहीं है। सवाल कानून की व्याख्या का है, प्रक्रिया की वैधता का है और सबसे बढ़कर, उस मूक मतदाता के अधिकार का है, जिसका नाम एक हस्ताक्षर भर से मतदाता सूची से गायब हो सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया इस पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि में एक काली छाया की तरह मंडरा रही है। आयोग का यह कहना कि एसआईआर से जुड़े सभी निर्णय सर्वसम्मति से हुए, सतही तौर पर संतोषजनक लगता है, परंतु गहराई से देखने पर यह स्पष्टीकरण अपने ही भीतर एक प्रश्न छिपाए रखता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के शब्दों में झलकने वाली बेचैनी इसी विरोधाभास से उपजी है, असहमति यदि वास्तविक थी, तो वह सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? और यदि निजी ही रही, तो क्या यह कानून का पालन था अथवा असुविधाजनक सत्य से बचने की एक व्यवस्थित चुप्पी?

नृपेंद्र अभिषेक 'नृप', टिप्पणीकार

जब अंपायर ही भेदभाव करने लगे, तो खेल में कुछ ज्यादा बचता नहीं है, इसलिए अंपायर का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कैग, लोकपाल, सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग जैसे संस्थान वही अंपायर हैं। अभी एक सप्ताह पहले एक सवाल पर कैथल के महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा था कि यह बहुत जरूरी है कि जो संस्थान हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर जा रहे हैं, उस पर वह विश्वास करे। अगर ऐसा नहीं है, तो हमें अपने भीतर झांकने और सुधार करने की जरूरत है। चुनाव आयोग आज ऐसा ही संस्थान बन चुका है, जो दिन-ब-दिन जनता में अपना विश्वास खोता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त तमाम आरोपों पर स्पष्टीकरण दें, एसआईआर के जरिये फर्जीवाड़ा करने के लिए माफी मांगें और अपना पद छोड़ दें।

सचिन भारद्वाज, मीडिया शोधार्थी

महज एक घटना से नहीं डिगेगा विश्वास

भारतीय निर्वाचन आयोग हमारे लोकतंत्र की उन चंद संस्थाओं में शुमार है, जिसकी प्रतिष्ठा सात दशकों से भी अधिक समय में करोड़ों मतदाताओं के भरोसे से बनी है। हाल में एक खोजी रिपोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों का उल्लेख हुआ, जिससे आयोग की कार्यप्रणाली पर बहस तेज हुई। यह स्वाभाविक है कि किसी सांविधानिक संस्था के भीतर असहमति या निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठें, तो उसकी छवि प्रभावित होती है, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ एक घटना से किसी संस्था की विश्वसनीयता खत्म नहीं होती।

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित चुनाव आयोग का दायित्व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। इसकी साख किसी एक रिपोर्ट या एक फैसले से नहीं, बल्कि हजारों चुनावों के सफल संचालन से बनी है। 1951-52 के पहले आम चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाताओं के साथ शुरू हुई यह यात्रा आज 95 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुंच चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना अपने आप में आयोग की संस्थागत क्षमता का प्रमाण माना जाता है। इतिहास बताता है कि आयोग ने कई कठिन परिस्थितियों में अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। साल 1990 के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने आदर्श आचार संहिता के कठोर पालन, चुनावी खर्च की निगरानी व बूथ कब्जाने जैसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर आयोग की प्रतिष्ठा को जो ऊंचाई दी, वह आज तक कायम है। बाद के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और फिर वीवीपैट व्यवस्था को लागू कर मतदान-प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। इन सुधारों ने चुनाव प्रबंधन को मजबूत किया।

निस्संदेह, आलोचनाएं भी हुई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर आयोग पर पक्षपात, आचार संहिता के असमान अनुपालन या फैसलों में देरी के आरोप लगाते रहे हैं। कई मामलों में आयोग के निर्णय न्यायालयों तक पहुंचे हैं। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषता है कि सांविधानिक संस्थाएं सार्वजनिक विमर्श और न्यायिक समीक्षा, दोनों के दायरे में रहती हैं, इसलिए मतभेद सामने आना संस्था की कमजोरी का अंतिम प्रमाण नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता का संकेत भी हो सकता है। यदि चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद हैं, तो उनका संस्थागत समाधान और फैसलों का स्पष्ट रिकॉर्ड लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करेगा, परंतु यह निष्कर्ष निकाल लेना कि इससे आयोग की विश्वसनीयता ध्वस्त हो गई है, सही नहीं होगा।

बिट्टू शर्मा, टिप्पणीकार

पेट्रोल के बढ़ते खर्च और प्रदूषण के बीच इलेक्ट्रिक दोपहिया बेहतर विकल्प बन रहे हैं। सवा लाख रुपये तक की कीमत में अब कई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक मौजूद हैं, जिन्हें भविष्य के वाहन माना जा रहा है। अब रोजाना की जरूरत और इस्तेमाल के हिसाब से बैटरी, रेंज, डिजाइन और पावर जैसे पहलुओं को समझना जरूरी है। किसकी जरूरत के लिए कौन–सा इलेक्ट्रिक दोपहिया बेहतर हो सकता है, बता रही हैं रूपाली चतुर्वेदी

बाजार में छाए कम कीमत के इलेक्ट्रिक दोपहिया

देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया का बाजार तेजी से पैर पसार रहा है। अगस्त 2026 में 1.83 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया बिके, जो पिछले साल से करीब 67 फीसदी अधिक हैं। वहीं, जनवरी से अगस्त तक की बिक्री 13.6 लाख यूनिट पार कर चुकी है। दरअसल, इस सेगमेंट में करीब 1.25 लाख रुपये के बजट में स्कूटर से बाइक तक कई विकल्प मौजूद हैं। हालांकि, खरीदारी से पहले अपनी जरूरत और रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से सही मॉडल चुनना जरूरी है।

1.25 लाख में कई विकल्प

करीब 1.25 लाख रुपये में टीवीएस आईक्यूब, एथर रिज्टा, ओला एस1 एक्स+ और एस1 प्रो+, वीडा वीएक्स2+ जैसे स्कूटर उपलब्ध हैं। वहीं ओला रोडस्टर एक्स जैसी बाइक का विकल्प भी मिलता है। वेरिएंट के अनुसार कीमत बदलती है। इस बजट में 1.8 से 4.5 केडब्लूएच तक की बैटरी, 100 से 250 किमी तक की दावा की गई रेंज और 68 से 125 किमी/घंटे तक की टॉप स्पीड वाले मॉडल मौजूद हैं।

इस रेंज के रिज्टा, विडा और आईक्यूब जैसे स्कूटरों को फैमिली स्कूटरों के तौर पर तरजीह दी जाती है। इनमें 27-34 लीटर तक स्टोरेज मिलता है। कुछ मॉडल में हिल होल्ड, क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन और रिजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखें कि सभी मॉडल के सभी वेरिएंट 1.25 लाख रुपये के भीतर नहीं आते। इनमें शहर और वेरिएंट के हिसाब से कुछ कम या ज्यादा कीमत हो सकती है।

1 लाख से कम के ई-स्कूटर

इस रेंज में बाजार में कई अच्छे ब्रांड के स्कूटर मौजूद हैं। इनमें ओला एस1एक्स, हीरो मोटर्स का विडा वीएक्स2 गो, टीवीएस ऑर्बिटर जैसे स्कूटर आते हैं। विडा वीएक्स2 गो के बैटरी वेरिएंट के हिसाब से तीन मॉडल हैं, जिनमें 2.2 केडब्लूएच वेरिएंट की कीमत 80000 है, जो 3.4 केडब्ल्यूएच बैटरी के साथ 95000 हो जाती है। इस स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे कई आधुनिक फीचर्स मिलते हैं।

वहीं टीवीएस ऑर्बिटर बैटरी एज ए सर्विस के साथ 50,000 रुपये एक्सशोरूम की कीमत में आ रहे हैं। एंपियर मैग्नस का नियो और रियोवीवाईबी भी एक लाख से नीचे की कीमत में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ओकिनावा प्रेज प्रो, रिज और लाइट मॉडल 60 हजार से लेकर 90 हजार तक की रेंज में मिल जाएंगे। होंडा क्यूसीवन न्यूनतम 90807 रुपये तक में उपलब्ध है।

क्या खासियतें

टीवीएस आईक्यूब का संतुलित पैकेज : 3.5 केडब्लूएच बैटरी वाला टीवीएस आईक्यूब वेरिएंट करीब 1.10 लाख रुपये में आएगा, जो 145 किमी आईडीसी रेंज देता है। आरामदायक सवारी के साथ नेविगेशन, पार्क असिस्ट और हिल होल्ड जैसे फीचर शहर में उपयोगी हैं।

रेंज व स्टोरेज के लिए टीवीएस ऑर्बिटर : बिना बास स्कीम के इस स्कूटर का 3.1 केडब्ल्यूएच वेरिएंट करीब 1.03 लाख रुपये में उपलब्ध है। यह 158 किमी आईडीसी रेंज देता है। 165 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और 34 लीटर बूट स्पेस इसे खराब सड़कों व रोजमर्रा के शहर के सफर के लिए व्यावहारिक बनाते हैं।

आराम के लिए एथर रिज्टा : 3.5 केडब्ल्यूएच वेरिएंट 161 किमी आईडीसी रेंज देता है। 34 लीटर बूट स्पेस के साथ लंबी सीट और पीछे बैठने वाले के लिए पर्याप्त जगह इसे दो लोगों के नियमित सफर के लिए उपयोगी बनाती है।

दमदार ओला एस1 एक्स+ : 4 केडब्ल्यूएच वेरिएंट में 11 केडब्ल्यू की पीक पावर के साथ 125 किमी/घंटे की टॉप स्पीड मिलती है। कंपनी के मुताबिक, यह वेरिएंट 242 किमी तक की आईडीसी रेंज देता है। हालांकि, दिल्ली में इसकी कीमत करीब 1.17 लाख रुपये है।

चार्जिंग में आसान वीडा वीएक्स2 : इसकी कीमत करीब 87,790 रुपये है। 3.4 केडब्ल्यूएच बैटरी 142 किमी की आईडीसी रेंज देती है। इसकी रिमूवेबल बैटरी को स्कूटर से निकालकर घर या दूसरी जगह चार्ज किया जा सकता है। पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट की सुविधा न होने पर यह विकल्प काम आ सकता है।

रेंज देखकर ही फैसला न करें : ईवी में कंपनी की आईडीसी रेंज सड़क पर कम हो सकती है। ट्रैफिक, तेज रफ्तार, वजन और चढ़ाई से रेंज प्रभावित होती है। रोज 20-30 किमी चलने वालों को बड़ी बैटरी पर ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं, जबकि 50 किमी या ज्यादा सफर में अतिरिक्त रेंज काम आ सकती है।

रोजाना कितनी बचत : 7-10 रुपये यूनिट बिजली पर ईवी की चार्जिंग लागत करीब 20-35 पैसे प्रति किमी पड़ सकती है, यानी 50 किमी में 10-18 रुपये और 100 किमी में 20-35 रुपये। 50 किमी प्रति लीटर का औसत देने वाली पेट्रोल बाइक में 100 रुपये लीटर पेट्रोल पर यही खर्च करीब 100 और 200 रुपये होगा। वास्तविक खर्च बिजली दर, पेट्रोल कीमत और वाहन की खपत पर निर्भर करेगा।

अगर इलेक्ट्रिक बाइक लें

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की बात करें, तो इस समय सवा लाख के बजट में ओला रोडस्टर एक्स मौजूद है। 2.5 से 4.5 केडब्लूएच बैटरी विकल्पों वाली इस बाइक की शुरुआती कीमत 1.04 लाख रुपये है।

विशेषज्ञ की राय

1 से 1.25 लाख रुपये के बजट में इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते समय कीमत और रेंज के साथ चार्जिंग सुविधा भी देखें। सोसाइटी में डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट, सही कनेक्शन और अर्थिंग की जांच करें। वोल्टेज में उतार–चढ़ाव से होने वाले नुकसान की वारंटी शर्तें और बैटरी की वारंटी कितने साल या कितने किलोमीटर की है, इसकी जानकारी लिखित में लें। सर्विस सेंटर और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता भी जरूर जांचें। – आशीष झा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एनालिस्ट

विविध

महंगी कारों में लग रहे डिजिटल मिरर

बिना साइड या रियर व्यू मिरर के कार चलाना सुरक्षित नहीं माना जाता। हालांकि, जापान और यूरोप में कई महंगी कारों में ये नदारद मिल रहे हैं। कंपनियां डिजिटल मिरर का विकल्प दे रही हैं। ऑडी ई-ट्रॉन, लेक्सस ईएस, होंडा ई जैसी कारों में यह चलन देखा जा रहा है। दरअसल, कार के बाहर लगे शीशे कार की गति, माइलेज और एअरो-डायनामिक्स पर असर डालते हैं। इसलिए ऐसी कारों में बाहरी रियर व्यू मिरर्स को पूरी तरह हटाकर बाहर छोटे कैमरे और अंदर डिजिटल स्क्रीन लगाए जाते हैं। इनकी मदद से ड्राइवर को साइड और पीछे से आती कारों की जानकारी बेहतर मिलती है, कार की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है।

इस तरह टू पॉइंट से थ्री पाइंट की हुई सीटबेल्ट

कार में सीटबेल्ट एक अनिवार्य सुरक्षा फीचर है। हालांकि, पहले टू-पॉइंट या लैप सीटबेल्ट का इस्तेमाल होता था, जो दुर्घटना में रीढ़ और अंदरूनी अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्वीडिश कार निर्माता वोल्वो के सुरक्षा इंजीनियर नील्स बोहलिन ने 1959 में थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट का आविष्कार किया। यह टक्कर के झटके को सीने और कूल्हे की मजबूत हड्डियों पर बांट देती है। वोल्वो ने इसका पेटेंट अपने पास रखने के बजाय इसे पूरी दुनिया के लिए मुफ्त कर दिया। माना जाता है इससे अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है।

ग्रीन कारों के काफिले में एक और पेशकश

कार खरीदारों के लिए विकल्प लगातार बढ़ रहे हैं। एक ओर सीएनजी के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली स्विफ्ट पेश हो चुकी है, तो वहीं, आधुनिक तकनीक और सुरक्षा फीचर के साथ हुंडई बेयॉन जल्द दस्तक देने को तैयार है

नई गाड़ी

सीएनजी एएमटी में आई स्विफ्ट

बीते दिनों मारुति सुजुकी ने ऑटो ग्रीन मिशन के तहत स्विफ्ट का ऑटोमैटिक एस-सीएनजी मॉडल पेश किया है। यह सुविधा वीएक्सआई वैरिएंट में उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक, स्विफ्ट सीएनजी-एएमटी यानी ऑटोमेटिक 35.34 किमी/ किलोग्राम तक का माइलेज देती है, हालांकि वास्तविक माइलेज ड्राइविंग और सड़क की स्थिति पर निर्भर करेगा।

पावर और ऑटोमैटिक गियर : स्विफ्ट सीएनजी एएमटी में 1.2-लीटर जेड12ई इंजन है, जो सीएनजी मोड में 69.75 पीएस पावर और 101.8 एनएम टॉर्क देता है। इसमें 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स है, जो क्लच और गियर अपने आप बदलता है। जरूरत पड़ने पर मैनुअल गियर भी इस्तेमाल हो सकता है।

फीचर में बदलाव नहीं : सीएनजी-एएमटी वर्जन में मुख्य बदलाव पावरट्रेन से जुड़ा है, जबकि फीचर्स पहले की तरह हैं। इनमें 9-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो-एपल कारप्ले, रियर एसी वेंट, रियर व्यू कैमरा और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।

सुरक्षा के लिए : 6 एयरबैग, एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, क्रूज कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं।

कीमत कितनी : एक्स-शोरूम कीमत 7.92 लाख रुपए बताई गई है।

किनसे टक्कर: मुकाबला मुख्य तौर पर हुंडई ग्रैंड आई10 निओस सीएनजी जैसे सीएनजी हैचबैक से माना जा सकता है। हालांकि, सीएनजी के साथ एएमटी का विकल्प इसे अलग बनाता है।

त्योहरी मौसम में पेश होगी बेयॉन

हुंडई बेयॉन को कंपनी के एन्हांस्ड ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक, इसे भारत के 5–स्टार सुरक्षा मानकों के तहत तैयार किया गया है। 4.2 मीटर लंबी बेयॉन में पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और आईवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा। इन–बिल्ट जनरेटिव एआई वॉयस असिस्टेंट और अलॉय व्हील्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। बुकिंग 11,000 रुपये में हुंडई की वेबसाइट और अधिकृत डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है। त्योहारी मौसम में पेश होने की संभावना है। कीमत 9 से 14 लाख रुपये एक्स–शोरूम हो सकती है। –नरेंद्र

कार चोरी से बचाने में कारगर गैजेट

कार चोरी का खतरा कम करने के लिए जीपीएस ट्रैकर, स्टीयरिंग लॉक, कार अलार्म जैसे कई गैजेट मौजूद हैं। ये चोरी की कोशिश को मुश्किल बनाने और जरूरत पड़ने पर कार का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। इनमें से कौन–सा विकल्प कितना कारगर है, जानना जरूरी है

टिप्स

कार की सुरक्षा के लिए सिर्फ कंपनी के दिए फीचर्स पर निर्भर रहने के बजाय अब कई लोग अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कुछ उपकरण चोरी की कोशिश को रोकने में मदद करते हैं, जबकि कुछ चोरी के बाद वाहन की लोकेशन पता करने में काम आते हैं। हालांकि, हर गैजेट का काम और सुरक्षा स्तर अलग होता है।

जीपीएस ट्रैकर : यह कार की लोकेशन जानने के लिए ही नहीं, घर-परिवार की सुरक्षा के लिए भी अच्छा विकल्प है। इसीलिए, इसे लेते समय सिर्फ लोकेशन ट्रैकिंग न देखें। मूवमेंट अलर्ट, जियो-फेंसिंग, बैटरी बैकअप और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा भी जांचें। कुछ डिवाइस के लिए सिम या सब्सक्रिप्शन का अलग खर्च होता है। ऑनलाइन भी मिलते हैं। ये 1500 से 15000 रुपये तक में मिल रहे हैं।

ओबीडी पोर्ट को भी रखें सुरक्षित: कार का ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स (ओबीडी) पोर्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम से जुड़ा होता है और कुछ मामलों में इसका गलत इस्तेमाल कार की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। जरूरत के अनुसार ओबीडी लॉक या सुरक्षा कवर जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ ओबीडी लॉक्स जीपीएस और एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ भी आते हैं। कीमत 4500 रुपये तक जा सकती है।

पार्किंग में भी बरतें सावधानी : कार को सुनसान जगह पर पार्क करने के बजाय रोशनी वाली और सीसीटीवी वाली जगह पर खड़ा करें। इससे चोरी की कोशिश का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।

स्टीयरिंग लॉक की मजबूती जांचें: स्टीयरिंग लॉक खरीदते समय सिर्फ कीमत या डिजाइन न देखें। लॉक मजबूत है, स्टीयरिंग पर सही तरह फिट होता है और इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता, यह देखना जरूरी है।

अलार्म में मोबाइल अलर्ट : सिर्फ तेज आवाज वाला हूटर अलार्म लगाने के बजाय ऐसा सिस्टम चुनना उपयोगी हो सकता है, जो गाड़ी से छेड़छाड़ होने पर मोबाइल पर भी अलर्ट भेजे। इससे कार से दूर होने पर भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिल सकती है।

की–लेस कार में चाबी भी रखें सुरक्षित : की-लेस एंट्री वाली कारों में चाबी के सिग्नल का गलत इस्तेमाल कर कार खोली जा सकती है। इसलिए चाबी को दरवाजे या खिड़की के पास रखने से बचें। सिग्नल-ब्लॉकिंग पाउच का इस्तेमाल भी अतिरिक्त सुरक्षा दे सकता है। -फीचर डेस्क

खरीद से पहले जानें

- जीपीएस ट्रैकर में रियल–टाइम लोकेशन कितनी सटीक है।
- डिवाइस के लिए अलग से सबस्क्रिप्शन या सिम का खर्च है या नहीं।
- मोबाइल एप में किस तरह के अलर्ट मिलते हैं।
- अलार्म सिस्टम कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ सही तरीके से काम करता है या नहीं।
- आफ्टर–सेल्स सर्विस और वारंटी उपलब्ध है या नहीं।
- डिवाइस में छेड़छाड़ होने पर तुरंत अलर्ट मिलने की सुविधा है या नहीं।
- डिवाइस लगाने से कार वारंटी या इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : मन परेशान रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

वृष : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। किसी राजनेता से भेंट हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। सेहत के प्रति सचेत रहें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। अफसरों का सहयोग भी मिल सकता है।

कर्क : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ अधिक रहेगी।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। संयत रहें। बातचीत में संतुलित रहें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। सचेत रहें। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। कारोबार के लिए माता से धन मिल सकता है। सेहत के प्रति सचेत रहें।

तुला : आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परंतु मन परेशान हो सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्च बढ़ेंगे। कारोबार में कठिनाई आ सकती है।

वृश्चिक : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। परिवार से दूर किसी स्थान पर जा सकते हैं।

धनु : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है।

मकर : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है।

कुंभ : किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। कारोबार में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। आय में कमी और खर्च में अधिकता की स्थिति रहेगी।

मीन : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। सम्मान की प्राप्ति होगी। संतान की सेहत में सुधार होगा। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

26 सितंबर, शनिवार, **शक संवत् :** 04 आश्विन (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग :** 10, आश्विन मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम :** 14, रबि–उल्सानी, 1448, **विक्रमी संवत् :** भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तिथि रात्रि 10.19 मिनट तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 11.32 मिनट तक पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र गण्ड योग दोपहर 01.18 मिनट तक, विष्टि करण प्रातः 10.43 मिनट तक, चंद्रमा मीन राशि में (दिन–रात)।

सूर्य दक्षिणायन। प्रातः 09 बजे से प्रातः 10.30 मिनट तक राहुकालम्। भाद्रपद पूर्णिमा। सत्यनारायण व्रत। पूर्णिमा श्राद्ध।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

घर और व्यापार में सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अज्ञात भय से डरे, तो क्या करें–

- घर में जो निर्माण कार्य हुआ है, उसमें दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में कोई निर्माण नहीं कराया है। यह दिशा खाली या हल्की होना हमें अनेक प्रकार के भय देती है।
- साथ ही अग्नि कोण में बना हुआ फाउंटेन भी इसमें और सहयोग दे रहा है।
- अग्नि कोण में जल तत्व होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यह न केवल आर्थिक स्थिति, वरन हमारे आत्मविश्वास, हिम्मत, प्रतिरोधी क्षमता भी कमजोर करता है।
- आप यहां से फाउंटेन बंद कर दें और हटा दें। दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी पर्वत की मिट्टी एवं पत्थर लाकर रखें। घर के दक्षिण पूर्व में लाल रंग की मोमबत्ती जलाएं।

वर्ग पहेली : 8463

■	1	■	2	3		4		5
6		■	■		■		■	
■	7							
8		■	■		■		■	
	■	9		■	10		■	
	■		■	11	■	■	12	
13								■
	■				■	■	14	
15						■		■

बाएं से दाएं
2. मकराना राजस्थान का सफेद पत्थर; सफेद चिकना पत्थर (6)
6. जो चुप हो; अवाक; गूंगा; दीन; लाचार (2)
7. धन जमा रखने पर बैंक से मिलने वाला दस्तावेज (3,2,3)
8. विष; बिच्छू का डंक (2)
9. घोंसला (2)
10. दर; आशय; ढंग; नाज; नखरा (2)
12. विविध; अनेक; मातामह (2)
13. अचेत हो जाना; शिथिल हो जाना; होशो हवास खो बैठना (5,1,2)
14. अंत; मृत्यु; समय (2)
15. नियंत्रण करना; लगाम चढ़ाना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. स्थान जहां सिक्के ढाले जाते हैं (4)
3. मोती का चटकना; जोर से कड़क कर बोलना; बादलों का गड़गड़ाना; तड़कना (4)
4. चालू रखने व बनाए रखने की क्रिया; देख भाल; देख रेख; साज संभाल (2,3)
5. जुर्माना वसूल करना; रसीद लिखकर देना (3,3)
8. आस पास; इधर उधर; साथ साथ (3,3)
9. अज्ञानी वैद्य; अनाड़ी हकीम; अल्पज्ञानी चिकित्सक; अल्पज्ञ; अल्प ज्ञानी; अल्प शिक्षित (2,3)
11. अगल बगल; समीप; निकट (2,2)
12. अनेक प्रकार से किया हुआ (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8462

1 ब	2 रा	य	3 ना	म	■	4 बा	■	5 ब
■	नी	■	का	■	6 क	त	र	ना
7 म	हा	स	म	र	■	सु	■	ब
■	र	■	क	■	8 ब	न	वा	ना
9 ता	■	10 दू	र	क	र	ना	■	या
11 ना	क	र	ना	■	बा	■	12 ल	■
क	■	सं	■	13 म	द	द	गा	र
14 स	मा	चा	र	■	हो	■	ता	■
ना	■	र	■	15 सू	ना	क	र	ना

सुडोकू : 8417

*मध्यम

		6		5				
					1	6		
3		1			2			5
	9	4			7		8	
		2				7		
	8		3			4	6	
5			1			2		4
		8	9					
				2		1		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8416

8	3	4	1	6	7	5	9	2
6	9	2	8	4	5	1	7	3
1	7	5	3	9	2	4	6	8
4	6	8	7	5	9	2	3	1
5	1	9	4	2	3	6	8	7
3	2	7	6	8	1	9	4	5
2	4	6	5	7	8	3	1	9
7	5	1	9	3	6	8	2	4
9	8	3	2	1	4	7	5	6

कल्पमेधा

संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। परिश्रम से भूख तेज होती है और संयम अतिभोग से रोकता है।

– रूसो

नैतिकता के नाम पर

एक सभ्य समाज अपने बीच उदारता और करुणा से लैस जीवन-मूल्यों की कद्र करता है और अपनी सोच-समझ के बरक्स अन्य लोगों या समुदायों की जीवन-पद्धतियों, जीने के तरीकों का भी सम्मान करता है। मगर इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आज इक्कीसवीं सदी का सफर तय करते हमारे देश में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें किसी के निजी विचार या उसकी पसंद को न केवल नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, बल्कि ऐसा करने के लिए हिंसा या अपराध का भी सहारा लिया जाता है। हाल ही में बिहार के जमुई के अलावा बांका और समस्तीपुर में लगातार ऐसी घटनाओं के वीडियो प्रचारित हुए, जिनमें कुछ आपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने रास्ते में लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा की या उनके दोस्त को भी मारा-पीटा। ऐसे मामले सामने आने के बाद पुलिस ने कानून के मुताबिक कदम उठाए, लेकिन इस दौरान एक बार फिर यह सवाल उठा कि महज नैतिकता के नाम पर लड़कियों या उनके दोस्त को प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को किसने दे दिया!

एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर दो लोग दूसरों के जीवन को बाधित किए बिना अपनी जिंदगी खुद तय करते हैं, तो इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर दो युवा जब दोस्ती करते हैं, मिलते-जुलते हैं या फिर आगे चलकर प्रेम और विवाह करते हैं, तो यह उनका अपना चुनाव है और इसमें किसी भी अन्य को दखल देने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में अदालतों ने भी समय-समय पर यह व्यवस्था दी है कि कोई भी वयस्क किसी से दोस्ती करने का अधिकार रखता है। मगर कुछ असामाजिक तत्त्व न तो अपने विचारों में सभ्यता और परिपक्वता लाने के लिए तैयार होते हैं और न ही इस संबंध में कानूनी तकाजों का खयाल रखना जरूरी समझते हैं। देश भर से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें अराजक समूहों ने कहीं पार्क या रेस्तरां में जबरन घुस कर लड़के-लड़कियों या प्रेमी युगलों के खिलाफ अपमानजनक और हिंसक व्यवहार किया।

हैरानी की बात यह है कि एक ओर समाज अपनी रोजमर्रा की जीवनशैली में सभी आधुनिक सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है, लेकिन सोच-समझ और पूर्वाग्रहों के मामले में उन्हीं प्रतिगामी मूल्यों को ढोता है, जो कई बार अमानवीय और आपराधिक भी होते हैं। ऐसी घटनाएं कितनी शर्मनाक होती हैं, जिनमें कहीं बैठे या जा रहे युवक-युवती को रोक कर उन्हें सिर्फ नैतिकता के नाम पर अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। सच यह है कि कथित नैतिकता की पहरेदारी करने का दावा करने वाले लोग अपनी सोच-समझ में बेहद पिछड़े और संकीर्ण दायरे में सिमटे होते हैं। इसके अलावा, जब कोई जनप्रतिनिधि भी 'शालीन तरीके से' नैतिक पहरेदारी की वकालत करे, तो समझा जा सकता है कि एक जड़ मानसिकता वाले समाज को और ज्यादा पीछे करने में ऐसे नेता कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। समूचे समाज के लिए एक जरूरी चिंता का मसला यह होना चाहिए कि लोगों के बीच यह कैसी प्रवृत्ति विकसित हो रही है या पल-बढ़ रही है कि वे किसी की निजी जिंदगी को अपने पूर्वाग्रहों के मुताबिक संचालित कर सकते हैं। इस तरह की आपराधिक मानसिकता का अगर विस्तार होता है, तो क्या इसके नतीजों का अंदाजा लगाना इतना मुश्किल है? अगर समाज में किसी की निजी जिंदगी में नाहक दखल देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह किस रूप में किसके पास पहुंचेगा या लौटेगा, कहा नहीं जा सकता!

मिलावट के विरुद्ध

शुद्ध और सुरक्षित भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है। मगर कुछ लोगों ने खाद्य पदार्थों के बाजार में मिलावट को मुनाफे का औजार बना लिया है। यह केवल कानून के उल्लंघन का प्रश्न नहीं, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य और विश्वास के साथ खिलवाड़ का भी मसला है। रोजमर्रा के जरूरी खाद्य पदार्थों जैसे- दूध, घी, तेल, मसाले, मिठाइयां, दालें और यहां तक कि फलों एवं सब्जियों में भी मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे पदार्थों के सेवन से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव ज्यादा गंभीर हो सकता है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम नागरिक को कैसे पता चलेगा कि किस खाद्य वस्तु में मिलावट की गई है और किसमें नहीं? अगर कोई शिकायत करता भी है, तो यह संबंधित विभाग के अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे कितनी संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से सचालित प्रयोगशालाओं के माध्यम से खाद्य वस्तुओं की तत्काल जांच की सुविधा मुहैया कराने की पहल निश्चित रूप से आम लोगों के लिए एक बड़ा कदम है।

देश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट का फैलता बाजार एक गंभीर समस्या बन गया है। इसका प्रमुख कारण खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन न होना तथा खाद्य वस्तुओं की नियमित जांच और मिलावट करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का अभाव है। सामान्य तौर पर बाजार से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उनकी जांच कराने की जिम्मेदारी विभागीय कर्मियों की होती है। मगर इस प्रक्रिया में कितनी ईमानदारी और पारदर्शिता बरती जाती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस स्थिति में हरियाणा में आम लोगों को खुद जांच कराने की सुविधा मुहैया कराने का सरकार का फैसला महत्त्वपूर्ण है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर तैनात सचालित प्रयोगशालाओं में कोई भी व्यक्ति खाद्य वस्तुओं की जांच करा सकता है, जिनका नतीजा दस से बारह मिनट में मिल जाएगा। अन्य राज्यों को भी इस तरह की पहल करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जांच प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष हो।

प्रक्रिया की पेचीदगी में उलझती पहचान

देश में हरेक नागरिक की पहचान अब केवल नाम और चेहरे तक सीमित नहीं है। ऐसे में कई बार प्रमाणपत्रों के सत्यापन की जटिल व्यवस्था सुविधा के बजाय जी का जंजाल बन जाती है।

विकेश कुमार बडोला

आधुनिक दौर में नागरिक की पहचान केवल नाम और चेहरे तक सीमित नहीं रह गई है। जन्म प्रमाणपत्र से लेकर आधार, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट, बैंक खाते, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक जीवन के लगभग हर महत्त्वपूर्ण पड़ाव पर किसी न किसी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। इनका उद्देश्य नागरिक और राज्य के बीच भरोसेमंद पहचान स्थापित करना है। मगर जब एक ही व्यक्ति की अलग-अलग संस्थाओं में दर्ज सूचनाओं में मामूली अंतर रह जाता है, तो यही व्यवस्था सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बनने लगती है। समस्या दस्तावेज की संख्या भर नहीं है। असली कठिनाई उनके बीच समन्वय, जिम्मेदारी और सुधार की प्रक्रिया को लेकर है। किसी प्रमाणपत्र में नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, पते या अन्य विवरण में त्रुटि हो जाए, तो नागरिक को अक्सर संबंधित कार्यालय, पोर्टल या सेवा केंद्र के बीच चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक दस्तावेज में सुधार के लिए दूसरे दस्तावेज की मांग की जाती है और दूसरे में सुधार के लिए पहले प्रमाणपत्र का सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसे में नागरिक एक ऐसे दुश्चक्र में फंस जाता है, जिसका हल उसके हाथ में नहीं होता।

डिजिटल प्रणाली के जरिए इस जटिल स्थिति को कई स्तरों पर सरल बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह भी सच है कि डिजिटल होने भर से प्रक्रिया नागरिक-केंद्रित नहीं हो जाती। जन सेवा केंद्रों और आनलाइन पोर्टलों ने आवेदन तथा दस्तावेज जमा करने की सुविधा बढ़ाई है, पर अंतिम सत्यापन और निर्णय का अधिकार अलग-अलग विभागों के पास बना हुआ है। इसका अर्थ यह है कि नागरिक को एक ही सूचना बार-बार अलग संस्थाओं के सामने सिद्ध करनी पड़ सकती है। तकनीक का लाभ तभी व्यापक होगा, जब विभागीय डेटाबेस के बीच सुरक्षित और स्पष्ट समन्वय के साथ त्रुटि-सुधार की जिम्मेदारी भी तय हो। आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जिसका उपयोग अनेक सेवाओं में पहचान के सत्यापन के लिए किया जाता है। बैंक खातों और मोबाइल सेवाओं से जुड़े विवरणों में आधार का इस्तेमाल व्यापक है।

ऐसे में आधार या उससे जुड़े रिकार्ड में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा अन्य सूचना की गड़बड़ी का असर दूसरी सेवाओं पर पड़ सकता है। प्रश्न यह है कि गलती हुई कहां है। यदि त्रुटि किसी विभागीय रिकार्ड में हुई है, तो उसके सुधार का पूरा बोझ नागरिक पर डालना प्रशासन की न्यायसंगत भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। नागरिक से आवश्यक प्रमाण मांगना अलग बात है, लेकिन विभागों के पास उपलब्ध प्रमाणों और अभिलेखों का परस्पर सत्यापन करना व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहां एक बुनियादी सिद्धांत सामने आता है- राज्य को नागरिक से पहचान का प्रमाण मांगने के साथ अपनी संस्थागत पहचान और जिम्मेदारी भी स्पष्ट करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने दशकों तक कर चुकाया है, मतदाता के रूप में पंजीकृत है, उसके जन्म, शिक्षा, संपत्ति या पारिवारिक संबंधों के सरकारी अभिलेख उपलब्ध हैं, तो इन सूचनाओं को अलग-अलग द्वीपों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। सत्यापन की प्रक्रिया में नागरिक को हर बार शून्य से शुरुआत करने के लिए विवश करना प्रशासनिक सुविधा नहीं, नागरिक के समय और श्रम पर अनावश्यक बोझ है।

इसलिए एकीकृत नागरिक प्रलेख एवं प्रमाणन तंत्र की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसे किसी नई पहचान संख्या या अतिरिक्त कागजी व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि मौजूदा प्रणालियों के बीच समन्वयकारी ढांचे के रूप में विकसित किया जाना अधिक उपयोगी होगा। केंद्र और राज्यों के संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, आधार व्यवस्था, निर्वाचन तंत्र, पासपोर्ट प्रणाली तथा अन्य वैधानिक संस्थाओं के बीच स्पष्ट प्रोटोकाल बनाया जा सकता है। इसमें यह तय होना चाहिए कि कौन-सा मूल रिकार्ड किस संस्था के पास रहेगा, कौन-सी सूचना किस परिस्थिति में साझा की जा सकती है, गलती सुधारने की जिम्मेदारी किसकी होगी और नागरिक को आवेदन का कौन-सा रास्ता मिलेगा। इस व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष घर-द्वार तक सेवा पहुंचाने की अवधारणा हो सकता है। बुजुर्गों, दिव्यांगों, दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और उन नागरिकों के लिए, जिन्हें बार-बार कार्यालय जाना कठिन होता है, उन्हें प्रशिक्षित सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन और दस्तावेजी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए निर्धारित शुल्क हो, तो वह पारदर्शी और सीमित हो तथा गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए छूट या निशुल्क सेवा का प्रावधान रखा जाए।

> **किसी एक दस्तावेज से जुड़े रिकार्ड में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा अन्य सूचना की गड़बड़ी का असर दूसरी सेवाओं पर पड़ सकता है। यहां सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गलती हुई कहां है। यदि त्रुटि किसी विभागीय रिकार्ड में हुई है, तो उसके सुधार का पूरा बोझ नागरिक पर डालना प्रशासन की न्यायसंगत भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। नागरिक से आवश्यक प्रमाण मांगना अलग बात है, लेकिन विभागों के पास उपलब्ध प्रमाणों और अभिलेखों का परस्पर सत्यापन करना व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए। डिजिटल शासन की वास्तविक परीक्षा भी यही है कि राज्य कितना अधिक डेटा जुटाता है और वह उपलब्ध जानकारी के आधार पर नागरिकों का जीवन कितना सरल बना पाता है।**

नागरिकता के प्रश्न पर विशेष सावधानी जरूरी है। आधार संख्या नागरिकता का प्रमाण नहीं है और किसी पहचान दस्तावेज की मौजूदगी अपने आप भारतीय नागरिकता सिद्ध नहीं करती। इसलिए नागरिकता निर्धारित करने की किसी भी व्यवस्था को मौजूदा कानूनों, तय प्रक्रियाओं और न्यायिक संरक्षण के अनुरूप ही काम करना होगा। केवल संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत धारणा के आधार पर किसी व्यक्ति से नागरिकता छीन लेना गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं। नागरिकता से जुड़े मामलों में सुनवाई, प्रमाण प्रस्तुत करने, अपील और स्वतंत्र समीक्षा की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एकीकृत डिजिटल पहचान व्यवस्था जितनी शक्तिशाली होगी, उसके साथ निजता और डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होगी। अलग-अलग विभागों का डेटा एक जगह जोड़ देना सुधार नहीं है। किस अधिकारी को कौन-सी सूचना देखने का अधिकार होगा, नागरिक की सहमति कब आवश्यक होगी, डेटा कितने समय तक रखा जाएगा और दुरुपयोग होने पर जवाबदेही किसकी होगी- इन सवालों के स्पष्ट उत्तर जरूरी हैं। साइबर सुरक्षा और स्वतंत्र निगरानी इस ढांचे के अनिवार्य अंग होने चाहिए। ऐसी व्यवस्था से रोजगार सृजन की संभावना भी हो सकती है, विशेषकर सत्यापन, नागरिक सहायता, डिजिटल अभिलेख प्रबंधन और क्षेत्रीय सेवा के क्षेत्र में यह संभव है। उसकी सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसने नागरिक की लागत, प्रतीक्षा समय, कार्यालयों के चक्कर और शिकायतों की संख्या कितनी घटाई।

आज जब डिजिटल शासन को पारदर्शिता और सुशासन का माध्यम बताया जा रहा है, तब नागरिक की पहचान से जुड़ी छोटी-सी त्रुटि भी उसके लिए बड़ी बाधा नहीं बननी चाहिए। एक अक्षर की गलती, गलत जन्मतिथि या पुराने पते को सुधारने के लिए महीनों की भाग-दौड़ उस डिजिटल व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है, जो नागरिक से तो त्वरित सेवा की अपेक्षा करती है, लेकिन स्वयं विभागों के बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित नहीं कर पाती। आखिरकार पहचान का उद्देश्य नागरिक को सुविधा, अधिकार और सुरक्षा देना है, उसे संदेह की स्थायी स्थिति में खड़ा करना नहीं। एक संवेदनशील राज्य वह होता है, जो सत्यापन की आवश्यकता और नागरिक के सम्मान के बीच संतुलन बनाए। यदि विभिन्न पहचान प्रणालियों को सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह ढांचे में जोड़ा जाए, तो नागरिकों को प्रमाणपत्रों के दुश्चक्र से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

कर्ज का संजाल

रानी प्रियंका वल्लरी

बीते कुछ दशकों की तुलना में आज के युवा अधिक प्रतिभा और क्षमता वाले हैं, जो हर वक्त सीखने और नई चीजों को तलाशने के लिए उत्सुक रहते हैं। हालांकि वे नई हर चीज को पा लेने की जल्दबाजी में दिखते हैं। देखा-देखी की लत इस जल्दबाजी को गति प्रदान कर रही है और इसी वजह से आज की युवा पीढ़ी बाजारवाद के जाल में फंसती चली जा रही है। ज्यादातर युवा सब कुछ पा लेने की ललक में मशगूल दिखते हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वे क्या खरीद रहे हैं, किसलिए खरीद रहे हैं। इस क्रम में कई बार अनावश्यक चीजें भी खरीद ली जाती हैं। ऐसी चीजें, जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती। फिर भी वह खरीदता है, क्योंकि उन्हें दुनिया की नजर में बड़ा दिखना होता है। यह बात दीगर है कि अपनी चाहतों को पूरा करने में वे कर्ज से अपनी पीठ टेढ़ी करता रहते हैं।

युवा पीढ़ी को इस स्थिति में लाने में बाजार से संजाल के बीच क्रेडिट कार्ड की बड़ी भूमिका है। इनका बाजार में अच्छा तालमेल है। दरअसल, आजकल क्रेडिट कार्ड से लेन-देन करना काफी आसान हो गया है। बहुत सारे लोग दो-चार ऐसे कार्ड रखना शान मानते हैं और मौके-बेमौके झट से उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इस तरह चुपके-चुपके उनके ऊपर उधार बढ़ता जाता है और वे कर्ज में डूबते जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में पांच करोड़ से ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी देश की कुल आबादी के करीब साढ़े पांच फीसद लोग अपने काम के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखें, तो कनाडा में लगभग तिरासी फीसद लोग कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वहीं अमेरिका जैसे देश में तकरीबन सड़सठ फीसद लोग कार्ड से खरीदारी करते हैं।

सही है कि क्रेडिट कार्ड समय की तेज रफ्तार के साथ होड़ में खड़ी कर देते हैं, लेकिन लोगों का दायरा सिकुड़ता चला जा रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए अंदर से बिखरता जा रहा है। किसी को किसी से मिलने के लिए वक्त नहीं है। अपने लक्ष्य को पूरा करने में लोग दिन-रात लगे रहते हैं। हर व्यक्ति सुबह से शाम और देर रात काम कर रहा है। ज्यादातर लोग काम को पूरा करने के लिए अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। इस क्रम में उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है और लंबे समय तक अकेले रहने पर कई लोग अवसाद में जा रहे हैं। अरस्तू ने कहा है- 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले देवता रहता है या दानव'। अकेलेपन से उपजा अवसाद अक्सर लोगों को द्रोही बना देता है। आज किसी से किसी को भावनात्मक लगाव महसूस होता नहीं दिखता है। लोग मतलब के आधार पर रिश्तों की पहचान कर रहे हैं और रिश्तों में औपचारिकता कर रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरे की कमी ढूंढ़ कर अपने को बेहतर साबित करने में लगा है। जबकि साथ रह कर कई जटिल समस्या पर चर्चा करके सुलझाया जा सकता है।

जीवन को सुंदर सुगम बनाया जा सकता है, लेकिन दूरी हमेशा दूरी ही पैदा करती है। लोग अकेले रहने के लिए आमादा हैं। यह भी सच है कि लोग अपने काम में इस प्रकार तल्लीन हैं कि किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं हैं। कोई देर रात घर लौटता है। सुबह अलसाए मन से दफ्तर के लिए चल देता है। घर में रहने और सुनने-समझने के लिए समय की तंगी है। हर काम को डिजिटल तरीके से संपादित किया जा रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, पर अपने बजट के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि कर्ज में डूबने से बचा जा सके। जीवन में संतुष्ट होने के लिए हमें अथाह भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रथम प्रयास जरूरत की वस्तुओं का प्रबंध करना ही होना चाहिए। अगर इसका उपयोग समझदारी से और समय पर न किया जाए, तो यह उच्च ब्याज दरों और खराब 'क्रेडिट स्कोर' का कारण बन जाता है। इस पर कई बार तीस फीसद से भी ज्यादा दर से ब्याज की भारी दर से वसूली की जाती है। चुकाने में नकारात्मक अंक होने से भविष्य में कर्ज मिलना कठिन हो सकता है।

सरल भाषा में कहें, तो क्रेडिट कार्ड एक व्यक्ति की वित्तीय योजनाओं के प्रबंधन का माध्यम हो सकता है। इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड किसी को आर्थिक स्वतंत्रता की तरह भी लग सकता है। बस इतना हो कि हम बड़ी खरीदारी कर समयानुसार उस कर्ज को चुका दें। कई क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले आकर्षक प्रस्ताव देते हैं और कैशबैक यानी नकद वापसी की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे आनलाइन खरीदारी करने पर कुछ छूट और विभिन्न रियायतें मिल सकती हैं। इसके लिए पहले अपना मासिक बजट तैयार करने की जरूरत होती है। अगर अपने बजट को सही से प्रबंधित नहीं किया जाए, तो वह खराब होगा ही। महीनों की तनख्वाह लाखों में क्यों न हो, पर मासिक बचत ही मूल कमाई है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रख कर किसी भी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है कि जिंदगी मासिक किस्त चुकाने में फिसलती जा रही है। आजकल ज्यादातर युवाओं की जीवनशैली में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, जो जीवन को निगलते जा रहे हैं, तो कुछ मासिक किस्तें। आज की हकीकत यही है। हर व्यक्ति कर्जदार हो रहा है। पहले जमाने में कर्जदार होना शर्म की बात थी, आज के वक्त में कर्जदार होना गर्व समझा जा रहा है।

दुनिया मेरे आगे

> **जीवन में संतुष्ट होने के लिए हमें अथाह भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं हैं। जरूरत भर वस्तुएं रहना ही ठीक है। हमारा प्रथम प्रयास जरूरत की चीजों का प्रबंध करना ही होना चाहिए। अगर इसका उपयोग समझदारी से और समय पर न किया जाए, तो यह उच्च ब्याज दरों और खराब 'क्रेडिट स्कोर' का कारण बन जाता है।**

जोखिम में कृषि

पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों के घुसने की आशंका को सरकार ने गंभीरता से लिया है। दो मत नहीं कि दूसरे देशों में अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें भारत की परिस्थितियों के अनुरूप लागू किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में आने वाले ये कीट कम समय में खेतों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। भारत पहले भी पाकिस्तान और ईरान की ओर से आने वाले टिड्डी दलों का सामना कर चुका है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में इनके प्रकोप ने किसानों की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में पाकिस्तान की दिशा से टिड्डियों के आने की आशंका को हल्के में लेकर नजरअंदाज करना उचित नहीं। सीमावर्ती इलाकों में निरंतर निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणाली, पर्याप्त दवाओं तथा प्रशिक्षित नियंत्रण दलों की तैनाती पहले से करनी होगी। ड्रोन आधारित निगरानी, सटीक छिड़काव और आधुनिक पूर्वानुमान तकनीक इस व्यवस्था को और प्रभावी बना सकते हैं। टिड्डी दल सीमा नहीं पहचानता, लेकिन उसके संभावित मार्ग को पहचान कर उससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

सबक की अनदेखी

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक इमारत के ढहने के बाद दिल्ली सरकार, पुलिस और नगर निगम सभी नींद से जागे जरूर लग रहे हैं, लेकिन अब तक जो प्रवृत्ति दिखी है, उसमें ऐसा लगता है कि जल्दी ही अगला हादसा होने तक सब सो जाएंगे। इसी साल जून में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 22 लोगों की मौत से अगर सबक लिया गया होता, तो शायद सत्य निकेतन में हादसा नहीं होता। उपहार सिनेमा अग्निकांड से लेकर तो लंबी सूची बन जाएगी। शायद ही कभी दीर्घकालिक हल पर विचार किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय और संबद्ध कालेजों में कुल सीटों की तुलना में छात्रावास की सीटें दस फीसद भी नहीं हैं। अनेक कालेजों में छात्रावास हैं ही नहीं। ऐसे में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को किराए पर कमरा लेकर रहना पड़ता है। दूसरी ओर, व्यवसाय के तौर पर बड़ी संख्या में पीजी चल रहे हैं।

– कमल कुमार जोशी, अल्मोड़ा

दावे की सच्चाई

बिहार के जमुई में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और मारपीट से बिहार में कानून व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कानून व्यवस्था पर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। दावे किए जाते हैं कि अपराधियों की शामत आई हुई है। मगर सच्चाई सामने है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराधी बैखौफ हैं। लगातार मुठभेड़ के बाद भी अपराध का ग्राफ कम नहीं होना यह दर्शाता है कि व्यवस्था अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम है। केवल बड़बोलेपन से अपराध नहीं रुकता है। देखने में आता है कि अपराधियों को राजनीतिक आधार पर श्रेणीबद्ध कर दिया गया है। अपने-पराए के आधार पर अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है। यही कारण है कि जिनको राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, उनके हौसले बुलंद हैं। जबकि इनका राजनीतिक संरक्षण किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर कहीं जघन्य अपराध करने वालों को महिमामंडित किया जाएगा, तो वहां अपराध बढ़ेंगे ही।

– हेमा हरि उपाध्याय 'अक्षत', उज्जैन

बुजुर्गों की फिक्र

जापान में सौ वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों की संख्या एक लाख पार कर गई है। दरअसल, वहां की खान-पान की आदतें, गतिशील जीवनशैली और सौहार्दपूर्ण सामाजिक परिवेश लोगों को स्वस्थ बनाता है। जबकि यह स्थिति हमारे देश में नहीं दिखाई देती। गलत खान-पान की आदतें, जंक फूड का सेवन, बेतरतीब जीवनशैली और मोटापा इत्यादि के कारण लोग मुश्किल से साठ-सत्तर साल ही जी पाते हैं। बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भरता, कम सामाजिक मेल-जोल और आर्थिक सुरक्षा का अभाव व्यक्ति को भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। बुजुर्ग खुद को अकेला महसूस करते हैं। जबकि सक्रिय जीवनशैली, उचित खान-पान, बेहतर सामाजिक परिवेश जरूरी है। भावनात्मक रूप से मजबूत और अकेले रह कर भी खुश रहना, बच्चों पर कम या न के बराबर निर्भरता और दूसरों से कम अपेक्षा स्वस्थ रहने के सूत्र हैं।

– अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

राजकाज
जनसत्ता | 26 सितंबर, 2026

वियतनाम के नेता ले डक थो को 1973 का नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के साथ देने का एलान किया गया था। डक थो ने पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया था क्योंकि उनके अनुसार वियतनाम में शांति स्थापित नहीं हुई थी। नोबेल की आधिकारिक वेबसाइट ने उन्हें एकमात्र ऐसे शांति पुरस्कार विजेता के रूप में दर्ज किया है जिन्होंने पुरस्कार लेने से इंकार कर दिया था। इस पुरस्कार को लेकर नोबेल समिति के भीतर भी तीखा विवाद हुआ था।

'शहर में एक कयामत थी कयामत न रही
हश्र खामोश हुआ फित्ना ए दौरां चुप है'

पिछले दिनों अरुंधति राय ने एक साक्षात्कार में कहा–मैंने कभी सोचा नहीं था कि व्यवस्था के विरोध में लिखने के पैसे मिलेंगे, पुरस्कार मिलेंगे। अरुंधति राय भारत ही नहीं दुनिया की व्यवस्था के खिलाफ लिखती हैं। लेकिन उनकी अनूदित रचना का उत्सव मनाने वाली हिंदी पट्टी ने उनकी इस हौसलाअफजाई पर कान नहीं धरा। कभी

बेबाक बोल

असहिष्णुता पर पुरस्कार वापसी करने वाले लोग ग्यारह साल बाद ऐसे मंच पर पुरस्कार लेने जाते हैं जहां लोकतांत्रिक आवाजों को कुचलने वाली शक्ति से जुड़े राजनेता मौजूद हों। कभी भीड़ की हिंसा की मुखालफत करने वाली हिंदी पट्टी के लोग पुरस्कारों के मामले में भीड़ की आवाज बन जाना चाहते हैं। ऐसे पुरस्कार की जयकार के खिलाफ बोलने वाले साहित्य के 'फूफा' करार दिए जा रहे हैं। पुरस्कार के हथियार को जब फिर हार की तरह पहना गया है तो अखलाक की आह याद दिलाता बेबाक बोल।

हथियार का हार

मुकेश भारद्वाज

'सब दलीलें तो मुझ को याद रहीं
बहस क्या थी उसी को भूल गया'

अगर साहित्य का इतिहास वर्तमान के साथ सतत संवाद करता तो इस स्तंभ का शीर्षक होता, 'आह अखलाक!' अखालक याद है आप लोगों को...वो दादरी, वो बाबरी...पुरस्कार वापसी...। वो बहस इस स्तंभ का भी मील का पत्थर बनी थी। वह सितंबर 2015 था...संयोग, ग्यारह साल बाद भी सितंबरी सितम ही हुआ। तारीख का संयोग तारीखी हो जाता है। 28 सितंबर 2015 की रात उत्तर प्रदेश के दादरी के एक गांव में 52 साल के मोहम्मद अखलाक की भीड़ ने हत्या कर दी। इस 'भीड़' शब्द को याद रखिएगा। उससे पहले एमएम कलबुर्गी की हत्या हो चुकी थी। मुखालफत में उदय प्रकाश, नयनतारा सहगल और मूर्धन्य कवि सहित कई संस्कृतिकर्मी इस मुहिम में शामिल हुए। पुरस्कार सार्वजनिक नैतिक प्रतिरोध का माध्यम बन गया। पुरस्कार वापसी की मुहिम ने पुरस्कारों व सत्ता की साख को थू-थू कर दिया था।

क्या आपको पता है कि दिल से 'आह अखलाक!' पहली बार कब निकला? जब भाजपा की अगुआई वाली सरकार ने बैंकों में 15 लाख आएंगे को जुमला कहा था तब? नहीं, नहीं नहीं...। पहले आगे बढ़ते हैं। साहित्य के मूर्धन्य मनुष्य ने कथित पुष्पगंधा जैसे किसी मंच से कहा कि लेखकों का स्वभाव ही सवाल पूछना है। कवि ने कहा था, 'इसका उद्देश्य किसी सुबह अचानक कोई नाटकीय कदम उठा लेना नहीं था, बल्कि परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोध दर्ज करना था।' सवाल है, जिस पुरस्कार को हथियार बनाया था, फिर उसी का हार पहन लिया तो 'हम भारत के लोग' क्या आह अखलाक! आह कलबुर्गी! कह सकते हैं?

हम तो इंसान हैं, भावनाओं में बह सकते हैं। इस मसले पर चैट जीपीटी से पूछा। कृत्रिम बुद्धि ने कहा, '2026 का निर्णय 2015 में स्थापित उनकी अपनी नैतिक सार्वजनिक छवि के साथ एक कठिन सवाल पैदा करता है।' यह पुरस्कार जब कृत्रिम बुद्धि के लिए इतना कठिन है तो फिर सोचिए मानवीय बुद्धि को यह कहना, 'अरे फूफा! नाराज क्यों हो रहे, स्वागत नहीं करोगे हमारा' कितनी बड़ी नाइंसाफी है।

फूफा जैसे कथित कमजर्फ रिश्ते की तो बहुत बात हो गई। अब जरा 'चचा' पर आएं। 'चचा' शब्द इसलिए कहा कि गालिब के साथ भी जुड़ता है, आजाद हिंद के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ भी जुड़ता है। 'अंकल सैम' पता है न! वही अमेरिका वाले ट्रंप। फूफा का मजाक उड़ाने वालों के सामने चचा ट्रंप को खड़ा कर देने का मन करता है। पुरस्कार पर सवाल उठाने वालों को हिंदी के विद्वानों ने कह डाला कि क्या 21 लाख का विरोध करने वाले नोबेल पुरस्कार का भी विरोध करेंगे। भाई

प्रतीकात्मक चित्र

साहब...इतिहास ने तुलनात्मक अध्ययन के कुछ नियम बताए हैं। अगर आप उस नियम को दरकिनार करना चाहते हैं तो बस एक उदाहरण। ज्यां पाल सार्त्र का नाम सुना होगा? सम्मान की चहुंओर मुनादी के बाद भी लेखक उस सम्मान को किन शब्दों में नकार सकता है? सार्त्र ने तो इसे लेखक की आजादी पर पड़ने वाला संस्थागत दबाव मान कर ठुकरा दिया।

हाजरीन-नाजरीन...फिर 2026 की सितंबर आ गई। मकबूल कवि की 95वीं जयंती पर उनके नाम पर स्थापित पुरस्कार समारोह में 21 लाख की नकद प्राप्ति के साथ कुछ ऐसा-वैसा कहा गया कि पुरस्कार के नाम वाले कवि की कविता अपने समय के साथ हमारे समय को भी दर्ज करती है। कविता को सत्य, स्मृति और भय के समय में निर्भीकता की जगह बनाने वाली शक्ति बताया गया।

इस पुरस्कार के स्रोत के पहले एक और घटना पर बात कर लेते हैं। एपस्टीन फाइल...नाम तो सुना होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अपने पैसे को 'गंदा' कहने पर जेफरी एपस्टीन ने भी क्रांतिकारी दलील दी थी। उसने अपने पैसे को 'गंदा' बताए जाने पर उन कथित गरीब देशों का रुख करने की सलाह दी थी, जहां उसके आरोपित धन से पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए थे। अब एक हृदयविदारक सवाल, अगर हिंदी पट्टी में हृदय नामक अंग बचा हो तो...। कोई इंसान बच्चों को पोलियो-मुक्त करने के लिए पैसे दे तो क्या उसे बच्चों का यौन शोषण करने की इजाजत मिल जानी चाहिए? अभी हिंदी पट्टी दुनियावी चिंताओं से जिस तरह से शोक-मुक्त महसूस कर रही है उसके हिसाब से तो होना चाहिए। अगर एपस्टीन ने कभी भारत आकर किसी हिंदी साहित्यिक मंच पर कुछ लोकलुभावन भाषण दे दिया होता तो दावा है कि इस ग्रह पर हिंदी पट्टी एकमात्र ऐसा क्षेत्र होती जहां एपस्टीन सम्मान समारोह को गर्व से स्वीकार किया जाता। इसकी मुखालफत करने वालों को 'फूफा' कहा जाता।

यह स्तंभ लिखते वक्त सत्ता प्रायोजित फूफा याद नहीं आ रहे हैं। याद आ रहे हैं 'चचा सैम'। अब इतना पता है न कि 'सैम' मतलब अमेरिका? तो अभी वाले चचा सैम के पहले वाले चचा यानी बराक ओबामा के सामने नोबेल पुरस्कार ने कैसे 'शांति' से समर्पण किया था? हिंदी साहित्य की कथित प्रतिरोधी धारा चाहे कितने भी नारे लगा ले, 'अमेरिकी साम्राज्यवाद हो बर्बाद' लेकिन पुरस्कार पर उनके आदर्श अमेरिका वाले चचा ही हैं। अब चचा को ऐसे नोबेल नहीं मिला तो क्या हुआ? वेनेजुएला की नेता ने चचा सैम को समर्पित कर दिया। पिछली बार ट्रंप के चुनाव हारने पर कहा गया था कि ट्रंप हार गए लेकिन 'ट्रंपवाद' जीतता रहेगा। बात सही थी। अब यह 'ट्रंपवाद' हिंदी साहित्य में भी दिख रहा है। फूफा तो बहाना है, इस देश में हिंदी पट्टी पर चचा की शक्ति को राज कराना है। अमेरिका पूरी दुनिया का मूल्य निर्देशक बना बैठा है। हिंदी साहित्य की दुनिया ने अघोषित रूप से कह ही दिया है, 'चचा ट्रंप तुम आवाज दो हम तुम्हारे साथ हैं। येन-केन-प्रकारेण पुरस्कार को उचित ठहराएंगे और उसे अपने नाम कराएंगे।'

स्तंभ की शुरुआत में अपील थी, भीड़ शब्द को याद रखने की। भीड़ कहीं भी जुटाई जा सकती है। पुरस्कार वापसी के लिए भी और 'मैं ही पुरस्कार हूं' वाली भावना को न्यायोचित ठहराने के लिए भी। हिंदी पट्टी में किसी भी तरह के निजी संबंध सिद्धांत से अहम होते हैं। फूफा को धकियाने वाले चचा के आगे वैसे ही शांति से समर्पण करते हैं जैसे नोबेल समिति ने बराक ओबामा के सामने किया था। आज पुरस्कृत पुरुष का समर्थक-समूह शोक में पड़े लोगों को 'अ' का आह्वान करते हुए 21वीं सदी में 21 लाख की अहमियत समझाने की पुरजोर कोशिश करेगा। कहेगा कि फलां कवि के पुरस्कृत होते ही कविता जिंदा लोगों में जोश लाएगी।

एक बात याद रखिए। हार की तरह धारण किया जानेवाला पुरस्कार कब सरकार पर प्रहार का हथियार बन जाए, इसकी बानगी आप पुरस्कार वापसी में देख चुके हैं। अब भी क्या गारंटी कि भविष्य में यही हार एक बार फिर हथियार वालों पर प्रहार का हथियार न बन जाए? हिंदी पट्टी वालों से अनुरोध है कि वे कितना भी अल्फ्रेड नोबेल याद दिलाएं आप अखलाक को याद रखिएगा। हथियार का हार पहनने वालों को याद रखिएगा। हथियार के पुरस्कार को याद रखिए और कहिए–

आह अखलाक!...कलबुर्गी!

राजपाट

माधव की चर्चा

भाजपा में राम माधव का राजनीतिक पुनर्वास कई बरस बाद हुआ है। वे पार्टी में महासचिव तो पहले ही रह चुके हैं। इस बार नितिन नवीन ने उन्हें अपनी टीम में उपाध्यक्ष बनाया है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के निवासी राम माधव आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। भाजपा में आरएसएस ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर 2014 में भेजा था। जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की साझा सरकार के गठन का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। माधव 62 वर्ष के हो चुके हैं। उन्होंने आज तक लोकसभा या राज्यसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा। भाजपा के ज्यादातर पदाधिकारी संसद के किसी न किसी सदन में रह चुके हैं। लेकिन राम माधव को मौका नहीं मिला। नितिन नवीन ने उन्हें तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभारी बनाया है। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है। संभव है कि पार्टी उन्हें इसी सूबे से अगले महीने राज्यसभा भेज दे पर उसमें पार्टी को बाहरी को तरजीह देने के आरोप का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है ज्यादा सीट वाले उत्तर प्रदेश से भी मौका मिल जाए। जहां उसके पास आठ लोगों को राज्यसभा भेजने का अवसर है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा में हैं। उन्हें अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की अटकलें सही होंगी तो फिर दूसरी बार उत्तर प्रदेश से पार्टी उन्हें राज्यसभा वैसे भी नहीं भेजेगी। जिससे राम माधव की राह आसान हो जाएगी।

पंजाब में कुछ तो गड़बड़ है...

चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं लेकिन पंजाब में कांग्रेस के अंदर चल रहा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस द्वारा देश भर में एक साथ प्रदर्शन करने के एलान के बाद भी पंजाब के नेता एक साथ नजर नहीं आए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब प्रभारी सचिन पायलट की ओर से सभी नेताओं को एक साथ होकर आगे आने की हिदायत दी गई थी ताकि चुनाव से पहले एकजुटता का प्रदर्शन सामने रखा जा सके। लेकिन पंजाब में हुए पार्टी के प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी व प्रताप सिंह बाजवा नजर नहीं आए। जहां राहुल गांधी राष्ट्रीय परिदृश्य में पुरजोर पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पंजाब के अंदर कुछ तो गड़बड़ है...होने के स्पष्ट संकेत हैं।

गठबंधन पर मंथन

पंजाब में चुनाव को लेकर भाजपा का गठबंधन अभी तक सवालों के घेरे में है। चर्चा चल रही है कि भाजपा और अकाली दल फिर साथ आ सकते हैं। खबरों की मानें तो अगले साल फरवरी में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव में दोनों गठबंधन करेंगे। आखिरी बार दोनों ने 2017 का विधानसभा और 2019 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। तब राज्य की 117 सीटों में से अकाली दल ने भाजपा को केवल 23 सीटें ही दी थीं। इस बार स्थिति उलट है। उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा के सहयोगी दल उस पर 2022 की तुलना में ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं वहीं पंजाब में भाजपा अकाली दल के साथ इस बार बराबरी का बंटवारा चाहती है। यानी बिहार की तर्ज पर। अब उसे लगता है कि पंजाब में जहां अकाली दल कमजोर हुआ है वहीं भाजपा की ताकत बढ़ी है। दलील दी जा रही है कि 2022 में जब दोनों अलग-अलग लड़े थे तो अकाली दल को 18 फीसद और भाजपा को 13 फीसद वोट मिले थे। लोकसभा के पिछले चुनाव में अकाली दल के साढ़े छह फीसद वोट के मुकाबले 18 फीसद वोट लेकर भाजपा ने उसे पछाड़ दिया था। इसी आधार पर भाजपा खुद 59 और अकाली दल के हिस्से में 58 सीटे देना चाहती है। पर चुनाव विधानसभा का है, इस नाते अकाली दल कुछ ज्यादा सीटें चाहता है। चुनावी रणनीति को समझने और बनाने में भाजपा के इतिहास को देख कर लगता है कि वह व्यावहारिक रुख चुनेगी।

सुक्खू बदलेंगे रीत!

हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की रीत चली आ रही है। एक बार भाजपा सरकार बनाती है तो अगली बार कांग्रेस। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री पद पर दावा तो वीरभद्र सिंह के परिवार का था पर मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह उर्फ सुक्खू। संकटों में घिरे रहने के बाद भी वे अपना अस्तित्व बचाने में सफल रहे हैं। पार्टी आलाकमान को उनसे उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन की रीत को वे बदल देंगे। राज्य में अगले साल नवंबर में गुजरात के साथ चुनाव होगा। सुक्खू को प्राकृतिक आपदा से लेकर विधायकों की बगावत और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है। फिर भी वे सरकार बचाए हुए हैं और सफलता से चला भी रहे हैं। सात राज्यों के बीच हाल में हुए किशाऊ बांध समझौते ने उन्हें सहारा दिया है। हिमाचल सबसे बड़ा लाभार्थी है। दूसरी तरफ सुक्खू वंचितों और दलितों पर फोकस कर परियोजनाएं चला रहे हैं।

प्रशांत की अगली परीक्षा

प्रशांत किशोर की बिहार में फिर परीक्षा होगी। उनकी जन सुराज पार्टी का बिहार के आम चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन पिछले दिनों बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत कर वे नायक बन गए। बांकीपुर एक तो भाजपा का अभेद्य किला था, दूसरे यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के त्यागपत्र से खाली हुई थी। भाजपा और पीके में मुकाबला भी सीधा नहीं था। राजद ने भी यहां अपना उम्मीदवार उतारा था। बहरहाल पीके की ऐतिहासिक जीत का शोर-शराबा अब थम चुका है। अब राज्य में विधान परिषद की आठ सीटों का चुनाव है। इनमें चार स्नातक श्रेणी की और चार शिक्षक श्रेणी की हैं। पीके ने आठों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। चुनाव इसलिए भी रोचक है क्योंकि पटना स्नातक सीट पर पीके के उम्मीदवार को जद (एकी) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने समर्थन दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के नीरज सिंह को पराजित करने का एलान कर दिया है। अगड़े, पिछड़े, मुसलमान और महिला सभी वर्गों के अपने समीकरण के बल पर पीके राजग और राजद को कितनी चुनौती दे पाएंगे, यह नतीजों से ही साफ होगा।

संकलन : मृणाल वल्लरी

आपके पत्र

धीमा जहर

अर्थशास्त्र के अध्याय में कर-शास्त्र के अनर्थ एवं उलझनपूर्ण तर्कों के समावेश से उत्पन्न स्थिति ने हम जैसे करोड़ों उपभोक्ताओं को ऊहापोह में डाल दिया है। कर्तव्य पथ पर कर के विविध कांटों के रोपण में माहिर इंद्रप्रस्थ के कलाकारों ने आम जनता को जिस तरह भरमाने में दक्षता हासिल की है, वह भारतीय कर विज्ञान का अद्भुत प्रयोग है। वित्त प्रधानी का युवा वर्ग से एकपक्षीय अपेक्षा की अंगड़ाई में वित्तीय आत्ममुग्धता के क्रूर आवरण से उपजे मौन प्रश्न दो जून के निवाले हेतु हताश युवा अपने भविष्य को उस द्वंद्व दरिया में डूबते दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्हें साहिल दृष्टिगत नहीं हो रहा है। विकास के आयाम का अंतरंग बने यूपीआइ की करुण मनोदशा यदि क्षरण सूचकांक की यात्रा का पथिक हो गया तो शीत निष्क्रियता में विश्रामित जेब और बटुए निश्चय ही त्योहारी मुद्रा में आ जाएंगे, भले भिक्षुक भाई करारोपण के मनोवैज्ञानिक भय से अपनी भूख को भूल जाएं। शुल्क पक्ष के बारहमासा की विभीषिका में करदाता गड्ढे से गुजरते हुए अब उस दलदल के दौर में दिख रहे हैं, जहां अर्थसागर के आकाश में उन्हें शुक्ल और कृष्ण पक्ष में समानता दिख रही है। मौजूदा अर्थ-विधान ने आम जनों को यह विवश कर दिया है कि वे धन की तीनों गति यथा उपभोग, दान एवं नाश के विकल्प के अपने नूतन संस्करण धन अर्जन, धन संचय और धन निकासी सह-व्यय में कर भुगतान की कृपा सिंधु में शीतल स्नान करते हुए राष्ट्रीय कर्तव्य का पुण्य प्राप्त करें।

-अशोक कुमार, पटना, बिहार।

कर-पथ

शायद मुल्क का कोई भी 'पथ' बगैर 'कर' लिए कुछ कदम चलने की इजाजत नहीं देता। यहीं से शुरू होता है हमारे कर के कर्तव्य पथ का बेइंतहां सफर। कर के चुभते रास्तों पर चलती अवाम की जिम्मेदारियों से निकले सवालों का जवाब तलाश रहा है। अदला-बदली से शुरू सफर-ए-जिंदगी ने सिखाया कि हर सौदे की एक कीमत है। बेशक जरूरतें, पसंद और हालत-ए-जेब से तय सौदे से शिकायत नहीं होती मगर खामोशी से जेब कुतरते करों से बचना मुमकिन नहीं है। बहस इस बात पर चल पड़ी कि दुनिया भर में डंका बजाता 'खैरात' अपने घर की किरकिरी कैसे बना? बात थोड़ी पुरानी मगर ताजा है, घर-घर मुफ्त चाय पिलाती उस वक्त की बड़ी कंपनियों ने चाय की प्याली इतनी गहरी कर दी कि यह तक याद न रहा कि पिछली चाय कितने की थी। हमारी जिंदगी बदल देने का खिताब हासिल मुफ्त की चाशनी में डूबा 'यूपीआइ' कोई तोहफा नहीं, मजबूरी थी। लिहाजा इसके इस्तेमाल पर लगने वाले 'जुर्माने' पर सवाल उठना लाजिम है। हम वाकिफ हैं उस फरेब से जिसने मुफ्त के शोर में जेब से निकाली हमारी गाढ़ी कमाई राशन थैले में भर कर 80 करोड़ लोगों में बांट दिए। यकीनन यूपीआइ के जबड़े में धकेलने से पहले सरकारी खजाने की सेहत परखी गई हुई होगी! अगरचे नहीं तो मुफ्त की आड़ में लगा जुर्माना किसी फरेब से कम नहीं। सवाल चंद रकम या जुर्माने का नहीं, उस नीयत का है जो हमारे भरोसे का कत्ल करती है।

-एमके मिश्रा, रांची, झारखंड।

शुल्क के दरवाजे

एक रिक्शाचालक मोबाइल पर भुगतान की सूचना सुनकर आगे बढ़ जाता है। सब्जीवाला बिना नकद लिए ग्राहक को सामान दे देता है। दूर गांव में बैठा मजदूर कुछ ही क्षणों में परिवार को पैसे भेज देता है। यह डिजिटल भारत का सबसे उपयोगी चेहरा है। यूपीआइ ने सचमुच छोटे दुकानदार, मजदूर और सामान्य नागरिक को ऐसी सुविधा दी है, जिसकी कुछ वर्ष पहले कल्पना भी कठिन थी। लेकिन जब इसी व्यवस्था से किसी नए शुल्क की चर्चा जुड़ती है, तो लोगों की चिंता स्वाभाविक है। आधुनिक बाजार का एक जाना-पहचाना तरीका है, पहले किसी सुविधा को मुफ्त या सस्ता बनाकर जनजीवन का हिस्सा बनाओ, फिर निर्भरता बढ़ने के बाद उसकी कीमत वसूलो। मोबाइल सिम, इंटरनेट, आनलाइन मनोरंजन, घर तक सामान पहुंचाने वाली सेवाएं और डिजिटल मंच इसी रास्ते से आगे बढ़े हैं। आरंभिक छूट धीरे-धीरे सदस्यता शुल्क, प्लेटफार्म शुल्क, सुविधा शुल्क और अन्य कटौतियों में बदल जाती है। ग्राहक जब तक इन सेवाओं का अभ्यस्त होता है, तब तक पुराने विकल्प कमजोर पड़ चुके होते हैं। डिजिटल भुगतान का मामला इससे अधिक संवेदनशील है, क्योंकि इसे केवल बाजार की सुविधा नहीं, बल्कि सरकारी नीति, पारदर्शिता और आर्थिक समानता के साधन के रूप में बढ़ावा दिया गया। डिजिटल व्यवस्था की सफलता केवल लेन-देन की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसने गरीब का जीवन कितना आसान और सस्ता बनाया। नागरिक को पहले सुविधा की आदत लगाकर बाद में उसी निर्भरता को राजस्व का साधन बना देना उचित नीति नहीं है। तकनीक तभी लोकतांत्रिक है, जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना नए आर्थिक बोझ के पहुंचे। वरना डिजिटल सुविधा धीरे-धीरे एक ऐसे दरवाजे में बदल जाएगी, जिसमें प्रवेश मुफ्त होगा, लेकिन बाहर निकलने का हर रास्ता शुल्क वाला।

-मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया।

विकास कहां है?

भारत कभी कृषि-प्रधान देश था। दुनिया भर में भारतीय कामगार जाने लगे। इस तरह भारत मजदूर-प्रधान देश बन गया। समय फिर बदला और अब भारत कर-प्रधान देश बन गया है। पहले आय पर कर, उस आय को जहां जमा किया, वहां कर; कुछ खरीदा या बेचा, तो कर; उपयोग किया, तो कर। जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली, सड़क, यात्रा इत्यादि पर कर। निवेश पर कर, विनिवेश पर कर। एक भिखारी भी करदाता है। खैर, सरकार का तर्क है कि देश के विकास के लिए ये कर आवश्यक हैं। ठीक है, मान लिया मगर विकास कहां है? शहरों से लेकर गांवों तक बुनियादी ढांचे की कमी है और जो कुछ है, उसके रख-रखाव का अभाव है। लचर शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, कुपोषण, गरीबी और बेरोजगारी। विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह कर के पैसों से नहीं, बल्कि 'पीपीपी माडल' पर हो रहा है, जिसके उपयोग के लिए जनता को तमाम कर देने के बाद भी पैसे देने पड़ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को कार के उदाहरण से समझिए। पहले आमदनी पर कर, फिर कार खरीदने पर कर, फिर सड़क कर, फिर ईंधन पर कर एवं सेस, और सड़क पर चलें तो टोल।

-बृजेश माथुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

विशेष पन्ना कैसा लगा

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं। हमारी ई-मेल आइडी है :
vishesh.jansatta@expressindia.com

चिंतन

दुनिया को दिखा आतंक पर पाक का दोहरा रवैया

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो गया है। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पत्रकारों ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और आतंकवादियों को पनाह देने को लेकर सीधे सवाल किए। पूछा गया कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेगा और हाफिज सईद पर कार्रवाई कब होगी। शहबाज दोनों सवालों पर खामोश रहे और आगे बढ़ गए। सवाल भले पत्रकारों ने पूछे हों, लेकिन यह सवाल अब पाकिस्तान की आतंकवाद नीति पर अंतरराष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान की विडंबना यही है कि वह एक ओर स्वयं को आतंकवाद का पीड़ित बताता है और दूसरी ओर उसकी जमीन से संचालित या उससे जुड़े आतंकी संगठनों को लेकर भारत और अन्य देशों के गंभीर आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। हाफिज सईद इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में उसका नाम दर्ज है और उसे लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ा गया है। मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में उसकी भूमिका को लेकर भारत लंबे समय से पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग करता रहा है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच से जुड़ी पूरक चार्जशीट में भी सईद को आरोपी बनाया है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उसके बारे में सवाल पूछा जाना अस्वाभाविक नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई का दावा कर चुके हैं। आतंकवाद का शिकार होने का दावा पाकिस्तान को अपनी जमीन से दूसरे देशों के खिलाफ होने वाली आतंकी गतिविधियों से जुड़े सवालों से मुक्त नहीं कर सकता। आतंकवाद के खिलाफ किसी देश की प्रतिबद्धता का आकलन उसके बयानों से नहीं, उसके ठोस और निरंतर कदमों से होता है। यही विरोधाभास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी दिखाई दिया। पाकिस्तान ने भारत में कश्मीर और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए। भारत ने पलटकर पाकिस्तान के आतंकवाद के इतिहास और उसके सामाजिक प्रभाव का मुद्दा उठाया। इससे यह स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर केवल आरोप लगाने से किसी देश की छवि नहीं बदलती। जब कोई देश दूसरों के मानवाधिकारों पर सवाल उठाता है तो दुनिया स्वाभाविक रूप से उसके अपने रिकॉर्ड को भी देखती है। पाकिस्तान की विदेश नीति लंबे समय से कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दों को एक-दूसरे से जोड़कर प्रस्तुत करने की कोशिश करती रही है। आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने आतंकवाद को लेकर सवाल पहले से अधिक स्पष्ट हैं। आतंकी संगठन किसी एक देश की समस्या नहीं है। उनकी गतिविधियां सीमाओं से बाहर तक असर डालती हैं। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी चयनात्मक नहीं हो सकती। भारत के लिए यह स्थिति इस बात का संकेत भी है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में आतंकवाद का मुद्दा केंद्रीय बना रहेगा। संवाद, पड़ोसी संबंध और क्षेत्रीय शांति अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आतंकवाद को नजरअंदाज करके स्थायी शांति की कल्पना संभव नहीं है। यूएन में शहबाज से पूछे गए सवाल अपनी जगह कायम है। दुनिया अब पाकिस्तान के भाषणों से अधिक उसकी कार्रवाई देखना चाहती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दावा और आतंक से जुड़े सवालों पर खामोशी, यही वह विरोधाभास है जिसने पाकिस्तान के दोहरे रवैये को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है।

मुद्दा
मनोज कुमार अग्रवाल

आईआईटी : आत्महत्याओं की वजह तलाशें

आईआईटी संस्थानों में लगातार बढ़ती आत्महत्याओं और हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या की घटना ने देश भर में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। देश के 23 आईआईटी सहित 31 केंद्रीय संस्थानों के पास छात्रों के तनाव को समय रहते पहचानने (सक्रिय स्क्रीनिंग) की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक समाज ठोस प्रमाणों और तथ्यों पर विश्वास करता है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आरोपित को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। निराशा और हताशा में आईआईटी के निदेशक अथवा प्राध्यापकों पर जातिवाद का आरोप लगाना समाज और संस्थान में विद्वेष और घृणा की विषबेल रोपने जैसा है, इससे बचना चाहिए।

आईआईटी संस्थानों में लगातार बढ़ती आत्महत्याओं और हाल ही में आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या की घटना ने देश भर में गंभीर चिंता पैदा कर दी है। बता दें कि 18 सितंबर 2026 को आईआईटी बॉम्बे में 22 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे का उनके हॉस्टल के कमरे में शव मिला। परीक्षा के दौरान एक प्रोफेसर द्वारा कथित तौर पर मोबाइल का उपयोग नकल करने के लिए टोके जाने और कॉपी ले लिए जाने के बाद यह घटना सामने आई, जिसके बाद छात्रों ने भारी प्रदर्शन किया। परिवार ने जातिसूचक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने एससी/ एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। परिवार का दावा था कि उनके पुत्र को लंबे समय से जातिगत भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने प्राध्यापक सूर्यनारायण दूल्ला सहित कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की। न्यायालय के फैसले से पहले किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है।

सवाल है कि देश के आईआईटी संस्थानों में तेरह हजार से अधिक होनहार पढ़ रहे हैं। जातीय आधार पर किसी एक छात्र से ही दुर्व्यवहार कैसे संभव है? एक न्यूज चैनल रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच विभिन्न आईआईटी परिसरों में लगभग 171 छात्रों की असमय/आत्महत्या से मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से लगभग 70 प्रतिशत मामले पिछले एक दशक में सामने आए हैं। इनमें बड़ी तादाद में सवर्ण छात्र भी शामिल हैं, इसलिए भी जातिगत भेदभाव के आरोप सही नहीं हैं। आरटीआई और अन्य आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2006 से सितंबर 2026 के बीच आईआईटी परिसरों में 140 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है। जबकि पिछले पांच सालों में देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में 70 होनहारों ने आत्महत्या की। गंभीर चिंता यह भी कि जुलाई से शुरू हुए सत्र में अब तक आईआईटी के तीन और आईआईएम का एक छात्र आत्महत्या कर चुका है। वहीं आईआईएससी बंगलूरु में भी पंद्रह दिन में दो छात्रों ने आत्मघात किया है। विडंबना यह है कि इन आंकड़ों में देश के अन्य शिक्षण संस्थानों के आत्मघात के मामले शामिल नहीं किए जाते हैं, जिससे देश में आत्महत्या करने वाले छात्रों की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ पाती। यह अकल्पनीय है कि जिन इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला लेना छात्रों का सपना होता है, वहां पहुंचकर कोई छात्र आत्महत्या क्यों कर लेता है? विचारणीय प्रश्न है कि आखिर ये छात्र आत्मघाती कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या वे इंजीनियरिंग आदि के पाठ्यक्रम के साथ साम्य नहीं बैठा पाते? क्या सिस्टम की खामियां उन्हें हताश करती हैं? क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के छात्र अंग्रेजी के पाठ्यक्रम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं? अक्सर चर्चा होती है कि उच्च इंजीनियरिंग संस्थानों में देश के चर्चित व महंगे अंग्रेजी स्कूलों से आए छात्रों द्वारा भाषा,जाति, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा आर्थिक स्तर पर अन्य छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। आरोप है कि अंग्रेजी माध्यम से आये छात्र हिंदी व क्षेत्रीय भाषाओं से पढ़ाई करके आए छात्रों को हेय दृष्टि

से देखते हैं। आरोप तो यहां तक हैं कि कुछ शिक्षक भी ऐसे छात्रों के प्रति दुराग्रह रखते हैं। कमोबेश ऐसी चिंताएं ग्रामीण पृष्ठभूमि व वंचित समाज से आए छात्रों को लेकर भी सामने आती हैं। नये छात्रों को परिसर तथा छात्रावासों में भेदभाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। फलतः इन छात्रों का आत्मविश्वास डिगता है। कालांतर वे अपनी कक्षाओं की पढ़ाई के साथ साम्य नहीं बना पाते व हताशा में आत्मघात की राह चुनते हैं। इंजीनियरिंग व प्रबंधन से जुड़े देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घातक प्रवृत्ति के मद्देनजर सरकार ने मामले की पड़ताल के लिए पिछली जनवरी में तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। इस समिति ने भी स्वीकार किया था कि व्यवस्था में कुछ खामियां जरूर हैं, जिसके चलते छात्र आत्मघात के लिए बाध्य होते हैं। दरअसल, कुछ छात्र शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक आकांक्षाओं के बोझ के साथ अध्ययन कर रहे होते हैं। इससे उनके मन में यह भय पैदा हो जाता है कि क्या वे अपने जीवन के लक्ष्य हासिल भी कर पाएंगे? बड़ी संख्या में मध्यमवर्गीय, गरीब परिवारों व वंचित समाज की प्रतिभाएं खून-पसीना एक करके इन संस्थानों में दाखिला लेती हैं। उन पर मानसिक दबाव होता है कि परिवार ने पेट काटकर और कर्ज आदि लेकर उन्हें महंगे इंजीनियरिंग व प्रबंधन संस्थानों में दाखिला दिलाया है।

यदि वे असफल हुए तो परिवार को क्या मुंह दिखाएंगे? दूसरा, हमारे समाज में इंजीनियर, प्रबंधक व डॉक्टर बनने की भेड़चाल चल रही होती है। ईश्वर हर बच्चे की रचना उसके विशिष्ट गुण के साथ करता है। जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग में दाखिला लेने वाले हर छात्र की रुचि इंजीनियरिंग में ही हो। कोई छात्र मानविकीय संकाय की प्रतिभा हो सकता है। इंजीनियरिंग, उसकी रुचि व मन का विषय नहीं हो सकता, जिसके चलते वो पूरे मनोयोग से इस पाठ्यक्रम से साम्य नहीं बैठा पाता। आज सोशल मीडिया की विकृतियां तमाम छात्रों की एकाग्रता को बाधित कर रही हैं। नये वातावरण से साम्य न बैठा पाने व अन्य कारणों से छात्र मानसिक तनाव में आ जाते हैं। विडंबना यह है कि अधिकांश संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ नहीं हैं। निश्चित ही देश की इन प्रतिभाओं को असमय काल-कवलित होने से बचाने की सख्त जरूरत है। आंकड़ों के अनुसार, आत्महत्या के लगभग 61% मामलों के पीछे मुख्य वजह अकादमिक तनाव है। संस्थानों में ग्रेड, रैंक और सीजीपीए को ही सफलता का एकमात्र पैमाना मान लिया जाता है, जिससे छात्र खुद को एक अंतहीन दौड़ में फंसा हुआ पाते हैं। लगभग 12% मामले जॉब की अनिश्चितता और प्लेसमेंट के भारी मानसिक तनाव से जुड़े होते हैं। हालिया आईआईटी बॉम्बे की घटना और पूर्व के मामलों में भी कैंपस के भीतर एससी , एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ कथित भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार, कुल आत्महत्या के मामलों में 55% से अधिक छात्र इन्हीं आरक्षित वर्गों से आते हैं। देश के 65% उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं की भारी कमी है। देश के 23 आईआईटी सहित 31 केंद्रीय संस्थानों के पास छात्रों के तनाव को समय रहते पहचानने (सक्रिय स्क्रीनिंग) की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक समाज ठोस प्रमाणों और तथ्यों पर विश्वास करता है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आरोपित को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। निराशा और हताशा में आईआईटी के निदेशक अथवा प्राध्यापकों पर जातिवाद का आरोप लगाना समाज और संस्थान में विद्वेष और घृणा की विषबेल रोपने जैसा है, इससे बचना चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

कृषि
रवि शंकर

मानसून की बेरुखी से फसलों पर संकट

अल नीनो के प्रभाव के कारण देश में इस वर्ष मानसून सत्रह साल में सबसे सूखा रहा है, जिसमें कुल वर्षा सामान्य से 15 फीसदी कम दर्ज की गई है। खास बात यह है कि अब तक 14 राज्यों में बारिश की कमी 20 फीसदी से ज्यादा रही है। इनमें बिहार, पंजाब, हरियाणा के अलावा दक्षिण भारत के सभी पांच प्रायद्वीपीय राज्य शामिल हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, वर्ष 2009 के बाद (जब 18.3 फीसदी की कमी देखी गई थी) यह देश का सबसे कमजोर मानसून सीजन साबित हुआ है। एक जून से 21 सितंबर 2026 तक की अवधि में जहां देश में सामान्य रूप से 827.2 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, वहीं वास्तविक आंकड़ा केवल 703.7 मिलीमीटर पर सिमट कर रह गया है। 123.5 मिलीमीटर की इस भारी गिरावट ने न केवल चालू खरीफ फसलों के उत्पादन पर संकट खड़ा कर दिया है, बल्कि आगामी रबी सीजन की बुआई और देश के प्रमुख जलाशयों के जलस्तर को भी गंभीर खतरे में डाल दिया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस वर्ष मानसून के ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहने की मुख्य वजह प्रशांत महासागर में तेजी से सक्रिय हुआ 'सुपर अल नीनो' प्रभाव है।

अल नीनो की स्थिति के कारण समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया, जिसने वैश्विक पवन प्रणालियों को बाधित किया और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ने वाली मानसूनी हवाओं को कमजोर कर दिया। इस सीजन में बारिश का वितरण न केवल कम रहा, बल्कि समय और स्थान के लिहाज से भी बेहद असंतुलित था। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। देश के करोड़ों किसान जून से सितंबर के बीच होने वाली इस वर्षा के आधार पर ही अपनी फसलों की योजना बनाते हैं। इस साल बारिश के बेरुखेपन के कारण खरीफ फसलों विशेषकर धान, गन्ना, मक्का और कपास की बुआई पिछले सीजन की तुलना में 3.73 फीसदी पिछड़ गई है। इस सूखे मानसून के चलते अकेले चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन (1 करोड़ टन) तक की भारी कटौती हो सकती है। धान के खेतों में पर्याप्त पानी न होने के कारण पौधों का विकास रुक गया है, जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार घटने की पूरी आशंका है। इसके अलावा गन्ने की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे आने वाले महीनों में चीनी उत्पादन प्रभावित होना तय माना जा रहा है। साथ ही, यह रबी की फसलों (गेहूं, सरसों, चना) के लिए भी बेहद खतरनाक साबित होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मानसून भारतीय खेती की लाइफलाइन है। चिंता केवल खरीफ की मौजूदा फसलों तक सीमित नहीं है। देश के केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख 150 से अधिक जलाशयों में लाइव स्टोरेज (उपयोगी जल भंडारण) पिछले साल की तुलना में लगभग 36 फीसदी कम हो गया है। दक्षिण भारत के 54 प्रमुख बांधों में जलस्तर उनकी कुल क्षमता के 80 फीसदी से भी नीचे चला गया है। कम बारिश का सीधा असर अब देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर दिखने लगा है। अगस्त के महीने में खाद्य मुद्रास्फीति (फूड इन्फ्लेशन) लगातार सातवें महीने बढ़कर 5.95 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई, जो इस वर्ष का उच्चतम स्तर है। आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक, मानसून में होने वाली हर एक फीसदी की कमी खाद्य महंगाई को करीब 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा देती है। बाजार में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आपातकालीन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं, प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों की आसमान छूती कीमतों को रोकने के लिए कई राज्यों में रियायती दरों पर सरकारी आउटलेट्स के जरिए बिक्री की जा रही है। मानसून 2026 के इन निराशाजनक आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो जैसी मौसमी परिघटनाएं अब भारतीय कृषि के लिए एक स्थायी चुनौती बन चुकी हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर के अंत में बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर हो चुके 15 फीसदी के बड़े घाटे को पाटने में सक्षम नहीं होगा। सरकार को प्रभावित राज्यों में सूखा राहत पैकेज, किसानों के लिए फसल बीमा के त्वरित भुगतान और ग्रामीण रोजगार योजनाओं (मनरेगा) को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। आने वाले समय में जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन) और कम पानी में उगने वाली जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना ही भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र विकल्प होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है?

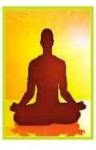

संकलित
दर्शन

जीवन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न जितने सरल लगते हैं, उतने ही रहस्यमय भी हैं। इन्हें जितना समझने की कोशिश करते हैं, वे उतने ही उलझते जाते हैं। दरअसल, जानना हृदय का विषय नहीं है, जीना हृदय का विषय है। रहस्य समझने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। जीवन के रहस्य को जीना ही आनंद है। ज्ञान प्राप्त होने से पहले लगता है कि हममें अज्ञान नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता है, तो लगता है हममें काफी अज्ञान है। एक कहावत है, आत्मज्ञान होने से पहले लकड़ी काटो और पानी भर कर लाओ। आत्मज्ञान के बाद भी, लकड़ी काटो और पानी भर कर लाओ। अंतर इतना है कि पहले हम दुखी रहकर काम करते थे। लेकिन आत्मज्ञान के बाद वही कार्य आनंद से करते हैं। हमारा जीवन कितना उत्तम है, यह हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। हम वही सुनना पसंद करते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है। जब हमारा जीवन प्रेम में केंद्रित होता है, तो हम प्रेम के बारे में जानना चाहते हैं। जब जीवन बच्चों के इर्द-गिर्द घूमता है, तो हम बच्चों के बारे में ही सुनना चाहते हैं। जो हमारी इच्छा हो, हमें वही सुनना पसंद है और हमारी इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता।

समर्पित भक्त का वास वैकुन्ठ में

संकलित
प्रेरणा

एक ब्राह्मण था तथा महान भक्त था, वह मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है वह एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था और उसने सुना कि नारायण मन में भी पूजे जा सकते हैं। उसने इस अवसर का लाभ उठाया क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से नारायण की पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था। जब वह यह समझ गया, कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अपने मन के भीतर वह बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था, गहनों के साथ लदी और सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखते हुए, वह भगवान का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी के जल के साथ अभिषेक कर रहा था। फिर बहुत ही उत्तम तरह से भगवान का श्रृंगार कर और फूल, माला के साथ पूजा करते हुए, वह मीठे चावल बहुत अच्छी तरह से भोजन के रूप में पका रहा था। वह परखना चाहता था कि भोजन भोग के लिए कहीं गरम तो नहीं हैं। तो ऐसा जानने के लिए उसने भोजन में अपनी उंगली डाली तो उसकी उँगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुइ देखी। तो वह चकित रह गया। इस तरह, वैकुन्ठ से नारायण, मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मीजी ने पूछाः आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं ? भगवान बोलेः मेरा एक भक्त अतिप्रभावी मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भक्त सब उच्च साधनो एवं सामग्रियों से मेरी अर्चना करते हैं, परन्तु उनका मन भटकता ही रहता है। इस समर्पित भक्त का वास वैकुन्ठ में होना चाहिए अतः मेरे दूतों को तुरंत उसे वैकुन्ठ लाने के लिए भेजो।

अंतर्मन

आज की पाती

दलबदल निरोधक कानून की प्रासंगिकता पर उठते सवाल

52वें संविधान संशोधन, 1985 के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आया राम-गया राम की राजनीति पर अंकुश लगाना तथा राजनीतिक अस्थिरता और बार-बार होने वाले दल परिवर्तन को नियंत्रित करना था। लेकिन इतने वर्षों बाद भी यह प्रश्न कायम है कि इस संविधान संशोधन से राजनीति में दलबदल की प्रवृत्ति पर कितना प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो पाया है। इस कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि के दलबदल पर अयोग्यता का निर्णय सदन के अध्यक्ष के अधीन रखा गया है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के निष्पक्ष और समयबद्ध निर्णय लें, ताकि लोकतांत्रिक जवाबदेही और संसदीय मर्यादा मजबूत हो। - विकास उपाध्याय, धमतरी

ट्रेंड

घरेलू उद्योग

सपा-बीएसपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अपराध का धंधा खूब फला-फूला; गाड़ियों की चोरी एक घरेलू उद्योग बन गई थी। आज उसी जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर, गाड़ी बनाने की यूनिट्स और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

हार्दिक बधाई

मैं एशियाई खेल-2026 में देश के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर झज्जर की सुरुचि और रेवाड़ी के कमलजीत को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई देता हूं।
- नायब सैनी, सीएम, हरियाणा

वोटर लिस्ट का एक्सेस

दिल्ली में बैठे कुछ लोगों के पास पूरे देश की वोटर लिस्ट का एक्सेस है। वे जिसे चाहे, उसका वोट जोड़ सकते है या उसका वोट हटा सकते हैं। हमारी मांग है कि पिछले 3 सालों में वोटर लिस्ट में किए गए सभी बदलावों को रद्द किया जाए और 3 साल पुरानी वोटर लिस्ट को बहाल किया जाए।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

एसआईआर प्रक्रिया

एसआईआर में अनियमितताएं सामने आने और निर्वाचन आयुक्तों के भी इनके बारे में बोलने के बाद केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने की जरूरत है।
- राज ठाकरे, अध्यक्ष, मनसे

करंट अफेयर

एजीयू के पुरस्कार विजेताओं में भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल

भारतीय वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल्ल और नीलिमा सत्यम को अनुसंधान, शिक्षा और उन्नत मृदा एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व के लिए अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (एजीयू) के वर्ष 2026 के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (युवा) से सम्मानित जलवायु वैज्ञानिक कोल्ल पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में कार्यरत हैं। उन्हें एजीयू के 'पावेल एस. मोलचानोव क्लाइमेट कम्युनिकेशंस प्राइज' के लिए चुना गया है। कोल्ल को हिंद महासागर के बढ़ते तापमान, मानसून में हो रहे बदलाव, समुद्री की गर्म होती सतह, चक्रवात और अत्यधिक बारिश के साथ-साथ दक्षिण एशिया में लोगों और उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों के दस्तावेजीकरण के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि, नाम अंकित पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष जलवायु विज्ञान, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों पर प्रभावी वैज्ञानिक संचार के लिए किसी वैज्ञानिक को दिया जाता है।

AGU
ADVANCING EARTH AND SPACE SCIENCES

ऑफ बीट

ओरंगुटान की आवाज में छिपा भाषा का रहस्य

सुमात्रा ओरंगुटान का वैज्ञानिक नाम 'पोंगो अबेली' है जो एक वानर की प्रजाति है और सुमात्रा द्वीप में पाई जाती है। ओरंगुटान हमारे पशु परिवार से संबंधित हैं। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज एक ही हैं और यह एक ऐसी प्रजाति है जो लाखों साल पहले रहती थी, जिससे हम दोनों विकसित हुए हैं। हमारी तरह, ओरंगुटान के भी हाथ होते हैं जो पकड़ सकते हैं, वे औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं और नयी चीजें सीख सकते हैं। हम अपने डीएनए का लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा ओरंगुटान के साथ साझा करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारे शरीर और दिमाग के कई हिस्से एक जैसे तरीके से काम करते हैं।

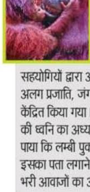

वर्ष 2024 में मनोवैज्ञानिक एड्रियानो लामीरा और उनके सहयोगियों द्वारा ओरंगुटान संचार पर किए गए शोध में ओरंगुटान की एक अलग प्रजाति, जंगली बोर्नियन ओरंगुटान (पोंगो पाइग्मियस वुर्मबी) पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने केवल नरों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली एक प्रकार की ध्वनि का अध्ययन किया, जिसे लम्बी पुकार के नाम से जाना जाता है, और पाया कि लम्बी पुकारें लयबद्ध पदानुक्रम के दो स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। इसका पता लगाने के लिए हमने जंगली मादा सुमात्रा ओरंगुटान की चेतावनी भरी आवाजों का अध्ययन किया और कुछ आश्चर्यजनक बातें पाईं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

📍EnglishEditorialsPDF with International Newspapers Editorials [35-40pages]

📍 Hindi Editorials PDF

📍 Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International [Genaral & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world. Asian, Europian & American

Hindi Newspapers

1) दैनिक जागरण
2) जनसत्ता
3) हरिभूमि
4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express
2. The Hindu
3. Business Line
4. Financial Express
5. Times of India
6. Hindustan Times
7. Economic Times
8. Live Mint
9. Business Standard

Click Here